नई दिल्ली
रविवार 28 जून 2026
ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी वर्ष : 30, अंक : 70
पृष्ठ 12 मूल्य 2.00

मौसम
अधि. 41
न्यूनू. 32

हरिभूमि

दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

पीएम मोदी 'जोनाथन' को पत्ती खिलाते हुए

दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय जीव

194 साल के कछुए 'जोनाथन' को प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाई पत्ती

पीएम ने बॉटनिकल गार्डन में एक पेड़ भी लगाया

एजेंसी ▸▸ सेशेल्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन दिवसीय सेशेल्स यात्रा के दौरान कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, लेकिन इनमें सबसे खास मुलाकात दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव 'जोनाथन' से हुई। करीब 194 साल का यह विशाल अल्डाब्रा जाइंट कछुआ अपने लंबे जीवन की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। इसका जन्म 1832 के आसपास हुआ था। उम्र अधिक होने के कारण ▸▸ शेष पेज 5 पर

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक, चंपत व मिश्रा के इस्तीफों पर होगा फैसला

राम मंदिर में हो सकती है तिरुपति बालाजी टैंपल की तर्ज पर अब सीईओ की नियुक्ति

- ट्रस्ट का दावा- भक्तों द्वारा दान में दी गई चांदी और आभूषण सुरक्षित
- नृपेंद्र मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया जा सकता है

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्ददेव गिरि ने कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का त्यागपत्र प्राप्त हुआ है।

चंपत राय

नृपेंद्र मिश्रा

न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। ट्रस्ट ने बताया कि भक्तों द्वारा दान में दी गई चांदी और आभूषण

फाइल फोटो

सुरक्षित हैं। 11 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, इसमें राम मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव तय होता सकता है। अनिल मिश्रा की जगह पर कोई अन्य सदस्य लाया जा सकता है। बैठक में राम मंदिर परिसर में ▸▸ शेष पेज 5 पर

ट्रस्ट के सदस्य बोले

दोषियों को बख्शा न जाए

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा गंभीर अपराध नहीं होना चाहिए था। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो दोषियों को कानून के मुताबिक उचित सजा मिलनी चाहिए। उडुपी के अष्ट (आठ) मठों में से एक पेजावर अधोक्षज मठ के प्रमुख स्वामी ने ▸▸ शेष पेज 5 पर

खास बातें

- कोषाध्यक्ष स्वामी गोविन्ददेव गिरि ने राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय के इस्तीफे की पुष्टि की।
- ट्रस्ट ने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा।
- ट्रस्ट ने बताया कि भक्तों द्वारा दान में दी गई चांदी और आभूषण सुरक्षित हैं।
- 11 जुलाई को होगी ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, इसमें राम मंदिर ट्रस्ट का नया महासचिव तय होता सकता है।
- डॉक्टर अनिल मिश्रा की जगह पर कोई अन्य सदस्य लाया जा सकता है।
- बैठक में राम मंदिर परिसर में सीईओ की भी नियुक्ति हो सकती है।

inh 24x7
छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल देखें
TATA PLAY चैनल नं. 1155
airtel चैनल नं. 366

खबर संक्षेप

यूपीएससी की सीधी भर्ती के लिए आवेदन 17 तक

नई दिल्ली। यूपीएससी ने भारत सरकार के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से

ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। विज्ञापन में पात्रता, आवेदन प्रक्रिया के निर्देश उपलब्ध हैं।

पूर्व डीआईजी की अटैच की 53 करोड़ की प्रॉपर्टी

गुवाहाटी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत सेवानिवृत्त

पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार दत्ता, आईपीएस तथा उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी समूह कंपनियों की लगभग 53.28 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

मान को लेकर अकाल तख्त का फैसला सही

अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विवादास्पद वीडियो पर पंजाब के सीएम भगवंत

मान को गुरु विरोधी और 'खालसा पंथ विरोधी' घोषित करने की अकाल तख्त साहिब की घोषणा का समर्थन किया। बैठक में निष्कर्ष निकाला कि मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मान को सीएम पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने गुजरात में लॉन्च की 'भारत टैक्सी सर्विस'

देश के पहले राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म में ड्राइवरों के पास होगा सीधे तौर पर 'मालिकाना हक'

ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा

एजेंसी ▸▸ गांधीनगर

निजी कैब कंपनियों की मनमानी और कैंसिलेशन की समस्याओं के सामधान के लिए केंद्र सरकार ने समाधान निकाला है। अब इस समस्या का एक नया और ठोस समाधान 'को-ऑपरेटिव मॉडल' (सहकारी ढांचे) के जरिए सामने आया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात में भारत टैक्सी सर्विस को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला ऐसा राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मालिकाना हक सीधे तौर पर इसे चलाने वाले ड्राइवरों के पास होगा। भारतीय मोबिलिटी सेक्टर में इस पहल को ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। शाह ने कहा कि इससे कई समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, साथ ही नागरिकों को कई फायदे भी मिलेंगे। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ ही कई जन प्रतिनिधि शामिल रहे।

गुजरात राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया

निजी कैब कंपनियों की मनमानी कैंसिलेशन होगी खत्म

'को-ऑपरेटिव मॉडल' से लोगों को दिया जा रहा लाभ

भारत सेवा टैक्सी लॉन्चिंग के कार्यक्रम में गृहमंत्री शाह और सीएम पटेल व अन्य

अगले एक माह में पूरे गुजरात में चलेंगी

लॉन्चिंग के पहले चरण में इस सेवा को गुजरात राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू किया गया है। सरकार और सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य बेहद आक्रामक है। उन्होंने अगले एक महीने के भीतर इस सर्विस के ऑपरेशंस का विस्तार पूरे गुजरात राज्य में करने की योजना बनाई है।

अब हर घर तक पहुंच होगी आसान

लॉन्चिंग कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ टैक्सी सेवाओं की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है और आज यह जरूरत हर घर तक पहुंच गई है। उन्होंने साफ किया कि प्राइवेट सेक्टर ▸▸ शेष पेज 5 पर

इससे शोषणमुक्त होंगे लोग

गृहमंत्री शाह ने कहा कि जब यह मुद्दा सामने आया, तो शुरुआत में यह विचार भी आया था कि सरकार को प्राइवेट कैब कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून बनाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल एक नया ▸▸ शेष पेज 5 पर

कैब सेक्टर से शोषण आधारित व्यापार पर लगेगी बंदिश

इस बिजनेस मॉडल के पीछे का सबसे बड़ा विचार कैब सेक्टर से शोषण-आधारित व्यापार को खत्म करना है। जब टैक्सी सर्विस को-ऑपरेटिव मॉडल पर चलेगी, तो मुनाफे और कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा सीधे ड्राइवर्स के पास रहेगा, जिससे प्राइवेट कंपनियों द्वारा होने वाला शोषण खुद ही कम होने लगेगा। शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने सहकारिता के माध्यम से कई अन्य सेक्टर्स में शानदार सफलता हासिल की है, इसलिए यही मॉडल टैक्सी सेक्टर की समस्याओं का भी एक सार्थक और प्रभावी समाधान बन सकता है। खास बात यह है कि 'भारत टैक्सी' का यह नया प्रयोग भारतीय मोबिलिटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का तीन दिवसीय तेलंगाना दौरा आज से, पार्टी संगठन की कई बैठकों में लेंगे हिस्सा

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज रविवार 28 जून से 30 जून मंगलवार तक तेलंगाना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीन दिवसीय संगठनात्मक प्रवास

पर रहेंगे। अपने इस विस्तृत प्रवास के दौरान नवीन प्रदेश में पार्टी के सांगठनिक ढांचे को नई ऊर्जा प्रदान करने, जमीनी स्तर पर जनसंपर्क को व्यापक बनाने और आगामी रणनीतियों को धार देने के उद्देश्य से कई उच्च-स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वे नवनिर्मित जिला कार्यालयों का लोकार्पण करेंगे, युवाओं व बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे तथा तेलंगाना प्रदेश भाजपा की राज्य कार्यकारिणी बैठक का विधिवत उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे।

प्रवास के पहले दिन रविवार को रंगारेड्डी ग्रामीण जिला भाजपा कार्यालय का भौतिक उद्घाटन करेंगे, तथा साथ ही नौ अन्य नवनिर्मित जिला कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से ऐतिहासिक लोकार्पण भी करेंगे। इसके पश्चात वे नामपल्ली स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में जीएचएमसी (ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन), सीएमसी (साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन) और एमएमसी (मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन) के बूथ अध्यक्षों के साथ एक अहम संवाद करेंगे। सायंकाल के समय श्री नवीन प्रदेश के सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर उनका मार्गदर्शन करेंगे।

प्रवास के दूसरे दिन, सोमवार) को नवीन घाटकेसर स्थित विज्ञान भारती इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 'विकसित भारत छात्र सम्मेलन' में सम्मिलित होंगे और युवाओं से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हनमकोंडा के साई नगर स्थित अशोका कन्वेंशन में जनजातीय समाज के प्रमुख नेताओं एवं विभिन्न सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद करेंगे। तत्पश्चात सायंकाल वे पुनः हैदराबाद लौटकर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की एक विस्तृत बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संगठन की भावी रूपरेखा एवं आगामी कार्ययोजना पर गहन मंथन करेंगे।

प्रवास के तीसरे और अंतिम दिन मंगलवार को नवीन घाटकेसर स्थित रॉक एन्क्लेव कन्वेंशन सेंटर में तेलंगाना प्रदेश भाजपा इकाई की अहम 'राज्य कार्यकारिणी बैठक' का विधिवत उद्घाटन करेंगे और अपने विस्तृत उद्बोधन से प्रदेश नेतृत्व व कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देशित करेंगे।

ठाणे से पेपर लीक, कई हिरासत में

महाराष्ट्र में एग्जाम से एक दिन पहले लीक हुआ 'टीईटी' पेपर

शिक्षा विभाग ने रद्द की परीक्षा

फाइल फोटो

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

महाराष्ट्र में 28 जून, 2026 को विभिन्न एग्जाम सेंटर में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की परीक्षा आयोजित कराई जानी थी। लेकिन, परीक्षा से एक दिन पहले ही ठाणे से टीईटी का पेपर लीक हो गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। ठाणे में पुलिस ने पेपर को बरामद किया। साथ ही इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ▸▸ शेष पेज 5 पर

मंत्री नड्डा आज करेंगे शुभारंभ

ई-सुश्रुत क्लीनिक से छोटे स्वास्थ्य केंद्र होंगे डिजिटल

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

देश में छोटे क्लीनिकों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डिजिटलीकरण को नई गति मिलेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा 29 जून को 'ई-सुश्रुतएट द रेट क्लीनिक' का शुभारंभ करेंगे। यह सी-डैक द्वारा विकसित सक्षम हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है।

किफायती डिजिटल समाधान तैयार किया

देश के अनेक छोटे क्लीनिक अब भी मरीजों के पंजीकरण, बिलिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कार्य मैनुअल तरीके से करते हैं। सी-डैक ने इसे विकसित किया है, जो सरल, क्लाउड आधारित और कम लागत वाला डिजिटल समाधान उपलब्ध कराएगा। इसे सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, उप-केंद्रों और निजी क्लीनिकों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

अफगानिस्तान में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप का असर

8 देशों में भी महसूस हुए झटके

दिल्ली- एनसीआर और जम्मू-कश्मीर में भूकंप के तेज झटके

एजेंसी ▸▸ नई दिल्ली

अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7.04 बजे 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत 8 देश भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखा गया। देश में जम्मू-कश्मीर और दिल्ली-एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि, अब

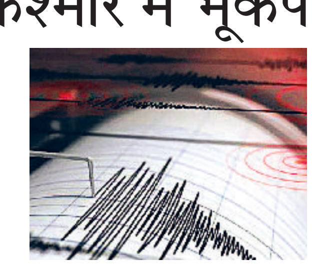

तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसका केंद्र उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान में कलाफगान से करीब 81 किलोमीटर दूर था और गहराई 215 किमी थी।

पिछले 24 घंटों में देश में 2, पाकिस्तान में 4 भूकंप आए

शनिवार सुबह 11:38 बजे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 3.2 तीव्रता का हल्का भूकंप आया था। इसका केंद्र जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर था। इसका केंद्र धर्मशाला से करीब 22 किमी उत्तर-उत्तर-पश्चिम में था। यूरोपियन-भूमध्यसागरीय सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक, पिछले 24 ▸▸ शेष पेज 5 पर

एपीडा की पहल से रीवा सुंदरजा आम ने वैश्विक बाजार में रखे कदम

150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया

1 मीट्रिक टन आमों की पहली खेप यूएई रवाना

हरिभूमि न्यूज ▸▸ भोपाल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद

निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने मध्य प्रदेश के जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को पहले वाणिज्यिक निर्यात में सहायता प्रदान की है।

यह उपलब्धि वैश्विक बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पिछले कई महीनों से एपीडा ने मध्य प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पैकिंग हाउस संचालकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर रीवा सुंदरजा आम के निर्यात की संभावनाओं पर काम किया।

रीवा के किसान ने की शुरुआत

रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक खेप में एक मीट्रिक टन आम शामिल थे, जिसे 26 जून 2026 को मेसर्स साल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया। निर्यात की गई खेप के आम रीवा जिले के गोविंदगढ़ निवासी प्रगतिशील किसान सोनू गुप्ता और ओन्धा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ▸▸ शेष पेज 5 पर

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एचआरडी, जल प्रबंधन, नई शिक्षा नीति योजना की सीएम ने की समीक्षा

बरसात से पहले नालों की सफाई 30 जून तक पूरी करने के दिए आदेश, वार्डों की होगी रैंकिंग

सीएम सैनी ने स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, शिक्षा और जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के दिए निर्देश

हरिभूमि ब्यूरो ▸▸ नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एचआरडी, जल प्रबंधन, नई शिक्षा नीति तथा आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनसेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री के उप-प्रधान सचिव यशपाल यादव ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं समीक्षा बैठक के एजेंडे से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एचआरडी, जल प्रबंधन, नई शिक्षा नीति तथा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति, लंबित कार्यों तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कहीं भी गंदगी का ढेर न लगे

स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन स्थानों पर लोगों का अधिक आवागमन रहता है, वहां विशेष रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरे का संग्रहण हो तथा कहीं भी गंदगी के ढेर न लगने दिए जाएं। सड़कों की नियमित सफाई के साथ-साथ उनके किनारों पर ▸▸ शेष पेज 5 पर

वार्ड समितियों के लिए पोर्टल विकसित करें

उन्होंने वार्ड समितियों के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि समिति के सदस्य एवं नागरिक अपनी समस्याएं एवं सुझाव सीधे साझा कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम आयुक्त त्रैमासिक आधार पर शहरी स्थानीय ▸▸ शेष पेज 5 पर

सीपीए के स्टोर्स में अनियमितताएं उजागर, 5 फार्मासिस्ट और 2 अधिकारी निलंबित

भ्रष्टाचार पर दिल्ली सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति : सीएम

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के विभिन्न स्टोर्स में जांच के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के मामले में 5 फार्मासिस्टों तथा 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच में दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन से संबंधित गंभीर अनियमितताएं एवं लापरवाहियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है और सरकारी व्यवस्था में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही अथवा अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के आवास तक निकाला जाएगा 'बेरोजगार पैदल मार्च' : पूर्व बस मार्शल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

स्थायी रोजगार की मांग को लेकर आंदोलनरत 10,792 पूर्व सिविल डिफेंस बस मार्शलों ने अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। राजघाट पावर हाउस धरना स्थल पर आयोजित आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जुलाई (शनिवार) को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आवास तक 'बेरोजगार पैदल मार्च' निकाला जाएगा। पूर्व बस मार्शलों के प्रतिनिधि मुकेश पाल सिंह ने शनिवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि पूर्व बस मार्शलों के अनुसार, यह पैदल मार्च 'सुबह 9 बजे जापानी पार्क, रोहिणी' से शुरू होकर विधानसभा अध्यक्ष के आवास तक पहुंचेगा। प्रदर्शन में हजारों पूर्व बस मार्शल पोस्टर और बैनर के साथ शामिल होंगे तथा अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। पूर्व बस मार्शलों का कहना है कि 31 अक्टूबर 2023 से

■ पिछले लगभग तीन वर्षों से की जा रही है रोजगार की मांग

बस मार्शल बेरोजगार हैं। रोजगार बहाली की मांग को लेकर वे दिल्ली सचिवालय के समीप राजघाट पावर हाउस धरना स्थल पर लगभग तीन वर्षों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार बनने के बाद भी पूरा नहीं किया वादा

पूर्व बस मार्शलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए सरकार बनने के 60 दिनों के भीतर स्थायी रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के एक वर्ष चार माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी भी पूर्व बस मार्शल को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात के दौरान शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

रानी बाग में संदिग्ध झपटमार पुलिस मुठभेड़ में घायल

एजेंसी, नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक संदिग्ध झपटमार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह मुठभेड़ शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात उस समय हुई, जब पुलिस ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया। आरोपी की पहचान चंदन उर्फ हड्डी के रूप में हुई है, जो चेन झपटमारी के मामलों में शामिल एक कुख्यात अपराधी बताया गया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस दल पर गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें चंदन के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे काबू कर हिरासत में लिया। घटनास्थल से उसके कब्जे से एक आग्नेयास्त्र भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राष्ट्रीय राजधानी में झपटमारी और अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है तथा उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

मुंडका सेप्टिक टैंक के मृतकों के घर पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, 1-1 करोड़ का मुआवजे की मांग

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली के मुंडका फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान हादसे में तीनों मृतकों के सुल्तानपुरी के इंदिरा झील में घर जाकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। इस प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा और एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मांग है कि इस हादसे के दोषी मालिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने की जबकि इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष सुखबीर शर्मा, किराड़ी जिला कांग्रेस अध्यक्ष वरुण ढाका, बनवारी लाल उपाध्याय, सुखबीरी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस बारे में डॉ. नरेश ने कहा कि हमने मुआवजे की मांग पर अड़े परिवारों को प्रशासन से भरोसा दिलवाया है कि उनकी मांग पर सुनवाई होगी। इस भरोसे के बाद कहीं जाकर पीड़ित परिवार ने मृतको के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद एसडीएम मिस्टर मीणा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (एससी) आयोग के सदस्य कर्मवीर कर्मा के सामने प्रतिनिधिमंडल ने मांग को प्रमुखता से रखा। इस दौरान स्थानीय विधायक मुकेश अहलावत भी वहां मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं के दबाव के बाद एसडीएम मीणा और आयोग के सदस्य कर्मवीर कर्मा ने आश्वासन दिया कि वे इन मांगों को दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे और इन्हें हर हाल में पूरा करवाएंगे। इस मामले पर डॉ. नरेश ने कहा कि हम तीनों की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या मानते है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 2013 का स्पष्ट आदेश है, जिसके तहत हाथ से मैला ढोने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद बिना किसी सुरक्षा के गरीब मजदूरों को सीवर और सेप्टिक टैंकों में उतारकर काम कराया जा रहा है। यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि सीधे-सीधे कानून की धज्जियां उड़ाकर की गई हत्या है। यह सब कुछ सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है, जो कि एक हत्या है।

कांग्रेस ने अभी से शुरू की निगम चुनावों की प्रक्रिया अगले 15 दिनों में मांगे हर वार्ड से 3-3 नाम

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली नगर निगम के चुनावों के लिए अभी से अपनी प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रत्येक वार्ड से तीन तीन संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगे है। हालांकि निगम चुनाव में अभी लगभग 16 महीनों का लंबा समय शेष पड़ा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शनिवार को लोकसभा प्रभारी, जिला प्रभारी और विधानसभा आब्जवरों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। दिल्ली कार्यालय राजीव भवन में हुई इस अहम बैठक में यादव ने कहा कि आगामी निगम चुनावों के मद्देनजर सभी विधान सभा आब्जवरों से अगले 15 दिनों में प्रत्येक वार्ड से 3 ऐसे नाम मांगे है जो लोग क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं और जनता के बीच में प्रसिद्ध हैं। जो अच्छी छवि के लिए जाने जानते हों, जिसमें एक महिला, एक एस.सी और एक

जनरल केटेगरी से संबंधित नाम होना चाहिए। यादव ने कि सभी ऑब्जर्वरों की विशेष जिम्मेदारी होगी कि क्षेत्र में अलग थलग पड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों से व्यक्तिगत रुप से मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाले और संगठन में सक्रिय रुप से जोड़े। बैठक में यादव के अलावा बैठक में आगामी निगम चुनावों के मद्देनजर सभी विधान सभा आब्जवरों से अगले 15 दिनों में प्रत्येक वार्ड से 3 नाम मांगे है, जिसमें एक महिला, एक एस.सी और एक जनरल कैटेगरी को होना चाहिए। यादव ने कहा कि निगम चुनावों में अभी समय है, लेकिन हमें अभी से चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करना होगा। जिसके लिए हमने सभी 13 हजार के लगभग बूथों पर बीएलए-2 की सफल नियुक्ति कर भाजपा की वोट चोरी के खिलाफ सभी जिलों में उन्हें ट्रेनिंग दे चुके हैं। बैठक में यादव ने साफ संदेश देते हुए कहा कि ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठकों में जिला व ब्लाक पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में सभी आब्जवरों को प्रत्येक वार्ड में हर बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की संगठन के प्रति गतिविधियों पर सम्पूर्ण निगरानी करने के निर्देश दिए कि हर बूथ को मजबूत करने के लिए सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों और सेक्टर इंचार्ज को एकजुट होकर काम करें। इस अवसर पर यादव के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, प्रदेश महासचिव संगठन एवं कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, प्रदेश प्रशासनिक प्रभारी जतिन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुरेन्द्र कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

एसयूवी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत, चालक गिरफ्तार

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान हरियाणा के गुरुग्राम निवासी सार्थक मट्टू (34) के रूप में हुई है। वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में कार्यरत था। पुलिस के अनुसार, 25 जून को वसंत कुंज दक्षिण थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक एसयूवी गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीसीआर कर्मी मट्टू को तत्काल इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार का पता लगाया। जांच में पता चला कि वाहन बेंगलुरु स्थित एक निजी कंपनी के नाम पर पंजीकृत है। यह कार बिहार निवासी और बेंगलुरु में कंपनी में कार्यरत सागर साहा (29) को किराये पर दी गयी थी।

पूछताछ के दौरान साहा ने पुलिस को बताया कि दुर्घटना के समय वाहन उसका मित्र अपूर्व सिंह (30) चला रहा था। अपूर्व सिंह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का निवासी है, वह एक निजी कंपनी में कार्यरत है और फिलहाल गुरुग्राम में रहता है। पुलिस ने बताया कि हादसे के समय साहा वाहन की अगली सीट पर बैठा था। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और अपूर्व सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसका चिकित्सकीय परीक्षण सफदरजंग अस्पताल में कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है।

डेढ़ महीने से दिन-रात जल रही हाई मास्क लाइट, बिजली की बर्बादी पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली के गांव मुबारकपुर डबास स्थित अंबेडकर चौपाल पर लगी एक सेमी हाई मास्क लाइट पिछले करीब डेढ़ महीने से लगातार दिन-रात जल रही है, जिससे बिजली की अनावश्यक बर्बादी हो रही है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में टाटा पॉवर (टीपीडीडीएल) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। चौगामा विकास समिति के महासचिव विजेंद्र सिंह डबास ने शुक्रवार को बताया कि मुख्य सड़क पर स्थित पोल नंबर 513-35-44 की यह हाई मास्क लाइट लगातार जल रही है। उनका कहना है कि इस कारण हर महीने हजारों रुपये मूल्य

की बिजली व्यर्थ खर्च हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण के बावजूद टीपीडीडीएल के कर्मचारी और अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

महासचिव विजेंद्र सिंह डबास ने कहा कि बिजली की बर्बादी का भार अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है, इसलिए ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने टीपीडीडीएल के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि संबंधित लाइट की तत्काल मरम्मत कराकर बिजली की अनावश्यक बर्बादी रोकी जाए। स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि समय पर रखरखाव और नियमित निरीक्षण से ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है तथा सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत द्वारा "भगोड़ा अपराधी" घोषित एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान साजिद इकबाल (58) के रूप में हुई है, जो तुर्कमान गेट का निवासी है और लंबे समय से गिरफ्तारी और न्यायिक कार्यवाही से बच रहा था। पुलिस को विशेष सूचना मिली थी कि साजिद चांदनी महल इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने जाल बिछाकर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय अदालत ने 30 मई को उसे इस मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। यह मामला इस वर्ष जनवरी में रामलीला मैदान क्षेत्र स्थित फ़ैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान भड़की हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार, हिंसा की वजह सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट थी, जिनमें दावा किया गया था कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तोड़ा जा रहा है। साजिद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में नौ साल से था फरार, पुलिस ने दबोचा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईवोडब्ल्यू) ने एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह व्यक्ति 18 करोड़ रुपये से अधिक की क्रेडिट सुविधा और प्रॉपर्टी के नकली कागजात से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले में 9 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजीव दीक्षित उर्फ संजय शर्मा के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को दिल्ली के ईवोडब्ल्यू थाना पुलिस ने विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला उषा रानी सेठी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दीक्षित ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विवेक विहार में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी के लिए 16 फरवरी 2013 की तारीख वाला एक नकली सेल डीड बनवाया। इसके लिए उन्होंने सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में खुद को उषा रानी सेठी बताकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने बताया कि बाद में इस नकली दस्तावेज़ का इस्तेमाल कनॉट प्लेस स्थित चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक से क्रेडिट सुविधा हासिल करने के लिए 'इक्विटेबल मॉर्गेज' (संपत्ति गिरवी रखकर लोन लेना) बनाने में किया गया, जिससे वित्तीय संस्थानों को गलत तरीके से नुकसान हुआ।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि दीक्षित ने सह-आरोपी सचिन भारद्वाज और अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। उन्होंने शिकायतकर्ता के नाम वाले ही किसी दूसरे व्यक्ति के पैन कार्ड विवरण का इस्तेमाल कर एक महिला को शिकायतकर्ता के तौर पर पेश किया और शिकायतकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना नकली सेल डीड रजिस्टर करवा लिया।

डीएम व एसडीएम कार्यालय के बाहर भी भर जाता है पानी

'मानसून की बारिश ने खोली सरकार और एमसीडी के दावों की पोल'

दया राम ▶▶ नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में मानसून की शुरुआत होते ही एक बार फिर विकास और व्यवस्था का दोहरा चेहरा सामने आ गया है। एक ओर जहां कनॉट प्लेस (सीपी) और वीआईपी इलाकों में हल्का-सा जलभराव होते ही पानी निकासी के लिए पंप, कर्मचारी और मशीनरी तत्काल सक्रिय हो जाती है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली देहात के इलाके आज भी बदहाल सड़कों और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। दिल्ली-हरियाणा सीमा से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (एनएच-44) के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करते ही प्रशासन के मानसून तैयारियों के दावों की हकीकत साफ दिखाई देने लगती है। सोनीपत की तरफ से दिल्ली में प्रवेश करते ही कई स्थानों पर जलभराव और क्षतिग्रस्त सड़कें यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक कार्यालय के बाहर ही जलनिकासी की उचित व्यवस्था दिखाई नहीं दी। वहीं, इसी मार्ग पर वापसी आते समय लिबासपुर, बुढ़पुर और अलीपुर से टीकरी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर भी कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे आम लोगों और सार्वजनिक परिवहन के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

■ राजमार्ग पर नजर नहीं आई जलनिकासी की उचित व्यवस्था

दिल्ली देहात के इलाकों को भी दी जाए समान प्राथमिकता

दिल्ली देहात के लोगों का कहना है कि राजधानी का विकास तभी सार्थक होगा, जब शहर के साथ-साथ गांवों को भी समान सुविधाएं और प्रशासनिक प्राथमिकता मिले। स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और संबंधित विभागों से मांग की है कि कनॉट प्लेस की तरह दिल्ली देहात के इलाकों को भी समान प्राथमिकता दी जाए। जलभराव वाले स्थलों की पहचान कर स्थायी जलनिकासी व्यवस्था विकसित की जाए, क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए और मानसून के दौरान नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन मिल सके।

एनएच -44 पर जगह-जगह जलभराव, सफर बना मुश्किल

सिंघु बॉर्डर टोल प्लाजा पार करते ही श्री गुरु तेग बहादुर स्मारक के सामने सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। इसके करीब एक किलोमीटर आगे सिंघु गांव के प्रवेश द्वार के पास गहरे गड्ढों में बारिश का पानी जमा है, जिससे वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके बाद 'जस्ट चिल वाटर पार्क' के सामने मुख्य मार्ग पर बदहाल सड़क और जलभराव नजर आता है। आगे बढ़ने पर अलीपुर गांव के मुख्य बस स्टैंड तथा आउटर नॉर्थ जिला राजस्व (डीएम-एसडीएम) कार्यालय के बाहर भी बारिश का पानी जमा मिला।

क्या दिल्ली देहात राजधानी का हिस्सा नहीं: ग्रामीण

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम का पूरा ध्यान केवल कनॉट प्लेस और वीआईपी इलाकों पर केंद्रित रहता है। वहां मामूली जलभराव होने पर तत्काल पंप लगाकर पानी निकाला जाता है, जबकि दिल्ली देहात के लोग वर्षों से जलभराव, टूटी सड़कों और खराब जलनिकासी व्यवस्था की समस्या झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि राजधानी के सभी नागरिक समान हैं तो सुविधाएं और प्रशासनिक संवेदनशीलता भी समान होनी चाहिए। दिल्ली देहात के साथ यह भेदभाव उचित नहीं है।

मानसून तैयारियों के दावों पर उठे सवाल

हर वर्ष मानसून से पहले दिल्ली सरकार, एमसीडी और संबंधित विभाग करोड़ों रुपये खर्च कर नालों की सफाई और जलनिकासी की व्यापक तैयारियों का दावा करते हैं। लेकिन मानसून की शुरुआती बारिश ने ही इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर जलभराव यह संकेत देता है कि कई स्थानों पर तैयारियां पर्याप्त नहीं रहीं।

महिलाओं और युवाओं को भी दिया गया पर्याप्त अवसर: मल्होत्रा

■ प्रदेश भाजपा ने जिलों और कुछ मंडल पदाधिकारियों की सूची की जारी

नई दिल्ली। महिला सशक्तिकरण के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने 33 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है और युवाओं को भी पर्याप्त अवसर दिया गया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से 11 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों ने अपने-अपने जिलों के पदाधिकारियों की सूची विधिवत घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष मल्होत्रा के अनुसार, तीन जिलों: उत्तर बाहरी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ की सूची वर्तमान जिला अध्यक्षों से परामर्श के बाद उचित समय पर घोषित की जाएगी। कुछ नए मंडल अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की नियुक्ति में भी सभी मानकों का सख्ती से पालन किया गया है। नई संगठनात्मक व्यवस्था दिल्ली की जनता की सेवा के लिए पार्टी संगठन को और अधिक ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करेगी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आरोपी तौहिद पुत्र** खुर्शीद, **पताः** किदवई नगर 2 मोदीनगर गाजियाबाद, **उत्तर प्रदेश CC No. 2348/19, U/S: 138 NI Act, पुलिस थानाः भजनपुरा, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **तौहिद,** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **तौहिद,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **तौहिद, CC No. 2348/19, U/S: 138 NI Act, पुलिस थानाः भजनपुरा, दिल्ली** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **27.07.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
पंकज राय
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–01
कमरा नं. 73, पाँचवा तल उत्तर पूर्वी जिला
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

DP/8689/NE/2026
(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P.C. & 84 BNSS देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **आरोपी प्रवीन उर्फ चंचल, पुत्रः** कृष्ण कुमार **पताः** मकान नंबर ई–123 जय विहार फेस–1 नजफगढ़, दिल्ली **FIR No. 849/2015, U/s: 354/354B/506/509 IPC, पुलिस थानाः नजफगढ़, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **प्रवीन उर्फ चंचल,** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **प्रवीन उर्फ चंचल,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **प्रवीन उर्फ चंचल, FIR No. 849/2015, U/s: 354/354B/506/509 IPC, पुलिस थानाः नजफगढ़, दिल्ली** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **01.08.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
ईब्बानी अग्रवाल
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी महिला कोर्ट–03,
दक्षिणी पश्चिम जिला कमरा नं. 312, जिला कोर्ट
द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली

DP/8407/DW/2026
(Court Matter)

खबर संक्षेप

संस्कृत भाषा और गीता के ज्ञान से मिलती है राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा: सत्या

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने शनिवार को वसंत कुंज स्थित संस्कृत भारती गुरुकुल में आयोजित गीता शिक्षण केन्द्रस्य अभ्यासवर्ग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और आचार्यों से संवाद करते हुए भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा तथा श्रीमद्भगवद्गीता के अमूल्य ज्ञान पर विस्तार से चर्चा की। सत्या शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश आज भी समाज और मानव जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है, जितना हजारों वर्ष पहले था। उन्होंने कहा कि गीता जीवन में कर्तव्य, नैतिकता और आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम केवल धार्मिक या शैक्षणिक आयोजन नहीं होते, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है और उनमें राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होती है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने संस्कृत भारती गुरुकुल के आचार्यों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रसार में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत और गीता के अध्ययन को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

आईपी विश्वविद्यालय को मिली बेहतर रैंकिंग

नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को 'टाइम्स हायर एजुकेशन सततता प्रभाव रैंकिंग 2026 में एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा' के अंतर्गत 201-300 वैश्विक बैंड में स्थान मिला है। आईपीयू प्रशासन ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रशासन ने बताया कि यह विश्वविद्यालय की अनुसंधान, नवाचार और उद्योग सहभागिता में बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। एक ऐसे युग में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और लचीला बुनियादी ढाँचा अर्थव्यवस्थाओं को फिर से परिभाषित कर रहे हैं, नवाचार अब प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं रहा बल्कि यह एक आवश्यकता बन गया है। प्रशासन ने बताया कि विश्वविद्यालय इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ज्ञान का सृजन कर, प्रतिभा विकसित कर और ऐसे समाधान उपलब्ध करा रहा है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं का उत्तर देते हैं। नवाचार की यह भावना विश्वविद्यालय के अटल इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और मजबूत होती है, जहाँ विचारों को समाधानों, स्टार्टअप्स और सतत उद्यमों में बदला जाता है।

एमसीडी ने की अवैध कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत शाहदरा नॉर्थ ज़ोन में दो अनधिकृत कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया। एमसीडी के अनुसार, इन कोचिंग संस्थानों द्वारा लागू नगर निगम नियमों और आवश्यक प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। जांच के दौरान नियमों के पालन में अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। एमसीडी प्रशासन ने शनिवार को यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि कि राजधानी में भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और शहरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संस्थानों को निर्धारित सुरक्षा एवं नगर निगम के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार हुई सख्त

मुख्यमंत्री रेखा की चेतावनी : एक महीने में अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा करें सभी कोचिंग संस्थान

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि एक महीने के भीतर सभी सभी कोचिंग सेंटर अग्नि सुरक्षा मानकों (फायर गाइडलाइंस) को पूरा करने करें, यदि तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो उन संस्थानों को तुरंत सील कर दिया जाएगा। शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की संख्या कितनी है, यह हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे बच्चों की सुरक्षा और जिंदगी सबसे बढ़कर है। माता-पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए भेजते हैं, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वे सुरक्षित हाथों में रहें। सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा।मुख्यमंत्री ने छात्रों से भी अपील की है कि अगर उनका कोचिंग सेंटर असुरक्षित है या वहां नियमों की अनदेखी हो रही है, तो वे सीधे मैसेज, ईमेल या फोन के जरिए सरकार को इसकी शिकायत दें। हर शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए एक बेहद दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। बता दें कि लखनऊ में एक कमर्शियल बिल्डिंग में स्थित कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने के कारण 15 छात्रों की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक अगले एक महीने के भीतर दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटरों को निम्नलिखित मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर सीधे सीलिंग की कार्रवाई होगी। इसके लिए दिल्ली फायर सर्विस से अनिवार्य रूप से निरीक्षण कराकर सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा। हर फ्लोर और क्लासरूम की क्षमता के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर (आग बुझाने वाले सिलेंडर) लगाने होंगे। किसी भी हादसे की स्थिति में बच्चों के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए चौड़े और साफ आपातकालीन रास्ते होने चाहिए। संकरी सीढ़ियों या बेसमेंट के अवैध इस्तेमाल पर रोक होगी। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे, उचित वेंटिलेशन (हवा की व्यवस्था) और क्षमता से अधिक बच्चों को एक साथ न बैठाने के नियम का पालन करना होगा। दिल्ली नगर निगम और दमकल विभाग को इस जांच और सुधार प्रक्रिया की डेली एक्शन टेकन रिपोर्ट सीधे सरकार को सौंपनी होगी।

लखनऊ हादसे के बाद दिल्ली सरकार तुरंत हरकत में आई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली के प्रमुख कोचिंग हब जैसे मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर और कटवारिया सराय में चल रहे 923 कोचिंग सेंटरों के विशेष निरीक्षण और फायर ऑडिट के आदेश दिए गए। कोर्ट की कमेटी के सुझावों के आधार पर सरकार अब कोचिंग सेंटरों की जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत नियामक कानून भी लाने जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

■ सलाह : दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वेबसाइट पर रखें नजर

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस- 2026) के तहत फेज-1 पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीयू प्रशासन ने शनिवार को यह जानकारी दी। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए सीयूईटी (यूजी)-2026 में शामिल हुए अभ्यर्थियों से जल्द पंजीकरण करने की अपील की है। विश्वविद्यालय के अनुसार, 67 कॉलेजों में संचालित 73 स्नातक कार्यक्रमों और 100 से अधिक बी.ए. कार्यक्रमों में प्रवेश केवल सीयूईटी (यूजी)-2026 के अंकों के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तों का पालन करना होगा, जिनका विवरण पाठ्यकम विवरण पुस्तिका यानी प्रॉस्पेक्टस 2026-27 में उपलब्ध है।

अभ्यर्थी वेबसाइट https://ugadmission.uod.ac.in पर जाकर अपने सीयूईटी (यूजी)-2026 आवेदन संख्या के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस वर्ष जन्मतिथि, फोटो और हस्ताक्षर जैसी आवश्यक जानकारी सुरक्षित एपीआई प्रणाली के माध्यम से स्वतः प्राप्त की जाएगी, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सरल और त्रुटिरहित बनेगी। पंजीकरण शुल्क को लेकर डीयू प्रशासन ने बताया कि सा मा न्य / ओ बी सी - एनसीएल/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 250 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है जबकि एससी/एसटी/दिव्यांग वर्ग के लिए यह शुल्क 100 रुपए निर्धारित है।

डीयू प्रशासन के अनुसार, फेज-1 के बाद अभ्यर्थियों को फेज-2 में अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। इस दौरान सीयूईटी के विषयों का मिलान कक्षा 12वीं में पढ़े गए विषयों से किया जाएगा और उसी के आधार पर पात्रता एवं मेरिट सूची तय होगी। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले यूजी प्रॉस्पेक्टस और सीएसएएस (यूजी) 2026-27 के दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रवेश से जुड़ी सभी नई जानकारी के लिए नियमित रूप से admission.uod.ac.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

छात्रों को नौकरी देने वाले बनाने के लिए सहायता करेगी दिल्ली सरकार : सूद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार छात्रों को नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनाने में सहायता करेगी। सरकार इसके लिए छात्रों को अपने विचारों को नवाचार में बदलने के लिए आधारभूत ढांचा, अनुदान और अन्य संसाधन उपलब्ध कराएगी। यह बातें शनिवार को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में आयोजित 'टेक4फ्यूचर-फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूटकैम्प' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही।शिक्षा मंत्री सूद ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपको सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा देना चाहते हैं और आपके विचारों को विकसित करने में संस्थागत सहायता देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराऊं। संसाधनों की चिंता न करें, केवल अपने विजन को बड़ा बनाएं। इस कार्यक्रम में सीएम श्री स्कूलों के छात्रों द्वारा विकसित नवाचार परियोजनाओं और कार्यात्मक आदर्श प्रतिरूपों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रस्तुत किए गए। सूद ने कहा कि ये छात्र केवल बच्चे नहीं हैं, बल्कि समस्या समाधानकर्ता हैं, जो एक 'विकसित दिल्ली' और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देंगे। कृत्रिम मेधा (एआई) और स्वचालन से रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को मानव बुद्धि के विकल्प के बजाय दक्षता बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखा जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि एआई आंकड़े दे सकता है, लेकिन विवेक केवल मानव मस्तिष्क से आता है। वास्तविक नवाचार मशीनें नहीं, बल्कि वे प्रश्न हैं जो हम क्यों और कैसे पूछते हैं। यही प्रश्न नवाचार को जन्म देते हैं। मंत्री सूद ने कहा कि सरकार रोबोटिक्स प्रयोगशालाएं और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित कर रही है ताकि छात्र केवल तकनीक के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके निर्माता बन सकें।

राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान ऐतिहासिक रहा है : गुप्ता

नई दिल्ली। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान असाधारण एवं ऐतिहासिक रहा है। यह बात दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को रोहिणी सेक्टर-9 स्थित बाल संस्कार शिविर 2026 के समापन अवसर पर कही। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आइए, हम सभी मिलकर रोहिणी को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और हरित बनाने का संकल्प लें। हमने इस वर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार पौधे लगाने तथा उन्हें पूर्ण विकसित वृक्ष बनने तक संरक्षित एवं पोषित करने का संकल्प लिया है। इस दौरान सम्पूर्णा महिला हाट तथा डॉ. शोभा विजेन्द्र की पुस्तक 'शतायु संघ और महिला सहभागिता' के परिचय एवं समीक्षा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के नव-निर्वाचित सदस्य अधिकारीमयुम शारदा देवी, सम्पूर्णा की संस्थापक डॉ. शोभा विजेन्द्र, सम्पूर्णा संस्था के पदाधिकारी, महिला उद्यमी, बाल संस्कार शिविर के प्रतिभागी, विशिष्ट अतिथि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई इबारत : रेखा गुप्ता

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

■ नरेला के रामदेव चौक स्थित कम्फर्ट जोन में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया संबोधित

पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश ने अंत्योदय और आत्मनिर्भरता की एक नई और स्वर्णिम इबारत लिखी है। आज भारत न केवल वैश्विक पटल पर बेहद मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है, बल्कि देश के कोने-कोने में डिजिटल क्रांति, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार और जनकल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ सीधे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यह बातें शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नरेला के रामदेव चौक स्थित कम्फर्ट जोन में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कही। यह सम्मेलन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया, नरेला से विधायक राजकरण खत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वनिधि जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर को गरिमापूर्ण और सुगम बनाया है। उन्होंने बताया कि नरेला और बाहरी दिल्ली के विकास पर बात करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक प्रगति और नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने की प्रतिबद्धता जताई। मात्र सवा वर्ष में नरेला विधानसभा में लगभग 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें सड़क, नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नरेला दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है और लंबे समय तक विकास से वंचित रही। वर्तमान सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। क्षेत्र में 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 2 अटल कैंटीन, गांवों में सड़क निर्माण, बेहतर परिवहन सुविधाएं तथा अन्य बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने नरेला में एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1,350 करोड़ रुपये की लागत से भूमि खरीदी है, जिससे गांव और देहात के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही, रिठाला–कुंडली वाया नरेला मेट्रो कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान करते हुए 5,000 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई है ताकि परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेला क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं जैसे बाईपास, फुटओवर ब्रिज, बालिका कॉलेज तथा अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सांसद, विधायक, पार्षद और जिला संगठन के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के प्रत्येक विकास कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने वहां मौजूद सभी युवाओं, महिलाओं और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत 2047 मिशन के तहत भारत को एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने का आह्वान किया।

चोरी के मोबाइल फोन की सीमा-पार तस्करी का भंडाफोड़

■ 10 संदिग्धों को किया गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। चोरी के मोबाइल फोन बांग्लादेश और नेपाल में तस्करी कर भेजने में कथित तौर पर सक्रिया रूप से शामिल एक सीमा पार गिरोह से जुड़े 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य के 325 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में चोरी के मोबाइल फोन ठिकाने लगाने वाले एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जो कथित तौर पर करीब एक वर्ष से सक्रिय था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि इस गिरोह ने संगठित माध्यमों से 10,000 से 12,000 चोरी के मोबाइल फोन की तस्करी की है। पुलिस ने इसे हाल के वर्षों में रोहिणी जिले में चोरी के मोबाइल फोन की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक बताया। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बहुस्तरीय नेटवर्क के जरिए काम करता था, जिसमें चोर, स्थानीय प्राप्तकर्ता (चोरी का सामान खरीदने वाले), मोबाइल एकत्र करने वाले, गोदाम संचालक, कूरियर संचालक और सीमा पार संपर्क शामिल थे। पुलिस के अनुसार, जिले में मोबाइल फोन चोरी, घरों में सेंधमारी और झपटमारी की घटनाओं में बढ़ोतरी तथा बरामदगी कम होने के बाद जांच शुरू की गई। अपराध के तौर-तरीकों के विश्लेषण में पता चला कि चोरी हुए कई मोबाइल भारतीय दूरसंचार नेटवर्क पर दोबारा सक्रिय नहीं हो रहे थे, जिससे आशंका हुई कि उन्हें जल्द ही दिल्ली से बाहर भेज दिया जाता था। इसके बाद गठित विशेष टीम ने करीब 200 आपराधिक रिकॉर्ड की समीक्षा की और सैकड़ों आदतन चोरों, झपटमारों तथा चोरी का सामान खरीदने वालों की गतिविधियों का विश्लेषण किया। जांचकर्ताओं ने तकनीकी निगरानी, जब्त मोबाइल फोन की डिजिटल जांच, कूरियर के जरिए भेजे गए सामान की कड़ियों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर इस गिरोह का पता लगाया। पुलिस के अनुसार, 19 जून को राजा उर्फ राजू, करण और गोविंद की गिरफ्तारी के साथ मामले में अहम सफलता मिली। उनके कब्जे से 101 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। गोविंद की तलाशी के दौरान एक कूरियर रसीद मिली, जिससे पता चला कि करीब 200 अन्य चोरी के मोबाइल फोन पहले ही कोलकाता भेजे जा चुके हैं। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने 23 जून को अजय कुमार और अली खान को गिरफ्तार किया। दोनों पर चोरी के मोबाइल फोन प्राप्त करने, उनकी छंटाई, पैकिंग और दूसरे राज्यों में भेजने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी के बाद 100 और मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में यह भी पता चला कि अजय ने रोहिणी के अवंतिका क्षेत्र में एक फ्लैट किराये पर लिया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर चोरी के मोबाइल फोन को जमा करने, पैक करने और भेजने के लिए गोदाम के रूप में किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि बाद की छापेमारी में ऋषिकेश कुमार उर्फ डब्लू, संजीव कुमार और सनी कुमार उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया।

एबीवीपी ने डीयू स्नातक प्रवेशार्थियों की सहायता के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर

■ तकनीकी जानकारी के अभाव में प्रवेश प्रक्रिया में ना हो दिक्कतें

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक प्रवेश प्रक्रिया का आरंभ चुका है। देशभर के लाखों विद्यार्थी डीयू का हिस्सा बनने के लिए हेतु आवेदन कर चुके हैं। हर वर्ष की भांति

इस वर्ष भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) दिल्ली ने प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की सहायता के लिए अपना एबीवीपी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कई छात्रों को तकनीकी जानकारी के अभाव में प्रवेश प्रक्रिया, फॉर्म भरने, कट-ऑफ और पाठ्यक्रम चयन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के त्वरित समाधान के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एबीवीपी ने कार्यकर्ताओं की एक हेल्पलाइन टीम गठित की है। नए आवेदक इन संपर्क सूत्रों पर 9999977990, 9084206032, 7052014490, 7310902683 और 6202523798 संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवेश लेने वाले छात्रों की मदद करने के लिए तैयार

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि देश के कोने कोने से छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना लेकर आते हैं। नामांकन के दौरान उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फॉर्म भरने या काउंसलिंग के दौरान उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आती है। एबीवीपी का यह हेल्पलाइन नंबर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी मेधावी छात्र का सपना केवल जानकारी की कमी से न टूटे। एबीवीपी के कार्यकर्ता 24 घंटे स्नातक में प्रवेश लेने वाले छात्रों की मदद करने के लिए तैयार हैं।

मानसून के इंतजार में दिल्ली, एक सप्ताह की देर से जुलाई में होगा आगमन, प्री मानसून बारिश दे सकती है राहत

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून आने की आमतौर पर 27 जून की तारीख मानी जाती है, लेकिन इस बार यह चूक गई है। मौसम विभाग की माने तो अब मानसून एक करीब एक सप्ताह की देरी के साथ 3 या 4 जुलाई के आसपास दिल्ली में दस्तक दे सकता है। निजी मौसम विज्ञान कंपनी स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत के अनुसार दिल्ली के साथ ही हरियाणा और पंजाब में मानसून के आने के लिए और इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अगले कुछ दिनों में सिर्फ़ कुछ जगहों पर प्री-मानसून बारिश होने की संभावना है। पलावत ने कहा कि जुलाई की शुरुआत में मौसम के बेहतर होने पर मानसून के फिर से आने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में साउथ वेस्ट मॉनसून का इंतज़ार अभी और जारी रहेगा। क्योंकि मौसम की हालत इसके तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है। मानसून सेंट्रल और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट भारत में इसके आगे बढ़ने में देरी हो रही है, जिससे लाखों लोग अभी के गर्म और उमस भरे मौसम से राहत का इंतज़ार कर रहे हैं। पलावत ने कहा कि 26 जून तक, मानसून की वेस्टर्न ब्रांच सिर्फ़ साउथ गुजरात तक ही आगे बढ़ी है, जबकि ईस्ट ब्रांच नॉर्थ बिहार पहुंच गई है। आम तौर पर, इस तारीख तक, मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों को कवर कर लेता और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों तक पहुँच चुका होता है। ऐसे में इससे नॉर्थ वेस्ट भारत में मौजूदा मानसून अपने क्लाइमेट शेड्यूल से लगभग एक हफ़्ते पीछे हो गया है। उन्होंने बताया कि देरी की मुख्य वजह सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट भारत में कोई मज़बूत सिनॉप्टिक वेदर सिस्टम न होना है। हालांकि मानसून का करंट पश्चिमी तट और उत्तर-पूर्वी राज्यों में एक्टिव है, लेकिन इसमें उत्तर-पश्चिमी मैदानों में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी रफ़्तार की कमी है। एक और रुकावट यह है कि अरब सागर के ऊपर मानसून का बहाव काफी कमजोर है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर साफ़ तौर पर कम दबाव वाला एरिया नहीं है। ऐसे सिस्टम आमतौर पर मानसून सर्कुलेशन को मजबूत करते हैं और मानसून को पूरे उत्तर भारत में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी धक्का देते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले तीन से चार दिनों में, दिल्ली में सिर्फ़ कुछ जगहों पर प्री-मानसून एक्टिविटी हो सकती है। कुछ जगहों पर, खासकर शाम या रात के समय, तेज हवाओं के साथ लोकल गरज के साथ बारिश हो सकती है और थोड़ी देर के लिए बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि हालांकि, ये बारिशें कहीं-कहीं ही होंगी और दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत का संकेत नहीं देंगी। दिन का तापमान नॉर्मल के करीब रह सकता है, जबकि उमस का लेवल ज्यादा रहने की संभावना है, जिससे मौसम खराब हो सकता है। जुलाई की शुरुआत में मानसून के नए झोंके की उम्मीद है। जून के आखिर और जुलाई की शुरुआत में मौसम के हालात बेहतर होने की उम्मीद है। मौसम के मॉडल बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक अच्छा सिनॉप्टिक सिस्टम बन सकता है, जिससे पूर्वी और मध्य भारत में मानसून का बहाव मजबूत हो सकता है। जैसे-जैसे यह सिस्टम अंदर की ओर बढ़ेगा और मानसून का सर्कुलेशन तेज होगा, दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ने और फिर उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ने की उम्मीद है। अगर मौसम की ये हलचल उम्मीद के मुताबिक होती है, तो दक्षिण-पश्चिम मानसून के 3 या 4 जुलाई के आसपास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पहुँचने की संभावना है। एक या दो दिन के बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगे बढ़ना आने वाले मौसम सिस्टम की ताकत और मूवमेंट पर निर्भर करेगा।

खबर संक्षेप

हवाई फायरिंग के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। अपराध शाखा एवीटीएस भूपानी की टीम ने थाना तिगांव क्षेत्र में युवक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करनेए गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने तथा हवाई फायरिंग करने के मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान भविष्य उर्फ भोला निवासी गांव भुआपुरए फरीदाबाद तथा लक्ष्य उर्फ लक्की निवासी गांव मुरतजापुर, जिला गाजियाबाद हाल निवासी तिगांव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गांव भुआपुर निवासी रविन्द्र की शिकायत पर थाना तिगांव में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 7 जून 2026 की शाम करीब 8 बजे एक कार में सवार कुछ युवक उनके घर के बाहर तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे थे।

साइबर ठगी के मामले में तीन लोग गिरफ्तार

फरीदाबाद। साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने सीआईएसएफ के नाम पर सरकारी खरीद का झांसा देकर 30,000 की साइबर ठगी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल किशोर निवासी हरदोई उत्तर प्रदेश, जतिन बाबू निवासी गांव शब्दलपुर, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश तथा राहुल गुप्ता निवासी गांव मेंडिया, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़ निवासी एक आरसीसी टाइल्स निर्माता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 17 जनवरी को एक व्यक्ति ने स्वयं को सीआईएसएफ का अधिकारी बताकर उससे संपर्क किया आरसीसी टाइल्स की आवश्यकता होने की बात कही ठग ने व्हाट्सएप के माध्यम से कथित परचेज ऑर्डर एवं अन्य दस्तावेज भेजकर उसका विश्वास जीत लिया।

गुरुग्राम के विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा से नहीं होगा समझौता: राव नरबीर सिंह

- मंत्री ने चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया

धर्मेंद्र कौशिक ▸▸ गुरुग्राम

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में सफाई व्यवस्था, वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन, ड्रेनेज नेटवर्क, नई जोन व्यवस्था, प्रॉपर्टी आईडी, राजस्व संग्रह और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही व प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हों और उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। राव नरबीर सिंह ने कहा कि किसी भी ठेकेदार को उसकी क्षमता से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। यदि कोई एजेंसी तय समय में काम पूरा नहीं करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले सड़क, सीवर, ड्रेनेज और अन्य निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 366 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण, सीवरेज, पेयजल, जल निकासी, पार्क विकास, सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य प्रगति पर हैं।

शीघ्र परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू किया जाएगा

मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की जाएं ताकि नागरिकों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बैठक में आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं नॉलेज सेंटर, नई सड़कें सीवर एवं पेयजल नेटवर्क विस्तार, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, सामुदायिक केंद्र और खेल सुविधाओं सहित कई नई विकास परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू किया जाए। बैठक में निगमायुक्त प्रदीप दहिया, अतिरिक्त निगमायुक्त अंकिता चौधरी, यश जालुका एवं रविंद्र यादव, चीफ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रीज सुनील शर्मा, संयुक्त आयुक्त सपना यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता तिलकराज मल्होत्रा सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

खाद्य मंत्री राजेश नागर ने नगर निगम अधिकारियों के निर्देश दिए

मानसून से पूर्व जलभराव की समस्या न हो निर्बाध बिजली के लिए व्यवस्था सही करें

- जलजमाव वाले क्षेत्रों की पहचान करें
- अधिकारियों के साथ व्यवस्था का दौराकर जायजा लिया
- आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए

हरिभूमि न्यूज ▸▸ फरीदाबाद

हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर ने मानसून को देखते हुए शहर में जलजमाव की समस्या तथा बिजली संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम, एफएमडीए, बिजली निगम और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या आम जनता के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए संभावित जलजमाव वाले क्षेत्रों की पहचान करें और वहां जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों और सीवर लाइनों की सफाई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि बारिश का पानी बिना किसी बाधा के निकल सके। निरीक्षण के दौरान मंत्री राजेश नागर ने पुरी प्राणायाम के आसपास के क्षेत्र का भी दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में जल निकासी, सड़कों की स्थिति तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यक हो, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि बारिश के मौसम में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमों को तैयार रखा जाए

बिजली व्यवस्था को लेकर मंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मरों, बिजली लाइनों और अन्य उपकरणों की जांच कर संभावित खामियों को दूर किया जाए। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीमों को तैयार रखा जाए। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

अवैध कार्रवाई पर जांच का भरोसा दिया

नेहरू कालोनी वासियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को सौंपा मांगों का ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ▸▸ फरीदाबाद

नेहरू कालोनी वासियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय का प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सुबह ही नेहरू कालोनी और अन्य कालोनियों के सैकड़ों परिवार नेहरू गर्ल्स सेक्टर-16 के साथ लगे पार्क में इकट्ठा होकर सभा की। सभा को संघर्ष समिति के चेयरमैन बिजेंद्र, संयोजक वीरेंद्र डंगवाल, सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान, सचिव सुधा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, जिला प्रधान करतार सिंह, एटक नेता रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नवल सिंह, एटक के नेता कामरेड आर एन सिंह ने प्रमुख रूप से संबोधित किया।

मार्क्सवादी पार्टी के राज्य सचिव प्रेम चंद ने भी आंदोलनकारी परिवारों को संबोधित किया तथा पार्टी की ओर से आंदोलन के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए भाजपा सरकार के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की। अपने संबोधन में तमाम वक्ताओं ने कहा कि नेहरू कालोनी समेत सभी कालोनियां अवैध नहीं हैं बल्कि इन्हें तोड़ने की कार्रवाई अवैध है। लाखों परिवार फरीदाबाद में इन्हीं कालोनियों में रहते हैं। फरीदाबाद व देश के विकास में यह योगदान दे रहे हैं। ये यहां के वोटर हैं, राशन कार्ड धारक हैं, फैमिली आईडी इनकी हैं। फिर भी भाजपा इन्हें उजाड़ने पर तुली है। बड़े शर्म की बात है कि जिन कालोनियों के इन परिवारों ने भाजपा के पार्षदों को जिताया, विधायकों ओर सांसदों को बनाया वही अब इनके घरों को तबाह कर रही है। उसके बाद जुलूस में प्रदर्शन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर पहुंचा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल प्रदर्शनकारियों के बीच आए। उन्होंने मांग पत्र लिया। संघर्ष समिति के नेताओं ने मंत्री गोयल से पूछा कि आप बताएं कि नेहरू कालोनी में बुलडोजर चलाने का निर्देश किसने दिया। इस कालोनी व अन्य कालोनियों में तोड़फोड़ की इस अवैध कार्रवाई के लिए कौन जिम्मेदार है, विपुल गोयल ने कहा कि में इसकी जांच करवाऊंगा। मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए हम तय करेंगे कि किसी का घर न टूटे व अब तोड़फोड़ की कार्रवाई न हो। कालोनी में बिजली पानी की बहाली को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली बहाल हो गई है, पानी भी एक हिस्से में पहुंच गया है। बाकी में भी पहुंच जाएगा। नगर निगम कमिश्नर कार्यालय पर चल रहे धरने पर आगामी दिनों में कोई पुलिस हस्तक्षेप नहीं होगा। आप शांतिपूर्वक अपना धरना जारी रख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए।

अपराध शाखा सेक्टर 30 द्वारा की गई कार्रवाई

मालखाना से हथियार चोरी करने के मामले में आईटीआई विद्यार्थी सहित 20 गिरफ्तार, हथियार बरामद

हरिभूमि न्यूज ▸▸ फरीदाबाद

थाना सैक्टर-8 के मालखाने से करीबन 30 से अधिक लाईसेंसी पिस्तौल चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस आयुक्त डॉ. सतेन्द्र गुप्ता ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मालखाना प्रभारी एएसआई बिजेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार कर हथियारों को बरामद कर लिया है।

गौरतलब है कि बीते 9 मई को प्रबंधक थाना सेक्टर 8 निरीक्षक राजबीर सिंह द्वारा मालखाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना मालखाना से हथियार गायब मिले। जिस पर थाना सेक्टर 8 में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार अपराध शाखा की टीमों का गठन कर घटनाक्रम में त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम ने सफलता हासिल करते हुए आईटीआई विद्यार्थी मोनू सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और चोरी किए गए सभी हथियार बरामद कर लिये हैं। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू निवासी गांव करनेरा फरीदाबाद, विपिन कुमार निवासी निवासी तिजारा राजस्थान, संजय सुनारिया वासी तिजारा राजस्थान, सरिता वासी गांव करनेरा फरीदाबाद, पवन वासी गांव कमालपुर खैरथल राजस्थान, अजय वासी जीवन नगर पार्ट-2 गोच्छी, मुजेसर, अंकित निवासी बसेलवा कॉलोनी ओल्ड फरीदाबाद, बलवान वासी गांव डूंगरवास रेवाड़ी, प्रदीप वासी गांव मिलकपुर भिवाड़ी, दीपक उर्फ बल्ली वासी मिल्कपुर तिजारा, पुष्पेंद्र, अमन, सचिन, अमित, आशीष वासी गण जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश, दिनेश उर्फ दीनू जिला रेवाड़ी, मुहम्मद तालीम वासी गांव घासेड़ा जिला नूंह धीरज वासी गांव पोंडरी जिला पलवल, राहुल वासी गांव भोगीपुर जिला मेवात, प्रवीण सहरावत वासी गांव हसनपुर नूंह के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि मोनू आईटीआई विद्यार्थी था और कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा था। जिसके द्वारा अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच थाना के मालखाना से हथियार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और फिर हथियारों को अपने मामा के लड़के विपिन के माध्यम से तिजारा निवासी संजय को दिये थे।

आरोपी महिला को फोन कर मिलने का दबाव बना रहा था

महिला कर्मी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी हवालात में

हरिभूमि न्यूज ▸▸ गुरुग्राम

उद्योग विहार एरिया में एक महिला कर्मी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया लोहे का दाव और बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया है।

दरअसल, बीती 20 जून को पुलिस को सूचना मिली कि उद्योग विहार फेज-5 में एक महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। सूचना मिलते ही थाना उद्योग विहार पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल महिला को उपचार के लिए सेक्टर-10 स्थित सरकारी अस्पताल भेजा जा चुका था। जहां महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी कंपनी से ड्यूटी समाप्त कर घर लौटने के लिए कंपनी के गेट से बाहर निकली थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने अचानक उस पर लोहे के दाव से जानलेवा हमला कर दिया। शिकायत के आधार पर उद्योग विहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को रोहतक के पीजीआईएमएस से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान यूपी के अमेठी निवासी शिव कुमार के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, वारदात के दौरान आरोपी के पैर में भी चोट लग गई थी, जिसके चलते वह अस्पताल में उपचाराधीन था। पउसकी पीड़िता से वर्ष 2024 में पहचान हुई थी। इसके बाद वह लगातार महिला को फोन कर मिलने का दबाव बना रहा था, लेकिन महिला हर बार मिलने से इनकार कर देती थी।

सनातन धर्म की मर्यादा और देश का गौरव वैश्विक स्तर पर बहाल हो सके

श्रीराम मंदिर चंदा चोरी पर संसद के विशेष सत्र में आए कानून, दोषियों को मिले संविधान की कठोरतम सजा: पूर्व विधायक नीरज शर्मा

हरिभूमि न्यूज ▸▸ फरीदाबाद

एनआईटी 86 फरीदाबाद के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में सामने आई अनियमितताओं और चंदा चोरी को लेकर सरकार व प्रबंधन पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने अत्यंत आहत मन से कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर केवल एक पावन परिसर नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में बैठे करोड़ों भारतवंशियों की अटूट आस्था का पावन गर्भगृह है।

नीरज शर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि इतिहास गवाह है कि हमारे पवित्र मंदिरों को बाहरी आक्रांताओं ने लूटा था, लेकिन आज बड़े ही दुख और शर्म की बात है कि कुछ अपनों ने ही इसे लूट का अड्डा बना दिया है। यह चंदा चोरी सिर्फ कोई साधारण वित्तीय हेराफेरी नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म को बदनाम करने की एक गहरी साजिश है, जिससे दुनिया भर में रह रहे सनातनियों के सम्मान को भारी ठेस पहुंची है। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने अपने हालिया विदेशी दौरों का अनुभव सांझा करते हुए कहा कि वह अभी विदेशों में श्रीराम कथा करके लौटे हैं और वहां भी प्रवासी भारतीय इस पूरे घटनाक्रम से बेहद आहत और चिंतित दिखे। फरीदाबाद के ग्रामीण अंचलों और सरपंचों से लेकर सात समंदर पार बैठे भारतवंशियों तक ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपनी गाढ़ी कमाई से दिल खोलकर चंदा दिया था। करीब 20-25 साल पहले आंदोलन के दौरान एकत्रित की गई शिलाओं ईंटों का कोई अता-पता नहीं है अब वर्तमान में चढ़ाए गए सोने, चांदी तथा अरबों रुपए की नकदी का भी कोई पारदर्शी हिसाब नहीं मिल रहा है। निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही पर बोलते हुए जहां सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता और पक्की दीवारें होनी चाहिए थीं आनन-फानन में महज फाइबर की अस्थाई दीवारें खड़ी करके करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का सरेआम मजाक उड़ाया गया है। नीरज शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस महाघोटाले पर लीपापोती करने के बजाय तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR

विज्ञापन सं.: R/05/2026 दिनांक 10 जून 2026
संस्थान निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
(i) पेशेवर प्रशिक्षु (वित्त एवं लेखा)-10 पद
शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अद्यतन जानकारी के लिए
https://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions पर जाएं।
कुलसचिव/ Registrar
CBC-21255/11/0003/2627

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा **82 Cr.PC./84 BNSS** देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त, **मोहसिन, पुत्रः** स्व. कयूम **पताः** म.नं. F-280, शाहीन बाग, बाटला हाउस, नई दिल्ली ने **FIR No.: 85/2021, U/s: 380/411 IPC, थानाः न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **मोहसिन,** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त, **मोहसिन,** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No.: 85/2021, U/s: 380/411 IPC, थानाः न्यू फ्रेन्डस कॉलोनी, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त, **मोहसिन,** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **31.07.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री विनोद जोशी,
अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी,
दक्षिण पूर्व जिला, कमरा नं. 515
साकेत कोर्ट, नई दिल्ली

DP/8638/SE/2026
(Court Matter)

गांव में लाइट, पानी, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप, 40 गांवों का वातावरण हो रहा प्रदूषित

सोतई में कूड़ाघर बनवाकर आईएमटी तथा आसपास के 30 गांवों और रेजिडेंशियल सोसायटियों को नरक बनाना चाहती है भाजपा सरकार : डॉ ऋषिपाल मास्टर

हरिभूमि न्यूज ▸▸ फरीदाबाद

ग्रेटर फरीदाबाद आईएमटी स्थित गांव सोतई आज महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता पंडित प्रेम कौशिक शाहपुर ने की, जबकि मंच संचालन भाई सतपाल तेवतिया ने किया। आज की पंचायत के संयोजक समस्त ग्राम सोतई वासी रहे। कांग्रेस किसान सैल के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता मास्टर ऋषिपाल ने पंचायत को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि सरकार ने पहले तो पृथला विधानसभा क्षेत्र के पांच गांवों को एमसीएफ में विलय किया। उनके सैकड़ों करोड़ एमसीएफ ने अपने खाते में जमा करवा लिए और जबकि विकास के नाम पर सभी गांवों की गलियों, लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था पानी की निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी और गांवों में बुरी तरह से कीचड़ भरे हुए।

अब सरकार पंचायती जमीनों को कूड़ाघर में तब्दील करने जा रही है, जिससे कि इन गांवों का आस-पास की रेजिडेंशियल सोसाइटीज, आईएमटी, आईओसी के रिसर्च सेंटर का और आसपास के करीब 40 गांवों का वातावरण पूरी तरह इतना प्रदूषित हो जाएगा कि लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे, यहां जमीन के रेट घटकर बहुत कम हो जाएंगे और दयालपुर आदि गांवों में जो रेजीडेंसी सोसायटी डवलप होने वाली है वो भी काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। मास्टर ऋषिपाल ने कहा कि पहाड़ों में इतने बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। खनन के बाद जिनको अगर सरकार भरना चाहेगी, कूड़े से तो इसमें करीब करीब दस साल लग जाएंगे तो कूड़े की समस्या का स्थाई समाधान भी हो जाएगा और सरकार उससे जो बात करती है खाद बनाने की वह भी बना सकती है। मास्टर ऋषिपाल ने कहा कि सरकार यदि हमें मारना ही चाहती है तो हम पुलिस की गोली से मरना पसंद करेंगे बजाय इसके कि जहरीला सांस ले लेकर हम डेली मारे और हमारे आने वाली नस्ल, फिर टेडी-मेडी पैदा हो और बर्बाद हो जाए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी हालत में यहां डंपिंग यार्ड नहीं बनने दिया जाएगा। उसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े और कितना भी संघर्ष करना पड़े, इस बात का उपस्थित जनसमूह ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और हर तरीके से संघर्ष का करने का वायदा किया। महापंचायत के अंत में सर्वसम्मति से बहुत ही संघर्षशील और जुझारू युवा साथी डिप्टी रावत को संघर्ष समिति का प्रधान चुना गया। सभी आए हुए गणमान्य सरदार तथा गांव के जिम्मेदार लोग मिलकर संघर्ष समिति के बाकी मेंबर चुनेंगे। इस मौके पर भाजपा नेता भाई विनोद भाटी और अनिल सरपंच बहबलपुर ने लोगों को आश्वस्त किया कि हम सभी को साथ लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बाकी नेताओं को ज्ञापन देंगे और कोशिश करेंगे कि जनता की समस्या का समाधान करवाए जाएं।

खबर संक्षेप

राहुल गांधी 19 जुलाई को करेंगे छात्र संवाद

प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 19 जुलाई को प्रयागराज में संभावित आगमन होगा। राहुल के साथ संसद प्रियंका वाड्रा का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। राहुल यहां 'छात्र संवाद' कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने उनके आगमन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में प्रतियोगी शामिल होंगे।

खान सर मामले में कोर्ट में सौंपी केस डायरी

पटना। बिहार के हाई-प्रोफाइल मामलों में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर व उनके सहकर्मियों से जुड़ी एक खबर पटना सिविल कोर्ट से सामने आई है। शनिवार को अदालत में मामले को लेकर बेहद सरगर्मी तेज रही। कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए कदमकुआं थाना पुलिस व जांच अधिकारी ने मामले की 'अपडेटेड केस डायरी' अदालत के समक्ष सबमिट कर दी है।

'कोल नीर' नाम से पानी बेचेगा बीसीसीएल

धनबाद। बीसीसीएल के पुटकी-बलिहारी कार्यालय परिसर में करीब दो करोड़ की लागत से 'कोल नीर' प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है, निर्माण की प्रगति का जायजा लेने बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने यहां बन रहे बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। तय कार्यक्रम के अनुसार 30 जून को कोयला मंत्री कोल नीर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे।

पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान

मूल्यों व आदर्शों से जुड़ी है भाजपा की शून्य से शिखर तक की यात्रा

भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए संस्थापकों के मूल्य और आदर्श सदैव सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत पार्टी की महानगर इकाई की तरफ से आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रतिभागियों को 'दल से पहले देश' और 'व्यक्ति से पहले समाज' के भाव से अनवरत आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया...

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों और आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। 1985 में मात्र दो लोकसभा सीट हासिल करने वाली इस पार्टी की आज केंद्र सहित देश के 21 राज्यों में सरकार है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है।सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर के गुलरिहा स्थित एक रिजॉर्ट में भाजपा महानगर के प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के अंतर्गत पार्टी की महानगर इकाई की तरफ से आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रतिभागियों को 'दल से पहले देश' और 'व्यक्ति से पहले समाज' के भाव से अनवरत आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से पार्टी के संस्थापकों के आदर्शों और संस्कारों से मिली प्रेरणा है। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उद्धरण, 'बिना मूल्यों और आदर्शों वाली राजनीति मौत का फंदा है' का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए संस्थापकों के मूल्य और आदर्श सदैव सर्वोपरि हैं।

भाजपा सरकार ने वाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मॉडल दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में वाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मॉडल दिया है। 2014 के पहले दुश्मन देश सैनिकों से क्रूरता करते थे। सरकारें तब बोलती नहीं थी, उन्हें देश की कीमत पर संबंध की चिंता रहती थी। 2014 के बाद सरकार ने दुश्मन की आंख में आंख मिलाने का सामर्थ्य दिया है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य और ताकत का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले कश्मीर जल रहा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद चरम पर था, देश के 120 जिलों में नक्सलवाद हावी था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद को कुचल दिया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद समाप्त हो चुका है। नक्सलवाद एक-दो जिलों तक सीमित है और बहुत शीघ्र वहां भी खत्म हो जाएगा।

सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास संभव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास संभव होता है। सुरक्षा का वातावरण बनने के कारण ही आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, हाईवे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, मेट्रो, रोपवे और लॉजिस्टिक के कार्य बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, विकास भी उतनी ही तेजी से होगा।

सीएम योगी ने किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमिपूजन एवं शिलान्यास

6,785 करोड़ का निवेश देगा जेवर क्षेत्र में रोजगार व नए उद्योगों को गति

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ गौतम बुद्ध नगर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर में 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से अंबर एंटरप्राइजेज एवं कोरिया सर्किट्स के ज्वाइंट वेंचर 'एसेंट के सर्किट्स' का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्षेत्र में रोजगार व नए उद्योगों को गति प्रदान करेगा। उन्होंने यूपी के प्रोजेक्ट्स को त्वरित स्वीकृति मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय मंत्रियों का आभार भी प्रकट किया। सीएम ने कहा कि कभी जंगलराज के लिए जाना जाने वाला जेवर क्षेत्र अब मंगलराज की पहचान बना है। मुख्यमंत्री शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 6,785 करोड़ रुपये से अधिक का यह निवेश क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और कई एंकर यूनिट्स की स्थापना में योगदान देगा। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई गति देगा। उत्तर प्रदेश पहले ही एमएसएमई का सबसे बड़ा हब है, जहां लगभग 96 लाख इकाइयां कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से शुरू हुई 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' योजना ने प्रदेश के उत्पादों को देश व दुनिया में नई पहचान दिलाई है।

सेमीकंडक्टर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत

देश के 55% मोबाइल नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बन रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। देश में बनने वाले 55 प्रतिशत मोबाइल फोन नोएडा-ग्रेटर नोएडा में निर्मित हो रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का भी 55 से 60 प्रतिशत उत्पादन यहीं हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अंबर ग्रुप और कोरिया सर्किट का यह संयुक्त उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा और उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत को नई उड़ान देगा।

केंद्र से यूपी के प्रोजेक्ट्स को मिलती है त्वरित स्वीकृति

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी प्रस्ताव को केंद्र सरकार में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचते ही सूचना मिल जाती है कि उसे अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और आप कार्य को आगे बढ़ाएं। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। जब अपनत्व का भाव हो, देश के प्रति जज्बा हो, तब ये चीजें देखने को मिलती हैं। मैं इस स्वीकृति के लिए पीएम मोदी जी व केंद्रीय मंत्रियों का आभार प्रकट करता हूं।

कोरिया से उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक व आत्मीय संबंध

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कोरिया से बहुत पुराना संबंध है। इतिहास में यह मान्यता है कि कोरिया की रानी क्वीन हो वस्तुतः अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थीं, जो जलमार्ग से कोरिया पहुंची थीं। कोरिया की प्रथम महिला के उत्तर प्रदेश आगमन पर अयोध्या में एक पार्क का निर्माण कराया गया था। कोरिया के राजदूत भी अयोध्या आए थे और उस ऐतिहासिक संबंध को स्मरण करते हुए भावुक हुए थे। यही आत्मीय संबंध भारत व कोरिया को और अधिक निकट लाता है। कोरिया इस बात का उदाहरण है कि आक्रामक रणनीति, अनुशासन और समर्पण के बल पर कोई देश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बन सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था नए प्रतिमान स्थापित कर रही है।

निशांत ने किया पीएमसीएच का औचक निरीक्षण

एक प्रशासनिक कार्रवाई ने मंत्री की कार्यशैली को लेकर नई बहस छेड़ दी

एजेंसी ▶▶ पटना

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी देहभाषा को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अब एक अलग वजह से चर्चा में हैं। पीएमसीएच के औचक निरीक्षण और उसके बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने उनकी कार्यशैली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता की सराहना हो रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानांतरण को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है।

पीएमसीएच पहुंचकर मरीजों से सीधे की बातचीत

23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव कुमार रवि के साथ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्डों का जायजा लिया और मरीजों व उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने इलाज, दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता को लेकर लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं।

मुफ्त दवा और इलाज को लेकर मिली शिकायतें

निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि सरकारी सूची में शामिल कई दवाएं मुफ्त में उपलब्ध नहीं हो रही हैं। साथ ही कुछ डॉक्टरों द्वारा इलाज और देखरेख में लापरवाही बरतने की भी शिकायत की गई। निशांत कुमार ने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए।

प्राचार्य की अनुपस्थिति के बाद हुआ तबादला

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह को बुलाने के लिए कहा, लेकिन जानकारी मिली कि वे अस्पताल नहीं आए हैं। मोबाइल पर भी उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अगले ही दिन डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह का तबादला बेतिया मेडिकल कॉलेज कर दिया गया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

फेसबुक पर हुई थी दोस्ती

युवती से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने बंधक बनाकर पीटा

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ लखनऊ

फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक युवती से मिलने पहुंचे युवक को परिजन और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद बंधक बनाकर पिटाई की गई। बाद में पुलिस युवक और युवती को थाने ले गई। यहां पूछताछ की जा रही है।

गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह गांव के मजरे जैतपुर निवासी उमेश कुमार की दोस्ती खखरेरू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से फेसबुक पर हुई थी। वह शनिवार दोपहर युवती से मिलने चौराहे पर पहुंचा। तभी युवती के अचानक गायब होने पर परिजन उसकी तलाश में जुट गए। खोजबीन के दौरान परिजन ने शाम करीब चार बजे दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद परिजन व ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी और टिन शेड के नीचे बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि दोनों के परिजन को बुलाया गया है और पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।

लगातार दूसरे दिन सीएम योगी ने सुनीं लोगों की समस्याएं

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय भरोसा देते हुए कहा कि जरूरतमंदों के इलाज और मकान की व्यवस्था सरकार कराएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी होना चाहिए। सीएम ने लोगों से कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी निस्तारण के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाएं। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा में भी रमे रहे। उन्होंने स्नेहिल थपकी देकर गायों-गोवंश को खूब दुलारा। गुड़-रोटी खिलाया और गोशाला के कार्यकर्ताओं को गोवंश के समुचित देखभाल के निर्देश दिए।

---

2 आंगनबाड़ी केंद्र व स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन

प्रारंभिक शिक्षा, पोषण और संस्कार से बनेगा बच्चों का उज्ज्वल भविष्य

हरिभूमि न्यूज़ ▶▶ अयोध्या

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को अयोध्या धाम में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने बाल वाटिका का निरीक्षण कर बच्चों से संवाद किया तथा फल-मिष्ठान वितरित किए। रसोईघर का निरीक्षण करते हुए मिड-डे मील की गुणवत्ता भी परखी। राज्यपाल ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम संस्कार और संतुलित पोषण से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं संस्कारित समाज की नींव गर्भकाल से ही रखी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक गर्भवती महिला का अस्पताल में पंजीकरण और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही अभिभावकों से तीन वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकन कराने तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की अपील की।

पेज एक का शेष

राम मंदिर में ...

सीईओ की भी नियुक्ति हो सकती है। तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर व्यवस्था को लागू किए जाने की चर्चा चल रही है। सीईओ की नियुक्ति से मंदिर में आने वाले पैसों और दान की राशि का उचित प्रबंधन किया जाएगा। अभी ट्रस्ट के स्तर पर ही वित्तीय प्रबंधन चल रहा था। इस कारण दान राशि में चोरी के मामले सामने आए। नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया जा सकता है। राम मंदिर परिसर में सीईओ का पद राम मंदिर ट्रस्ट के अधीन होगा।

दोषियों को बख्शा ...

कहा कि पूरे मामले के तथ्य सामने आने चाहिए। इस बीच, अयोध्या के रामलला की प्रतिमा के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भी पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आरोपों की सच्चाई जल्द सामने आनी चाहिए और श्रद्धालुओं की आस्था की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कुछ भी गलत हुआ है तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और दोषियों को कड़ी सजा मिले।

194 साल के ...

उसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है और सूंघने की क्षमता भी कमजोर हुई है, लेकिन फिर भी वह सामान्य जीवन जी रहा है। जोनाथन सिर्फ एक दुर्लभ जीव नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता और विरासत का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पीएम मोदी और जोनाथन की यह मुलाकात भारत और सेशेल्स के बीच पर्यावरण संरक्षण और साझा प्राकृतिक धरोहर के संदेश को भी दुनिया के सामने रखने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान विशालकाय कछुए को अपने हाथों से पत्तियां व हरी घास खिलाई। यह घटना सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में स्थित सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन में हुई। यहां पीएम मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ जोनाथन से मुलाकात की। इस खास पल और यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए दोनों नेताओं ने बॉटनिकल गार्डन में एक पेड़ भी लगाया।

अब हर घर तक पहुंच ...

की टैक्सी सेवाओं में कई तरह की दिक्कतें उभर कर सामने आ रही थीं, जिससे परेशान होकर आम जनता और ड्राइवर्स दोनों ने ही उनसे मुलाकात कर समाधान की उम्मीद जताई थी। इसी वजह से एक नए सहकारी ढांचे को विकसित करने का निर्णय लिया गया।

इससे शोषणमुक्त ...

कानून बना देना किसी भी समस्या का 100 प्रतिशत समाधान नहीं हो सकता। यही कारण है कि सिर्फ कानूनी बंदिशों पर निर्भर रहने के बजाय सरकार ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल तलाशने का फैसला किया जो बुनियादी रूप से ही शोषण से मुक्त हो।

महाराष्ट्र में एग्जाम ...

विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही विभाग की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी भी जल्द ही दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (एमएससीई) की ओर से ये परीक्षा आयोजित की गई थी। अब पुलिस द्वारा जांच करते हुआ यह पता लगाया जा रहा है कि प्रश्न-पत्र लीक कैसे हुआ। साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में और भी लोग शामिल थे।

पिछले 24 घंटों में देश ...

घंटों में पाकिस्तान में भी भूकंप के चार झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे तेज झटका 5.5 तीव्रता का था। सबसे तेज भूकंप शनिवार सुबह 8:36 बजे आया। इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई, जो जमीन से 40 किलोमीटर की गहराई पर आया था। केंद्र पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में था। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है।

रीवा के किसान...

से प्राप्त किए गए। स्थानीय बाजार में सुंदरजा आम का भाव लगभग 100 से 110 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि निर्यातक ने इसे 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा।

कहीं भी गंदगी ...

वन विभाग द्वारा फूलदार एवं आकर्षक पौधों का रोपण कराया जाए।

कचरा संग्रहण वाहनों को जीपीएस से जोड़े

उन्होंने निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों को जीपीएस प्रणाली से जोड़ा जाए, ताकि उनकी नियमित निगरानी की जा सके। वाहनों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों में वार्ड समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक तीन माह में वार्ड समितियों के साथ बैठक आयोजित की जाए तथा समय-समय पर उनके साथ वर्चुअल संवाद भी किया जाए।

वार्ड समितियों...

निकायों की स्वच्छता एवं कार्यप्रणाली की रैंकिंग करें। प्रत्येक नगर निगम अपने वार्डों की भी रैंकिंग तैयार करे तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वार्डों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने नगर निगमों एवं नगरपालिकाओं को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आवश्यकताओं एवं आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ही स्वच्छता कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए।

ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी

बिहार में 1 जुलाई से लागू होगी वीबी-जी राम जी योजना

- 15 दिन में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य

एजेंसी ▶▶ सिवान

जिले में ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और गांवों में टिकाऊ विकास कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी राम-जी 2025) लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण श्रमिकों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस संबंध में मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, आजीविका संवर्धन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले कार्य, रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही पंचायतों को चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बोआई और कटाई के चरम मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी करेगी। इस अवधि में योजना के तहत कार्य नहीं कराया जाएगा।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी

योजना के वित्तीय प्रावधान के अनुसार, केंद्र प्रायोजित इस योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमिट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी आधारित योजना निर्माण, डिजिटल मानिटरिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासा, मजबूत सामाजिक अंकेक्षण जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम और योजना संबंधित कार्यों में आएगी पारदर्शिता

डीपीओ ने बताया कि योजना के लागू हो जाने से बिचौलियों का भूमिका खत्म हो जाएगा। योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण से फर्जी हाजिरी और फर्जी भुगतान पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा सेटेलाइट और मैपिंग आधारित योजना निर्माण होगा, इससे केवल जरूरी और वास्तविक काम ही जमीन पर होंगे। हर हफ्ते काम और भुगतान का ब्योरा सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके।

मन-जीवन को कर रहा अशांत
सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस

स्पेशल: वर्ल्ड सोशल मीडिया-डे, 30 जून

आज के दौर में अधिकांश लोग किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन हाल के सालों में देखने में आ रहा है कि इन पर दिन में कई-कई बार आने वाले नोटिफिकेशंस से लोगों का मन-जीवन बेचैन और अशांत होता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजहें हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है और इनसे कैसे बच सकते हैं, आपको जरूर जानना चाहिए।

कवर स्टोरी / डॉ. मोनिका शर्मा

कभी किसी परिचित के सुंदर घर की तस्वीर तो कभी किसी फ्रेंड के विदेश घूम आने के अपडेट, वर्चुअल दुनिया में जुड़े किसी अनजान वर्चुअल मित्र ने अचानक अपना लुक बदल लिया, तो किसी के बच्चों की कमाल की उपलब्धियां। सब कुछ स्क्रीन के जरिए हम तक पहुंचता रहता है। हर उम्र के लोगों में लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट रहने और दूसरों को अपडेट करने की सोच बढ़ रही है। इस वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशन की टोन कई बार मन को बेचैन करने वाली दस्तक-सी लगने लगती है। दूसरों के लुक्स, करियर, महंगे शौक और एडवेंचरस ट्रिप्स को देखकर मन में कमतरी के भाव आने लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी के भी जीवन की हकीकत इतनी सुंदर-सहज नहीं होती है, जितनी सोशल मीडिया पर दिखती है। ऐसे में बनावटी-सजावटी आभासी दुनिया के बहकावे में आने के बजाय अपने मन-जीवन को साधना जरूरी है।

बढ़ने लगी है तुलनात्मक प्रवृत्ति

आज के दौर में स्क्रीन के जरिए दस्तक देता कंटेंट, हर उम्र के लोगों को कमतरी और बेहतरी के जाल में उलझा रहा है। शुभ कार्य हों या कोई व्यक्तिगत उपलब्धि, आभासी दुनिया में अजीब से नाप-तौल वाले मनोभावों से देखी, समझी और स्वीकारी जाने लगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर फैमिली ग्रुप्स में शेयर की जाने वाली सूचनाओं और क्लिक्स तक, हर बात और जज्बात तुलना करने की सोच की ओर धकेल रहा है। इसके चलते मन में आने वाली अनचाही तल्खी, व्यावहारिक जिंदगी की भरपूर समझ होने के बावजूद, दिलो-दिमाग को बोझिल कर रही है। सुंदरता, सहृदयता और संपन्नता की जो चमक स्क्रीन पर तैरते अपडेट्स में दिखती है, वही जीवन का सच नहीं है, यह जानते-बूझते हुए भी रंग-रूप, कद-काठी और उपलब्धियों से लेकर खुशियों और उत्सवीय रंग-ढंग तक एक असंतोष की भावना पनप रही है। ध्यान रहे कि सोशल मीडिया के जरिए क्लिक भर में आप तक पहुंच जाने वाले कंटेंट से तुलना का भाव स्वयं यूजर्स में तो बढ़ ही रहा है। बाजार ने भी इसे बढ़ाया है क्योंकि यह भी एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है।

गहरा होता है कमतरी का भाव

जाने-अनजाने लोगों के अपडेट्स देखकर पैदा हो रहा तुलना का भाव, खुद के जीवन में कमियां देखने को प्रेरित कर रहा है। इसके चलते हमारा मन रिश्तों, जीवनशैली और अपने हिस्से आए स्नेह-सम्मान की भी अनदेखी करने लगता है। नतीजतन जिंदगी की नेमतों को लेकर शुक्रिया कहने के भाव की जगह शिकायतों ने ले ली है। नोटिफिकेशन टोन के साथ पल-पल में अवतरित

होते संदेश, सूचनाएं, चित्र, असंतुष्टि भरी सोच और बेचैनी भी साथ लाते हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि वर्चुअल दुनिया में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दूसरे जाने-अनजाने चेहरों के अपडेट्स हर उम्र के लोगों के लिए व्यक्तिगत जीवन में असंतुष्टि की बड़ी वजह बन रहे हैं। स्मार्ट गैजेट्स की स्क्रीन के जरिए अमूमन अपनों-परायों तक अपनी कमियां, कमजोरियां और दिल की कसक नहीं पहुंचाई जाती। यह जानते-समझते हुए भी दूसरों के चमकदार, सफल और सुखी दिखते जीवन की वर्चुअल आभा में खुद को कहीं कमतर महसूस करने का भाव पनपने लगता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक आमतौर पर सोशल मीडिया पर लोग अपने बारे में सकारात्मक जानकारी ही प्रस्तुत करते हैं। फिल्टर्स का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को और प्रभावी बना देते हैं। इसके चलते यह लगने लगता है कि हमारे मित्र या संबंधी कितने सुंदर हैं! कितने सफल हैं! इससे कई बार ऐसा भी लगने लगता है कि हमारे अलावा सब के पास सब कुछ है, सब बहुत खुश और संतुष्ट हैं, जबकि यह एक आभासी सोच भर होती है।

खो रहीं सहज-सी खुशियां

लगातार मिलने वाले सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस के जरिए इंसानी व्यवहार और विचार में चाहे-अनचाहे स्क्रीन पर दिखी तस्वीरों, सूचनाओं और उपलब्धियों का ही लेखा-जोखा रहने लगता है। ऐसे में हम उस सुख को भी भूल जाते हैं, जो हमारी झोली में मौजूद होते हैं। इसकी वजह यह भी है कि वास्तविक दुनिया में तुलना करने के दायरे में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। सोशल मीडिया का डिजिटल यूनिवर्स, दूसरों के साथ तुलना करने की स्थितियों को कई गुना बढ़ा देता है। समझना जरूरी है कि दूसरों की जिंदगी के वर्चुअल अपडेट्स में दिखने और होने के फर्क को समझते हुए अपने जीवन की सहजता को बनाए रखिए। अपनी खुशियों को जीने से दूरी मत बनाइए। *

सही नहीं सबका पीछा करना

दूसरों के मीडिया अपडेट्स के चलते मन में आ रही खिन्नता लोगों को उनका फॉलोअर बना देती है। हम हरदम यह जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके ताजा अपडेट्स क्या हैं? आज उनकी क्या गतिविधियां हैं? अन्य लोग उनकी कैसे और कितनी सराहना कर रहे हैं? दूर बैठे लोगों की जिंदगी का पीछा करने की सोच से ऐसी बातों के चलते खुद आपके जज्बात बदलने लगते हैं। मन-जीवन में असंतोष भरी स्याह उदासी जगह बना लेती है। यहां तक कि ईर्ष्या का भाव भी पनपने लगता है। सोचने वाली बात यह है कि यह सब होने की कोई वास्तविक वजह ही नहीं होती है। सोच-समझकर दी गई जानकारियां और बना-संवारकर साझा की गई तस्वीरें लोगों को हैरान-परेशान करती हैं, जबकि खुद उनके ही द्वारा साझा की जा रही सामग्री के इतर उनके जीवन की असलियत का दूसरों को कोई अंदाजा ही नहीं। ऐसे में यह आदत बेवजह आपकी ऊर्जा और समय खपाने लगती है। सोशल मीडिया का उपयोग यूजर्स जिस इरादे से करते हैं, उनके मन-मस्तिष्क पर वैसा ही असर पड़ता है। बिना सोचे-समझे दूसरों के अपडेट्स के इंतजार में स्क्रीन स्क्रॉल करने से अवसाद और घबराहट पैदा होती है। जिन लोगों के अपडेट्स मन में भटकाव या नकारात्मक भाव लाते हैं, उन्हें अनफॉलो कीजिए। चिंतित और उदास महसूस करवाने वाले कंटेंट से दूरी बनाएं। वर्चुअल दुनिया हो या असल संसार औरों से ज्यादा अपनी जिंदगी में रुचि रखिए।

भारत के सरकारी स्पेस इंस्टीट्यूट इसरो की उपलब्धियां तो जगजाहिर हैं ही, अब इसी के नक्शेकदम पर चलते हुए कई स्पेसटेक निजी कंपनियां भी देश-दुनिया में अपनी धाक जमा रही हैं। स्पेसटेक के क्षेत्र में नित नई ऊंचाई हासिल कर रही देश की प्राइवेट स्पेसटेक कंपनियों की अचीवमेंट पर एक नजर।

अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहीं देश की निजी स्पेसटेक कंपनियां

अचीवमेंट
संजय श्रीवास्तव

हाल में 'गैलेक्सआई' द्वारा मिशन दृष्टि नामक दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद दुनिया भर की मीडिया में भारत की निजी स्पेस कंपनियों की कम लागत के साथ तकनीकी दक्षता तथा इस आधार पर वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में उनकी तीव्र बढ़त की चर्चा हो रही है।

गैलेक्सआई ने रचा इतिहास: जब भारत ने 'मिशन दृष्टि' के तहत 190 किलो वजनी दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया, तब बहुतों ने गैलेक्सआई का नाम पहली बार सुना। देश ने स्पेस तकनीकी क्षमता का लोहा वैश्विक स्तर पर मनवाया हो और खबरों में इसरो की जगह देश के सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बनाने वाली किसी ऐसी निजी कंपनी का नाम सुर्खियों में शामिल हो, जिसके अस्तित्व में आए महज पांच साल हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतने कम समय में यह अनूठी सफलता हासिल कर इसने बता दिया है कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति कितनी तेज गति से हो रही है।

बहुपयोगी है इसकी तकनीक: गैलेक्सआई द्वारा लांच मिशन दृष्टि की ऑप्टोसार तकनीक में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल यानी ईओ और सिंथेटिक, पर्चर रडार या एसएआर सेंसर को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। इस संयोजन के कारण यह उपग्रह हर मौसम और दिन-रात में डेटा संग्रह करने में सक्षम है। यह क्षमता अब तक सीमित देशों या अलग-अलग प्रणालियों में बंटी हुई थी, जबकि भारत ने इसे एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो अमेरिका, चीन और कुछ यूरोपीय देश पृथ्वी अवलोकन में अग्रणी रहे हैं, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से 'गेम चेंजर' ऑप्टोसार तकनीक जैसी एकीकृत प्रणाली भारत को तकनीकी बढ़त देती है। यह उपग्रह सेना को डेढ़ मीटर के दायरे में सीमा पार की सटीक जानकारी देगा। कृषि मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता व्यापक है। बाढ़ या चक्रवात के समय यह त्वरित और सटीक डेटा निर्णय लेने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इस प्रकार 'मिशन दृष्टि' ड्यूल-यूज टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे नागरिक और सैन्य दोनों लाभ एक साथ प्राप्त होंगे।

कई और कंपनियां भी हैं एक्टिव: गैलेक्सआई तो महज एक उदाहरण है, देश में इसरो के साथ मिलकर काम करने वाली कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी है। अनुमान है कि फिलवक्त निजी क्षेत्र में 400 स्पेसटेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। 150 से ज्यादा कंपनियां छोटे उपग्रह, लॉन्च व्हीकल्स, अर्थ ऑब्जर्वर और एआई एनालिटिक्स आदि पर शानदार काम कर रही हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस, जिसने निजी क्षेत्र का पहला सफल रॉकेट विक्रम एस. बनाया और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग में वैश्विक पहचान बनाने वाली पिक्सेल कंपनी से सभी परिचित हैं। अग्निकुल कॉस्मॉस, जो थ्री-डी प्रिंटेड इंजन अग्निलेट का निर्माण कर सुर्खियों में आई थी, अब उपग्रहों के लिए स्पेसएक्स की स्पेस बस की अवधारणा से उलट एक स्पेस 'टैक्सी' बनाना चाहती है। थ्री-डी प्रिंटरों का उपयोग करके, यह फॉलकन 9 से छोटे और दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने की सोच रहा है, जिन्हें ग्राहक की इच्छानुसार कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और उनके उपग्रह को ठीक उसी कक्षा में सटीकता से स्थापित किया जा सकता है, जिसकी उसे जरूरत है। मुमकिन है कि इस साल के अंत तक वह लक्ष्य पा लें। दिगांत्रा कंपनी एक कक्षीय हवाई-यातायात नियंत्रक के रूप में काम कर रही है, जो विभिन्न कंपनियों के उपग्रहों के अंतरिक्ष मलबे से टकराने के जोखिम की निगरानी में मदद करती है।

हो रहा वैश्विक प्रसार: देश की ये स्पेसटेक कंपनियां देश से बाहर भी अपनी धाक जमा रही हैं। आज पिक्सेल नासा के साथ डेटा साझेदारी कर रही है, तो स्काईरूट अंतरराष्ट्रीय ग्राहक लॉन्च सेवाएं दे रही है और ध्रुव स्पेस ग्लोबल सैटेलाइट सेवाओं में आगे है। इसी तरह तमाम निजी स्पेस कंपनियां विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही हैं यानी शोधरत हैं। भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियों की बढ़ती प्रसिद्धि के पीछे कारण यह है कि भारतीय स्पेसटेक कंपनियों का मॉडल 'कम लागत पर उच्च-दक्षता नवाचार' पर आधारित है। स्पेस टेक की दिशा में भारत अब 'सेवा प्रदाता' से 'तकनीक प्रदाता' बन रहा है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि भारतीय स्पेसटेक व्यापार 2030 तक 40 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। *

गजल
डॉ. माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग'

भूल गए हैं लोग सलीका

भूल गए हैं लोग सलीका आमंत्रण का,
भाव नहीं दिखता आंखों में अपनेपन का।
भरमाने वाले पेड़ों की भीड़ लगी है,
मोल नहीं होता कानन में अब चंदन का।
याद किसी की आने पर सर दीवारों से
टकराए तो दोष नहीं होता दरपन का।
इकदिन उम्र ढला करती है सबकी जग में,
धीरे-धीरे रंग उतरता है आनन का।
साथ न हो गर मन का मीत सफर में 'नवरंग'
लगने लगता है हर मौसम फिर बेमन का।

व्यंग्य / सूर्यदीप कुशवाहा

मेहमान इन पकवानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे इसके बाद कभी उन्हें खाना मिलेगा ही नहीं। एक तरफ मेहमान पकवान उड़ाते हैं, उधर लड़की के बाप का बीपी बढ़ता जाता है।

शादी का झमेला

आजकल समाज में शादी-ब्याह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों के बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा और धैर्य की परीक्षा का महायज्ञ बन गया है। यह वह अवसर होता है, जब एक अदना-सा इंसान अचानक शादी समारोह प्रबंधक बन जाता है और अपनी सारी जमापूंजी, साख और यहां तक कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए रखी गई पूंजी भी एक रात के दिखावे में झोंक देता है।

समारोह में दुल्हन को इतना पेंट किया जाता है कि पेंट किया हुआ घर भी फीका दिखने लगता है। चेहरे पर पुताई की इतनी परतें होती हैं कि अगर दुल्हन को छींक आ जाए, तो आस-पास के लोग उस गुबार से लाल हो जाएं। इसे ब्राइडल ग्लो कहा जाता है, जो सुबह होते ही वॉटरप्रूफ न होने की स्थिति में बह जाता है। आम धारणा है कि दुल्हन का लहंगा भी उतना ही भारी होना चाहिए, जितना दुल्हन के पिता का सिर कर्ज के बोझ से भारी हो जाता है।

शादी समारोह अब रिश्तों का उत्सव कम और कॉम्पिटिशन ज्यादा बन गया है। पड़ोसी की बेटी की शादी में पचास पकवान थे, तो हमें शुभ इक्यावन करने ही होंगे। चाहे इसके लिए पिता को क्यों न बैंक से लोन लेना पड़े। लगन के इस मौसम में सबसे ज्यादा प्रभाव उस मध्यमवर्गीय पिता पर होता है, जो तीन घंटे के दिखावे के लिए तीस साल की कमाई स्वाहा कर देता है। मेहमानों को खिलाने के लिए मेनू में तरह-तरह के व्यंजन होते हैं, जिसमें से अधिकतर मेहमान केवल वही स्पेशल डिश खाते हैं, जो उनके घर में नहीं बनते हैं। मेहमान इन पकवानों पर ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे इसके बाद कभी उन्हें खाना मिलेगा ही नहीं। एक तरफ मेहमान पकवान उड़ाते हैं, उधर लड़की के बाप का बीपी बढ़ता जाता है। यह ऐसा मेला है, जहां रिश्तेदार यह देखने आते हैं कि हलवाई ने पनीर की सब्जी में पनीर डाला था या सिर्फ ग्रेवी? वास्तव में शादी में आए मेहमानों का मुख्य उद्देश्य दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देना नहीं, बल्कि समारोह में कमियां उघाड़ना होता है। बिना बात नाराज होने वाले दूल्हे के फूफाजी अगर पनीर के चार टुकड़े खा लें तो यह उनकी दयालुता मानी जाती है। ये वही लोग होते हैं, जो अपनी बेटी की शादी में सबसे कंजूसी करते हैं, लेकिन दूसरे की शादी में फाइव स्टार होटल जैसी सुविधा चाहते हैं। इनके लिए शादी एक फ्री फूड फेस्टिवल होता है, जहां वे वीआईपी बन अपनी पसंद का खाना न मिलने पर दुल्हन के पिता को कोस और लताड़ सकते हैं। लेकिन समारोह का असली मजा या सजा सड़क पर बारात के रूप में मिलता है। डीजे वाले बाबू चाहे कैसा भी गाना बजाएं, बारातियों को तो बस वही एक स्टेप आता है-नागिन डांस। ऐसा लगता है जैसे सांपों ने पूरी बारात को डस लिया हो। दूल्हा घोड़ी पर बैठा ऐसे मुस्कुराता है, जैसे उसने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता हो, जबकि सच्चाई यह है कि वह कुछ ही देर में स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर कदम बढ़ाने वाला होता है।

हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार हो। शायद इसीलिए आज के दौर में शादी समारोह समाज के सामने अपनी औकात बताने का एक जरिया बन गया है। शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन शान से नई कार में घूमते हैं और पीछे दुल्हन के पिता उस कार की ईएमआई भरते हैं। इसे ही लड़की का बाप कहते हैं। *

पुस्तक चर्चा / मेनका त्रिपाठी

संवेदना-संघर्ष का कथालोक

हाल में प्रकाशित हुआ विक्रम सिंह का कहानी-संग्रह 'आवारा अदाकार' समकालीन जीवन की जटिलताओं, विडंबनाओं और मानवीय संघर्षों के दस्तावेज की तरह है। उनकी कहानियों में एक ओर यथार्थ की खुरदुरी जमीन दिखाई देती है, तो दूसरी ओर कल्पना की ऐसी ऊंचाई भी, जो साधारण जीवन को अर्थपूर्ण बना देती है। यही कारण है कि उनकी कहानियां केवल घटनाओं का विवरण नहीं लगतीं, बल्कि पाठक के भीतर संवेदना और विचार दोनों को जगाती हैं।

लेखक ने खाड़ी देशों में संघर्षरत मजदूरों की पीड़ा, कोरोना काल की त्रासदी, बेरोजगार युवाओं की बेचैनी, इंटरनेट ठगी और आभासी रिश्तों के खोखलेपन जैसे समकालीन विषयों को अत्यंत संवेदनशीलता से उठाया है। वे केवल दुख की दास्तां नहीं सुनाते, बल्कि जीवन की कठोर परिस्थितियों के बीच मनुष्य की जिजीविषा और छोटे-छोटे सुखों की तलाश को भी रेखांकित करते हैं। उनकी भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और आज के जीवन के जीवंत मुहावरों से भरपूर है। संवादों में स्वाभाविकता है, जिससे पात्र पाठक के बेहद करीब आ जाते हैं। हालांकि, विविध विषयों के कारण कहीं-कहीं कथ्य का हल्का बिखराव दिखाई देता है, फिर भी उनकी रचनात्मक ईमानदारी और मानवीय दृष्टि इस कमी को ढंक लेती है। *

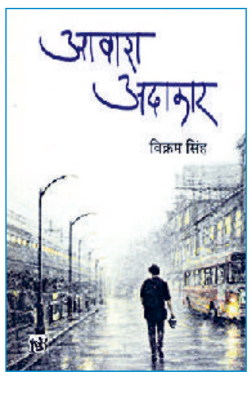

पुस्तक: आवारा अदाकार (कहानी संग्रह), **लेखक:** विक्रम सिंह,
मूल्य: 250 रुपए, **प्रकाशक:** लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज

खबर संक्षेप

नए कानून क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आज

भोपाल। भारत सरकार की ओर से लागू नवीन आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों (पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, कारागार एवं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला) के मध्य डिजिटल समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए (आईसीजेएस) के तहत एक राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविवार 28 जून को सुबह 9.30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार (मिंटो हॉल), भोपाल में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा विभिन्न जिलों के माननीय न्यायाधीश, मेडिकल आफिसर्स, अभियोजन, कारागार तथा फोरेंसिक साइंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहभागिता करेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य नवीन आपराधिक कानूनों की डिजिटल रूप से प्रभावी क्रियान्वयन रणनीतियों पर विमर्श करना एवं सभी स्तंभों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

संयुक्त संचालक स्तर के अफसरों के हुए तबादले

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया जारी है। विभाग ने संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इसके साथ ही विभाग ने 10 प्राचार्यों के तबादला आदेश भी जारी किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से अरविंद सिंह को संयुक्त संचालक, ग्वालियर से लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, महेश पांडवा को प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिंदवाड़ा से प्रभारी संयुक्त संचालक (विधि प्रकोष्ठ), लोक शिक्षण जबलपुर, अरुण इगले को संयुक्त संचालक, जबलपुर से प्रभारी संयुक्त संचालक, नर्मदापुरम, प्रियांशु शर्मा को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, नटेरन (विदिशा) से लोक शिक्षण संचालनालय सहित अन्य अधिकारियों के आदेश जारी हुए हैं।

वन कर्मचारी पर हमला करने पर लगाएं रासुका

भोपाल। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर राजगढ़ वन मडल के वन कर्मचारी के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले वन माफिया को तत्काल गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई करने की मांग की है। मंच के प्रदेशाध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राजगढ़ वन मंडल के सुठालिया वन क्षेत्र में सागौन की तस्करी करने वाले वन माफिया को पकड़ने गई वन कर्मचारियों की टीम के ऊपर वन माफिया ने फायरिंग कर हथियारों से प्राण घातक हमला कर दिया।

शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 20 लाख ठगे

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। भारत सरकार के उपक्रम IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड में कार्यरत सीनियर रेलवे मैनेजर कुंदन कुमार से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर 20 लाख 70 हजार रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर गौरेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, कुंदन कुमार मूल रूप से पटना (बिहार) के निवासी हैं और वर्तमान में डुमरिहा, गौरेला में रहकर गेवरारोड से पेण्ड्रारोड नई रेल लाइन परियोजना में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।

सूचना

सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

पिता पर भी किया हमला, पैर टूटा, हाथ व शरीर पर आईं गंभीर चोटें

दिव्यांग बेटे ने संपत्ति विवाद के चलते लाठी मारकर मां को उतारा मौत के घाट

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

जमीन के बंटवारे को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम चीतापाली में शुक्रवार देर रात एक दिव्यांग बेटे ने अपनी ही मां की लाठी मारकर हत्या कर दी और पिता पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उरगा थाना प्रभारी एसआई नवीन पटेल से मिली जानकारी के अनुसार चीतापाली निवासी श्याम लाल यादव के दो बेटे हैं।

बड़ा बेटा पत्नी-बच्चों के साथ कोरबा शहर में रहता है। घर में श्याम लाल, उनकी पत्नी जानकुंवर और छोटा बेटा रामकुमार यादव रहते थे। रामकुमार दिव्यांग है और लाठी के सहारे चलता है। वह लंबे समय से जमीन का बंटवारा चाह रहा था, लेकिन माता-पिता अभी बंटवारा नहीं करना चाहते थे। शुक्रवार रात करीब 9-10 बजे रामकुमार ने फिर से बंटवारे की बात उठाई। मना करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गुस्से में आकर रामकुमार ने लाठी से मां जानकुंवर के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर चोट से जानकुंवर की मौके पर ही मौत हो गई। इतने से भी मन नहीं भरने पर आरोपी ने पिता श्याम लाल पर भी लाठी बरसाई, जिससे उनका एक पैर टूट गया और हाथ व शरीर पर कई चोटें आईं। वारदात को अंजाम देने के बाद रामकुमार घर से फरार हो गया। रातभर मां का शव घर में पड़ा रहा। शनिवार सुबह घटना की सूचना उरगा पुलिस को मिली। थाना प्रभारी नवीन पटेल तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल श्याम लाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे ग्राम अंजोरीपाली से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रामकुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी माता-पिता से मारपीट कर चुका है। उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर रिमांड पर भेजने की तैयारी की जा रही है।

कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूमोड़ के पास की घटना

दो तेज रफ्तार ट्रालों में जोरदार टक्कर एक चालक की मौके पर दर्दनाक मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कोरबा

शनिवार की सुबह कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूमोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां दो तेज रफ्तार ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह के समय हुआ जब दोनों ट्रेलर तेज गति से एक-दूसरे की ओर आ रहे थे।

नियंत्रण खोने के कारण आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रेलर का चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शव केबिन के अंदर इस कदर फंस गया था कि उसे निकालने के लिए कटर का सहारा लेना पड़ा। दूसरा ट्रेलर चालक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस अब फरार ट्रेलर और चालक की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ कर वाहन की पहचान की जा रही है।

पुलिस ने तेज की अन्य फरार ड्राइवर की तलाश

सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर कटर की मदद से ट्रेलर की केबिन काटी और चालक के शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान की पुष्टि की जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों और वाहन मालिक को हादसे की सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। फरार ट्रेलर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हिट एंड रन का मामला दर्ज किया जाएगा। वाहन के नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है।

अवैध कॉलोनाइजरों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान

नया कॉलोनी कानून तैयार, 5 साल में विकास कार्य नहीं तो लाइसेंस रद्द

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया मसौदा | ड्राफ्ट को वरिष्ठ सचिव समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा

मध्यप्रदेश में अवैध और अनाधिकृत कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम-2026 का मसौदा तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट को जल्द ही वरिष्ठ सचिव समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नए कानून में कॉलोनाइजरों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि कॉलोनी की अनुमति लेने के बाद तय समय में विकास कार्य पूरे नहीं किए गए तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

वहीं अवैध कॉलोनियां बसाने वालों को 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, किसी भी कॉलोनाइजर को कॉलोनी की अनुमति मिलने के बाद पांच वर्ष के भीतर सड़क, पेयजल, बिजली, सीवरेज और अन्य आंतरिक विकास कार्य पूरे करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों में नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) अधिकतम दो वर्ष का अतिरिक्त समय दे सकेंगे। यदि अनुमति लेने के बाद भी कॉलोनाइजर कॉलोनी विकसित नहीं करता, तो उसे एक वर्ष के भीतर अपना लाइसेंस निरस्त कराना होगा। नया अधिनियम शासकीय कॉलोनियों के अलावा भोपाल, महू, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के सातों कंटोनमेंट क्षेत्रों में भी लागू होगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कॉलोनी विकास नियमों को एकीकृत कर अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

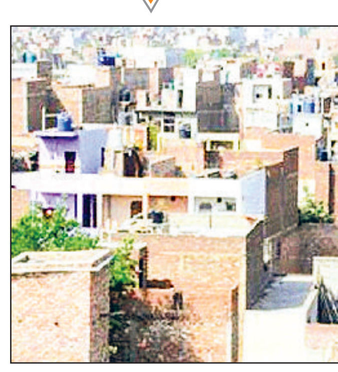

खरीदारों पर भी आर्थिक जिम्मेदारी

शिकायत मिलने के बाद यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में मकान या प्लॉट खरीदने वालों को भी नए कानून के तहत आर्थिक जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसी कॉलोनियों में आवश्यक आंतरिक विकास कार्यों की 50 प्रतिशत लागत रहवासियों से वसूली जाएगी, जबकि शेष राशि कॉलोनाइजर की बैंक गारंटी और संपत्ति जब्त कर वसूल की जाएगी।

ड्राफ्ट में संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

ड्राफ्ट में संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। शहरों की सीमा, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, हवाई अड्डों और निवेश क्षेत्रों के आसपास कॉलोनी विकसित करने पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। निवेश क्षेत्रों से 16 किलोमीटर की परिधि तक शहरी मानकों के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी। अब शासकीय भूमि, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नगर निकाय, विकास योजना, खेल मैदान, पार्क, नदी-नालों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के लिए अधिसूचित भूमि पर विकसित कॉलोनियों को अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित वार्ड प्रभारी से लेकर कलेक्टर तक की जवाबदेही तय होगी।

कार्रवाई के लिए 15 दिन की समय-सीमा का प्रस्ताव

सरकार ने अवैध और अनाधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई के लिए 15 दिन की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं कॉलोनी विकास से संबंधित विभिन्न अनुमतियां अधिकतम 45 दिन में जारी करनी होंगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि नए कॉलोनी अधिनियम का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी रोक लगाना, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है।

पतंजलि विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 का समापन

यहां से जाने वाला हर छात्र राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित युवा बने : आचार्य बालकृष्ण

हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय एवं पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक माह के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 का आज भव्य एवं गरिमामय समापन समारोह सम्पन्न हुआ। देश के 11 राज्यों से आए 130 छात्र-छात्राओं ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, भारतीय ज्ञान परंपरा तथा समग्र व्यक्तित्व विकास का अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को प्रयोगशाला आधारित वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, योग, यज्ञ एवं नैतिक मूल्यों से भी जोड़ने का कार्य किया। समापन समारोह में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण तथा उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रतिभागियों को

संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। आचार्य बालकृष्ण महाराज ने कहा कि भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में शोध करने वाला विद्यार्थी यदि भारतीय संस्कृति, योग एवं यज्ञ की परंपरा से भी जुड़ा हो, तो उसका व्यक्तित्व अधिक संतुलित, अनुशासित एवं राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित बनता है।

पुलिस महानिदेशक (रेल) सिंह ने दिए निर्देश

जीआरपी: स्वस्थ रहने हर शनिवार 5 किमी दौड़ेंगे आरक्षक से एसपी तक

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मप्र रेलवे पुलिस (जीआरपी) में अब फिटनेस को लेकर बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (रेल) राजाबाबू सिंह ने रेलवे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हर शनिवार 5 किमी की अनिवार्य दौड़ के निर्देश दिया हैं।

इस अभियान में आरक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक (एसपी) तक सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। एडीजी रेल का स्पष्ट कहना है कि पुलिस जनता के लिए एक फिटनेस आइकॉन होती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों को सेहतमंद दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की शारीरिक फिटनेस

बेहतर होगी तो उसका सकारात्मक असर उनकी कार्यक्षमता और जनता के बीच पुलिस की छवि पर भी पड़ेगा। रेलवे पुलिस में करीब 1500 जवान और अधिकारी पदस्थ हैं। एडीजी के निर्देश सभी रेल पुलिस अधीक्षकों, डीएसपी और जीआरपी थाना प्रभारियों तक पहुंचा दिए गए हैं। आदेश के अनुसार हर शनिवार आयोजित होने वाली 5 किमी की दौड़ में भाग लेना अनिवार्य होगा। रेल एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि मोहर्रम के दौरान पुलिस बल की कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के कारण इस सप्ताह दौड़ आयोजित नहीं हो सकेगी। अब यह अभियान 4 जुलाई से शुरू होगा। दौड़ का रूट भदभदा स्थित रेल आईजी कार्यालय से शुरू होकर न्यू मार्केट होते हुए प्लेटिनम प्लाजा तक रहेगा। इसमें अधिकारी और जवान एक साथ दौड़ लगाएंगे।

एडीजी राजाबाबू सिंह ने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों की उम्र 45 वर्ष से कम है, उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ अनिवार्य रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं इस दौड़ में शामिल होंगे, जबकि उनकी उम्र 59 वर्ष है। उनका मानना है कि जब वरिष्ठ अधिकारी खुद मैदान में उतरेंगे तो जवानों का मनोबल बढ़ेगा और फिटनेस के प्रति प्रेरित होंगे।

मंत्री परमार ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर जनसमस्याएं सुनीं

कार्यकर्ताओं से चर्चा करते मंत्री परमार।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं, आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया।

फैसले से राज्य के कानूनी और सामाजिक ढांचे में होंगे बदलाव

यूसीसी लागू करने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार, हाईलेवल कमेटी को मिली मंजूरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। सरकार के इस अहम कदम से राज्य के कानूनी और सामाजिक ढांचे में बदलाव आ सकता है। कैबिनेट ने जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाने को मंजूरी दी है। इस कमेटी का काम कानून का ड्राफ्ट तैयार करना होगा, जिससे भाजपा सरकार के चुनावी वादों में से एक को पूरा किया जा सकेगा।

पांच सदस्यों की होगी कमेटी

इस फैसले के साथ, छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जो यूसीसी पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पांच सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वह सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं और अहम संवैधानिक व कानूनी पैनलों का नेतृत्व करने के लिए जानी जाती हैं।

एक्सपर्ट होंगे शामिल उनके साथ कमेटी में रिटायर्ड नौकरशाह, अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ और सीनियर वकील शामिल हैं।

लघु वेतन कर्मियों की मांगों का हल नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को आंबेडकर मैदान में प्रदेशभर से आए हजारों अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि यह आंदोलन कर्मचारियों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य की लड़ाई है। सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र सकारात्मक पहल करनी चाहिए। आंबेडकर मैदान में प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो मप्र लघु वेतन कर्मचारी संघ प्रदेशभर में चरणबद्ध एवं व्यापक आंदोलन प्रारंभ करेगा।

PUBLIC NOTICE

The Public at large is hereby notified that my client Smt. Nisha Malhotra and others are intending to purchase a Freehold built-up Property No.83, Measuring Area 232.79 Sq. Yds. Situated at AGCR ENCLAVE, Delhi-110092, from (i)Shri Manoj Suneja S/o Sh. Santosh kumar Suneja & (ii)Smt. Mamta Suneja W/o Shri Manoj Suneja, they represent himself as owners of the said property.It is therefore notified that anybody claiming any rights, share, claim, title, litigation, attachment, interest or lien over the aforesaid property may file such claim or objection to the undersigned within a period of 07 days from the date of Publication of this Notice, otherwise it will be presumed that the said property is free from all encumbrances, charges and/or lien etc. and my clients are free to sell/transfer the said property.

Rakesh N.D. (ADVOCATE),
Office No.107, First Floor,
M.S. Chamber,C-1/A, Vikas Marg,
Laxmi Nagar, Delhi-110092

लोक भवन में मनाया गया पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस

विविधता में एकता का आधार भारत के विभिन्न राज्यों के लोग, हमारी आत्मीयता...साम्यता का मंच स्थापना दिवस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि भारत की विविधता में एकता का आधार भारत के विभिन्न राज्यों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दूध में शक्कर घुल जाती है, उसी तरह से मप्र में बंगाल के मूल निवासी घुल मिल गए हैं।

हमारी अनेकता में एकता की आत्मीयता और साम्यता को राज्य स्थापना दिवस के आयोजन साकार करते है। आयोजन के मंच पर हमारी वेशभूषा, गीत, नृत्य में समाई हमारी सांस्कृतिक विविधता में एकता की झलक मिलती है। पश्चिम बंगाल की प्रस्तुतियों में उन्हें गुजरात के गरबा नृत्य और वेशभूषा में असम राज्य की झलक दिखाई दी। राज्यपाल पटेल

आज लोकभवन में आयोजित पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के प्रसंग में आयोजित समारोह में सम्मिलित भोपालवासी बंगाली मूल के लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना को सुदृढ़, राष्ट्रीय एकात्मकता को नई शक्ति प्रदाय करने और राज्यों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक संवाद, आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देने के प्रयास अद्भुत है। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में भोपाल के विभिन्न काली बाड़ियों के सदस्य उपस्थित थे।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 देखिए)
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **पिन्नू पुत्र राजेन्द्र पता मकान नं ए-145, विजय विहार फेस-II, दिल्ली ने एफआईआर नं 1078/2017 धारा 33/58 दिल्ली एक्स एक्ट के तहत** थाना: मंगोलपुरी, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **पिन्नू** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **पिन्नू** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अत: इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **एफआईआर नं. 1078/2017 धारा 33/58 दिल्ली एक्स एक्ट के तहत थाना: मंगोलपुरी, दिल्ली के उक्त पिन्नू** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **31.07.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
रितिका जैन
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी - 05
नार्थ वेस्ट कोर्ट नं.105
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/8669/OD/2026

हमारे शहरों में बढ़ती जनसंख्या और उसके अनुरूप अनियोजित भवन निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से जानलेवा साबित हो रहे हैं। आवासीय इलाकों में बिना सोचे-समझे व्यावसायिक गतिविधियां और कारखाने खोल दिए जाते हैं। ऐसे में जब कभी आग लगती है तो संकरी गलियों के कारण दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं। ऐसे में हादसा अनगिनत जानों को लील लेता है। प्रशासन द्वारा निर्धारित भवन निर्माण के नियम कोई रुकावट नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए बेहद जरूरी सुरक्षा कवच हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अवैध निर्माण लालची बिल्डरों और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के गठजोड़ से फलते-फूलते हैं। बिल्डर सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करते हैं, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और खरीदार अंत में फंसता है। छोटे शहरों में स्थिति और भी बदतर है। यहां नगर पालिकाएं संसाधनों की कमी और स्थानीय दबाव के आगे घुटने टेक देती हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे और सुरक्षित भवन निर्माण की दिशा में तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए तो भविष्य में आगजनी की घटना अथवा आने वाला एक छोटा सा भूकंप भी हमारे विकास के सभी दावों को मलबे में बदल देगा। ***इन्हीं हालातों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...***

अनियोजित शहरीकरण से हादसों को निमंत्रण

विश्लेषण

डॉ. चंद्र त्रिखा

वरिष्ठ स्तंभकार

> **विकास की इस तेज भागदौड़ में हम यह बुनियादी बात भूल जाते हैं कि शहर केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे के बेजान ढांचे नहीं हैं; बल्कि ये एक जीती-जागती व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को सही ढंग से चलने और सुरक्षित रहने के लिए एक दूरदर्शी योजना की बहुत जरूरत होती है। आज हमारे शहर बिना किसी सही योजना के जिस तरह से फैल रहे हैं, वह किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी नाकामी 'भवन निर्माण के नियमों' की अनदेखी के रूप में सामने आती है, जो हमारे शहरों को एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल रही है। भवन निर्माण के नियम किसी भी सुनियोजित शहर की रीढ़ होते हैं। ये वे कानूनी और तकनीकी दिशा-निर्देश हैं जो यह पक्का करते हैं कि कोई भी इमारत रहने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो।**

शहरों का विकास आधुनिक युग की एक बड़ी और सुखद सच्चाई है। हर दिन हजारों लोग एक बेहतर जिंदगी, रोजगार, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की आस में गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमक-दमक वाली जीवनशैली शहरों को बहुत आकर्षक बनाती है। लेकिन, विकास की इस तेज भागदौड़ में हम यह बुनियादी बात भूल जाते हैं कि शहर केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे के बेजान ढांचे नहीं हैं; बल्कि ये एक जीती-जागती व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था को सही ढंग से चलने और सुरक्षित रहने के लिए एक दूरदर्शी योजना की बहुत जरूरत होती है। आज हमारे शहर बिना किसी सही योजना के जिस तरह से फैल रहे हैं, वह किसी भी समय जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी नाकामी 'भवन निर्माण के नियमों' की अनदेखी के रूप में सामने आती है, जो हमारे शहरों को एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल रही है। भवन निर्माण के नियम किसी भी सुनियोजित शहर की रीढ़ होते हैं। ये वे कानूनी और तकनीकी दिशा-निर्देश हैं जो यह पक्का करते हैं कि कोई भी इमारत रहने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। इन नियमों में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। जैसे कि इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली खाली जगह, जमीन के अनुपात में निर्माण की अधिकतम सीमा, आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम, भूकंप सहने की क्षमता, और आपात स्थिति में बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते। इसके पीछे का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि पड़ोसियों को भी पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। जब शहरों का फैलाव बिना किसी पक्की योजना के, रातों-रात मनमाने तरीके से होता है, तो सबसे पहले इन्हीं नियमों की बलि चढ़ाई जाती है।

नियमों की हो रही अनदेखी

ज्यादा मुनाफे की चाहत और जगह की कमी के नाम पर निर्माण करने वाले ठेकेदार और खुद भवन मालिक भी इन नियमों को ताक पर रख देते हैं। नतीजा यह होता है कि तंग गलियों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, जिनमें न तो हवा आने का कोई रास्ता होता है और न ही धूप का। इस अनदेखी का सीधा असर उन खौफनाक हादसों के रूप में सामने आता है, जो अब हमारे शहरों की रोजमर्रा की कहानी बन चुके हैं। बहुमंजिला इमारतों में भयानक आग लगने या उनके भरभरा कर गिर जाने की दर्दनाक खबरें अब आम हो गई हैं। आवासीय इलाकों में बिना सोचे-समझे व्यावसायिक गतिविधियां और कारखाने खोल दिए जाते हैं। ऐसे में जब कभी आग लगती है, तो संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं। इन इमारतों में संकट के समय बाहर निकलने के रास्ते या तो होते ही नहीं, या उन पर फालतू सामान रखकर रास्ता रोक दिया जाता है।

खास बातें

- भवन निर्माण के नियम हमारे और परिवार के जीवन की सुरक्षा की गारंटी
- संकरी गलियों के कारण दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पातीं।
- नगर निगम और जमीन माफियाओं का भ्रष्ट गठजोड़ असली जिम्मेदार
- शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए नियमों का पालन ही एकमात्र विकल्प

दम घुटने से ज्यादा मौतें

हवा के आने-जाने का सही रास्ता न होने के कारण आग लगने पर लोग लपटों से कम, और जहरीले धुएं से दम घुटने के कारण ज्यादा जान गंवाते हैं। इसी तरह, कमजोर नींव, घटिया निर्माण सामग्री और बिना अनुमति के बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों के कारण कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। जब इमारत बनाने से पहले मिट्टी की जांच और ढांचे की मजबूती परखने जैसे जरूरी कामों को नजरअंदाज किया जाता है, तो भूकंप का एक हल्का झटका या तेज बारिश भी भारी तबाही ला सकती है। बिना योजना के बसाए गए शहर जलभराव जैसी गंभीर मुसीबतों का भी मुख्य कारण हैं। भवन निर्माण नियमों में पानी की निकासी और बारिश के पानी को सहेजने के सख्त नियम होते हैं। अवैध निर्माण की होड़ में प्राकृतिक जल स्रोतों, नालों और तालाबों को मिट्टी से भरकर वहां ईंट-पत्थर के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं।

जमा पानी की निकासी नहीं

इसका नतीजा यह होता है कि थोड़ी सी बारिश में ही पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। पानी के निकलने का कोई रास्ता न बचने के कारण इमारतों के निचले हिस्सों में पानी भरने से होने वाली मौतें अब एक डरावनी सच्चाई बन गई हैं। यह सीधे तौर पर नगर नियोजन या शहर बसाने की योजना का मजाक उड़ाने का परिणाम है। यह डरावनी स्थिति एक-दो दिन में पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे ढीली प्रशासनिक अव्यवस्था, लापरवाह नगर निगम और लालची जमीन माफियाओं का भ्रष्ट गठजोड़ जिम्मेदार है। दिन के उजाले में खुलेआम अवैध निर्माण होता रहता है और जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी रहती है। रिश्वत और पहुंच के दम पर नियमों के खिलाफ बनी इमारतों को भी निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र आसानी से मिल जाते हैं। सस्ते घर के लालच में लोग ऐसी इमारतों में अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, जो कभी भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। अब वह समय आ गया है कि बिना योजना के बढ़ते शहरीकरण और नियमों की अनदेखी पर गंभीरता से विचार किया जाए। नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को अपनी जिम्मेदारी सख्ती से समझनी और निभानी होगी। नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

अवैध निर्माण वैध करना गलत

जुर्माना लेकर अवैध निर्माण को वैध कर देने की गलत परंपरा को तुरंत बंद करना होगा। हवाई सर्वेक्षण और उपग्रह से प्राप्त चित्रों जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके अवैध निर्माणों को शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए। घर खरीदते या बनाते समय यह जांचना हर नागरिक का भी फर्ज है कि वह इमारत सभी कानूनी और सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हो। यदि बिना सोचे-समझे हो रहे शहरीकरण पर नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ, तो ये बेतरतीब जंगल इसी तरह दर्दनाक हादसों को न्योता देते रहेंगे।

शहरीकरण की भूख से बर्बाद हो रहा मानव जीवन

हादसा

योगेश कुमार सोनी

वरिष्ठ पत्रकार

बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरी सुविधाओं पर बढ़ते दबाव और हादसों का सबसे बड़ा कारण अनियोजित और अनियंत्रित शहरीकरण है, जिसके चलते बुनियादी ढांचा जिसमें सड़कें, सीवर, बिजली शामिल हैं- यह सब चरमरा जाता है। इससे भीड़भाड़, यातायात के दबाव और असुरक्षित निर्माण जैसे हादसे होते हैं। सीमित सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ और पैदल यात्रियों के मिश्रण से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। बुनियादी ढांचे के अभाव में लोग अवैध, अनियोजित और कमजोर इमारतों में रहने को मजबूर होते हैं, जो ढहने या आग लगने जैसे हादसों का कारण बनती हैं। क्षमता से अधिक भार के कारण बिजली के शॉर्ट-सर्किट और आग लगने जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। जनसंख्या बढ़ने और कंक्रीट के जंगल बनने से बारिश के पानी की सही निकासी नहीं होती, जिससे सड़कों पर जलभराव, गड्ढे और करंट फैलने के घातक हादसे होते हैं।

यदि महानगरों की बात करें तो वह नब्बे प्रतिशत से अधिक अवैध रूप से इमारतें बनती हैं। चूंकि बिना नक्शे की बिल्डिंग बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं हैं, जिसके चलते लोग नगर निगम के अधिकारियों को रिश्वत देकर बिना नक्शे की इमारत बना लेते हैं। लोगों की हवस यहां तक भी नहीं रुकती- पार्किंग के साथ चार फ्लोर तक बना सकते हैं, लेकिन कुछ पांच से सात फ्लोर तक बना लेते हैं और कई लोगों की जान जोखिम में डाल देते हैं। जब हादसा होता है तो कई लोग बेमौत मारे जाते हैं। नियम को अनदेखी करना जैसे लोगों की फितरत में शामिल हो गया। अब भवन निर्माण उपनियम आया तो लोगों के घर टूट रहे हैं जिससे अब लोग परेशान हो रहे हैं। इसमें लोगों की भी गलती नहीं मानी जा सकती ,चूंकि जैसा सिस्टम था, वह उनके अनुसार ही चल रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब सत्ता बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है- मरना अंत में जनता का ही होता है। नक्शे व संबंधित डॉक्यूमेंट में यह स्पष्ट होता है कि इन खसरों पर किसी भी भवन या भूखंड का मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृत नहीं हो सकता। यहां बने निर्माण पूरी तरह अवैध हैं, इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सीवर, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। लोगों से कहा है कि किसी भी जमीन या भवन की खरीद-बिक्री से पहले उसकी स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।ल बावजूद इसके बिल्डर धडल्ले से इमारत बना कर बेचते हैं और आश्चर्य की बात कि लोग खरीदते भी हैं। सीलिंग के बाद भी यहां बिजली पानी के मीटर तक लग जाते हैं। यदि हम हिन्दुस्तान के परिवेश में चर्चा करें तो हमारे यहां जनसंख्या का बेहद तेजी से बढ़ना जारी है तो उस आधार पर सरकारों को जनता के लिए जगह की व्यवस्था करनी होती है। इसके चलते जंगल का पर्यावरण बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है । देश की तरक्की व जनता की जरूरत के लिए ऐसे मुद्दों की गंभीरता न समझना मानव जीवन पर ही भारी पड़ रहा है। मनुष्य की शहरीकरण की भूख ने इतनी हानि पहुंचा दी कि उसको यह मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब काल के गर्भ में प्रवेश कर गया। यदि महानगरों की जीवनशैली व यापन की चर्चा करें तो यहां पिछले दो दशकों कम आयु में होने वाली मौतों के आंकड़ों ने चौंका दिया। मनुष्य की आयु का घटना लगातार जारी है। इंसान की उम्र करीब सौ वर्ष होती थी, लेकिन आज के दौर में साठ साल पर आकर सीमित रह गई। वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार हो रही आपदाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के बेहद अधिक इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका मानना है कि आज स्थिति के आधार पर हमारी धरती अपने भार से कहीं अधिक भार वहन कर रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले दशकभर में धरती रहने लायक नहीं बचेगी, लेकिन मनुष्य आज भी सही राह पर चले तो वो अपना भविष्य सुधार सकता है। हर रोज न जाने कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। वैश्विक सरकारों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में भी इसको बेहद गंभीर मुद्दा माना जा रहा है, लेकिन कुछ देर ही जागरूक होकर फिर पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं, जिससे हम सही दिशा पर नहीं आ पा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं हैं कि सरकार ऐसे मामलों में एक बड़ा बजट पारित करती है व इसके प्रति गंभीर भी रहती हैं। इसके लिए केन्द्र व राज्य स्तर पर विभाग कार्यरत भी हैं, लेकिन हम उतनी संजीदगी से इस बात की गंभीरता नहीं समझ पा रहे, जितने की जरूरत है। सरकार को कोई ऐसा नियम निकालना चाहिए, जिससे शहरों में नियम-कानून के साथ इमारत बनें। यदि किसी जगह आग लग जाती है तो शहरों की छोटी तो छोड़ो, बड़ी गलियों तक में एंबुलेंस नहीं जा पाती, चूंकि लोगों ने सड़कों को घेरा हुआ है।

> **देश की तरक्की व जनता की जरूरत के लिए ऐसे मुद्दों की गंभीरता न समझना मानव जीवन पर ही भारी पड़ रहा है। शहरीकरण की भूख ने इतनी हानि पहुंचा दी कि मनुष्य को यह मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब काल के गर्भ में प्रवेश कर गया।**

भ्रष्ट नियामक और वास्तु का क्रेज

विरोधाभास

विवेक शुक्ला

वरिष्ठ पत्रकार

भारत में छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक, भवन निर्माण नियमों का पालन एक सपना बनकर रह गया है। जहां एक ओर नियामक संस्थाएं कानून की रखवाली का दायित्व निभाने के बजाय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी वास्तु शास्त्र के नाम पर 'परिपूर्ण' घर बनाने की होड़ में लगा हुआ है। यह विरोधाभास न केवल शहरी नियोजन को चुनौती दे रहा है, बल्कि सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के सवाल भी खड़े कर रहा है।

भारतीय शहरों में अनधिकृत निर्माण की समस्या कोई नई नहीं है। हर बड़े और छोटे शहर में यही कहानी दोहराई जाती है। भवन निर्माण नियम भूतल क्षेत्र अनुपात, पीछे हटाव, ऊंचाई सीमा, वाहन पार्किंग स्थान, अग्नि सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों को तय करते हैं, लेकिन इनका उल्लंघन आम बात है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अवैध निर्माण बिल्डर और सरकारी अधिकारी के गठजोड़ से फलते-फूलते हैं। बिल्डर सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करते हैं, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं और खरीदार अंत में फंसता है। छोटे शहरों में स्थिति और बदतर है। यहां नगर पालिकाएं संसाधनों की कमी और स्थानीय दबाव के आगे घुटने टेक देती हैं। एक साधारण प्लॉट पर मंजूरी से दोगुनी मंजिलें चढ़ जाती हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से बड़े हादसे होते हैं। बड़े शहरों में ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में प्रवेश कक्ष और तहखाने को व्यावसायिक स्थान में बदल दिया जाता है। कई कॉलोनियों में तहखाना वाहन पार्किंग स्थान की जगह दुकानें देखी जा सकती हैं। मुंबई में आदर्श सोसाइटी कांड या चेन्नई में इमारत गिरने की घटनाएं इस सड़ांध को उजागर करती हैं। देश भर के विभिन्न हिस्सों में यही स्थिति है, जहां नियमों की अनदेखी आम हो गई है। नियामक संस्थाएं भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों बनीं? कारण स्पष्ट हैं- राजनीतिक दखल, कमीशन की संस्कृति और जवाबदेही का अभाव। भवन अनुमोदन प्रक्रिया में स्वयं प्रमाणन का चलन बढ़ा है, जहां इंजीनियर का प्रमाण पत्र ही काफी माना जाता है। स्थल निरीक्षण नाममात्र का होता है। पारदर्शिता की कमी और डिजिटल निगरानी का अभाव समस्या को बढ़ाता है। एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि शहरी नियोजन में रिश्वतखोरी की पिरामिड संरचना काम करती है, निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक। इस बीच, वास्तु शास्त्र का क्रेज आसमान छू रहा है। लोग नए घर या कार्यालय बनाते समय दिशाओं, रंगों, सामग्री और 'ऊर्जा प्रवाह' का ख्याल रखने लगे हैं। वास्तु सलाहकारों की फीस लाखों में पहुंच गई है। देश के विभिन्न महानगरों में 'वास्तु अनुरूप' संपत्तियों की मांग बढ़ी है। बिल्डर विपणन में इसे अनोखी विशेषता बना रहे हैं-'उत्तर मुखी', 'सकारात्मक ऊर्जा' वाले फ्लैट। आज कई परिवार घर खरीदते या बनाते समय वास्तु विशेषज्ञ बुलाते हैं, लेकिन निर्माण नियमों की अनदेखी करते हैं। नतीजा? भूकंप या आग में जान-माल का नुकसान। वास्तु अच्छा है-यह प्राचीन भारतीय विज्ञान पर्यावरण और मनोविज्ञान को जोड़ता है-लेकिन जब यह भ्रष्ट निर्माण को सही ठहराने का बहाना बन जाए, तो समस्या गहरी हो जाती है। बिल्डर 'वास्तु अनुरूप' कहकर अवैध विस्तार बेचते हैं, जबकि अग्नि निकास या संरचनात्मक सुरक्षा की परवाह नहीं करते। देश के कई इलाकों में वास्तु के नाम पर अतिरिक्त बालकनी या कमरे जोड़े जा रहे हैं, जो इमारत की मजबूती को कमजोर कर देते हैं। इससे शहरों की सौंदर्यता बिगड़ रही है और यातायात जाम बढ़ रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह हानिकारक है, क्योंकि हरे-भरे स्थान घिर रहे हैं। समाधान क्या है? सबसे पहले, भवन निर्माण नियमों को सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाना होगा।

भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन सर्वेक्षण और ऑनलाइन मंजूरी प्रणाली लागू करें। भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, आपराधिक दायित्व और तीसरी पक्ष की जांच जरूरी है। वास्तु को वैज्ञानिक दृष्टि से बढ़ावा दें-इसे सतत वास्तुकला का हिस्सा बनाएं, न कि अंधविश्वास का, लेकिन अंधविश्वास और नियमों की अनदेखी खतरनाक है। देश के प्रख्यात वास्तुकार उज्जवल उपाध्याय कहते हैं कि सरकारें स्मार्ट शहर, अमृत 2.0 जैसी योजनाओं में भवन संहिता लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें। जन जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि खरीदार नियम जांचें। अगर हम नियमों का पालन करें और वास्तु को समझदारी से अपनाएं, तो ही स्वस्थ, सुंदर और सुरक्षित शहर बना पाएंगे। साफ है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जागरूकता से ही यह समस्या हल हो सकती है।

आज कई परिवार घर बनाते समय वास्तु विशेषज्ञ बुलाते हैं, लेकिन निर्माण नियमों की अनदेखी करते हैं। अगर हम नियमों का पालन करें और वास्तु को समझदारी से अपनाएं, तो ही सुंदर और सुरक्षित शहर बना पाएंगे। साफ है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जागरूकता से ही यह समस्या हल हो सकती है।

बिल्डिंग बायलॉज का कड़ाई से हो पालन

व्यवस्था

डॉ. विजेंद्र कुमार

स्वतंत्र स्तंभकार

विकास की अत्यंत तेज रफ्तार ने हमारे शहरों को आसमान छूती ऊंची इमारतों और कंक्रीट के विशाल जंगलों में बदल दिया है। दूर से देखने पर ये शहर भले ही बहुत आधुनिक और प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन इनकी नींव में एक ऐसी भयंकर लापरवाही छिपी है, जो किसी भी पल एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। आज हमारे शहर भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो चुके हैं।

विडंबना यह है कि इन शहरों में भूकंप से बचाव करने वाली तकनीक और इससे जुड़ी संस्थाओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी नाजुक और चिंताजनक हो चुकी है कि एक छोटा या मध्यम गति का भूकंप भी हमारे शहरों में बहुत बड़े हादसों का कारण बन सकता है। ऐसे में 'भवन निर्माण के नियमों' का वास्तविक महत्व और उनका पूरी कड़ाई से पालन करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से उत्तर भारत, हिमालय के आसपास के पहाड़ी इलाके और कई घनी आबादी वाले बड़े शहर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बसे हुए हैं। इन इलाकों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी और बिना किसी उचित योजना के हो रहे शहरीकरण ने खतरे को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। शहरों में जगह की भारी कमी और ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में लोग संकरी गलियों के भीतर भी कई मंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं। इन इमारतों को बनाते समय न तो मिट्टी की मजबूती की ठीक से जांच की जाती है और न ही दो इमारतों के बीच आवश्यक दूरी छोड़ी जाती है। यह हमारी उस लापरवाह सोच का नतीजा है जो मुसीबत आने से पहले उसकी तैयारियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। किसी भी शहर के सुरक्षित, व्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए 'भवन निर्माण के नियम' बनाए जाते हैं। इन नियमों में मुख्य रूप से इमारत की ऊंचाई, नींव की गहराई, इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता, हवा-रोशनी की उचित व्यवस्था, आपात स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते और भूकंप से बचाव के मापदंड तय होते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय जान और माल के नुकसान को कम करना है। हकीकत यह है कि ये महत्वपूर्ण नियम अक्सर केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाते हैं। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई के कारण इनकी खुलेआम अनदेखी होती है। नक्शे में जो डिजाइन कागजों पर दिखाया जाता है, असल निर्माण उससे बिल्कुल अलग होता है। कई बार ठेकेदार बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए मनमाने तरीके से इमारतें तान देते हैं। भूकंप के खतरों की गंभीरता को देखते हुए हर नई इमारत का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से होना चाहिए, लेकिन आज भी आम आदमी इसे एक फालतू खर्च मानता है और इससे बचने का हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा देश में ऐसे कुशल इंजीनियरों, राजमिस्त्रियों और निर्माण संस्थाओं की भारी कमी है, जिन्हें इस तकनीक का सही और व्यावहारिक ज्ञान हो। हमारे पास ऐसी संस्थाओं का भी घोर अभाव है जो पुरानी और कमजोर पड़ चुकी इमारतों को नई तकनीक के माध्यम से सस्ती दरों पर मजबूत बना सकें। हम अक्सर यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि केवल बहुत तेज भूकंप ही तबाही लाता है, लेकिन हमारे शहरों की वर्तमान बनावट और कमजोर ढांचे को देखते हुए यह सोच जानलेवा है। जब इमारतें बुनियादी सुरक्षा मानकों के बिना, खराब सामग्री से और नियमों को पूरी तरह ताक पर रखकर बनी हों, तो छोटी गति का भूकंप भी विनाशकारी साबित हो सकता है। संकरी गलियों में एक-दूसरे से बिल्कुल सटी हुई इमारतें जब हिलती हैं, तो उनके आपस में टकराने से वे बहुत आसानी से ढह सकती हैं। मलबे के कारण रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं और बचाव कार्य के लिए दमकल की गाड़ियों या एंबुलेंस का पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां धरती का हल्का झटका भी हजारों जिंदगियों को मलबे में दबा सकता है। इस बड़े खतरे से निपटने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। सरकार को यह पक्का करना होगा कि भवन निर्माण नियमों का पालन सिर्फ दिखावा न रहे। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। पुरानी और व्यावसायिक इमारतों के ढांचे की मजबूती की नियमित जांच अनिवार्य रूप से की जाए।

हर नई इमारत का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से होना चाहिए, लेकिन आज भी आम आदमी इसे एक फालतू खर्च मानकर इससे बचने का प्रयास करता है। इसके अलावा, देश में ऐसे कुशल इंजीनियरों, राजमिस्त्रियों की भारी कमी है, जिन्हें इस तकनीक का सही और व्यावहारिक ज्ञान हो

प्रशासन और निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच आखिरकार बनी बात, दोनों पक्षों में शांति-संवाद से समाधान पर सहमति की संभावना

उत्तराखंड प्रशासन और सिख समुदाय के बीच हुई वार्ता, निहंगों को किया रिहा

निहंगों ने कानून को हाथ में नहीं लेने का दिया आश्वासन

एजेंसी ▶▶ देहरादून

कर्णप्रयाग प्रकरण के बाद उत्तराखंड में तनावपूर्ण माहौल के बीच शुक्रवार को उत्तराखंड प्रशासन और निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक माहौल में महत्वपूर्ण वार्ता हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने पर सहमति जताई। निहंगों ने प्रशासन के सामने मुकदमा वापस लेने, निहंग सिखों से मिलने समेत 4मांगें रखीं। इन पर प्रशासन ने दो दिन का समय मांगते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई है। निहंग दो दिनों तक पांवटा साहिब में ही रहेंगे।

कर्णप्रयाग विवाद सुलह के करीब पहुंचा

निहंगों का एक जत्था

शुक्रवार को भी उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, अल्मोड़ा के एसएसपी हरबंस सिंह सहित अधिकारी गुरुद्वारा पांवटा साहिब पहुंचे। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कुलवंत सिंह भी मौजूद रहे। दोनों के बीच विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा हुई।अधिकारी लौट गए, जबकि पंजाब का निहंगों का जत्था गुरुद्वारा पांवटा साहिब में ही रुका हुआ है।

प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया

जगदीप सिंह अकाली, निहंग प्रतिनिधि ने कहा कि प्रशासन संग सकारात्मक चर्चा हुई है और प्रशासन ने उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती और गिरफ्तार निहंग सिंहों को रिहा नहीं किया जाता, तो आगे की रणनीति पर अमल किया जाएगा।

ये हैं निहंगों की मांगें

- जेल में बंद निहंगों से मिलने दिया जाए।
- अस्पताल में भर्ती घायल निहंग से भी मुलाकात हो।
- निहंगों को जमानत दिलाएं और उन्हें साथ लेकर ही जाएंगे।
- शांतिपूर्वक हेमकुंड यात्रा करने दी जाए।

सरकार ने लगाई सिंहों की टोली

निहंगों से वार्ता के लिए सरकार ने भी अपने सिंहों की टीम उतारी थी। इनमें भुल्लर से लेकर कई अन्य सिख अफसर निहंगों से वार्ता करने पहुंचे। इससे तो भाषा बाधा बनी और न ही सांस्कृतिक उलझन पैदा हुई। दो दिनों में कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार शुक्रवार को यह रणनीति काम कर गई और निहंगों के साथ सकारात्मक बातचीत से इसका अस्थाई ही सही लेकिन हल निकल आया।

पंजाबी भाषा भी बनी बड़ी समस्या

ज्यादातर निहंग केवल पंजाबी भाषा में ही बात करते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और पुलिस अफसर को निहंगों से सीधा संवाद करने में भी कठिनाई हो रही थी। कई निहंग सिख इसी बात को कह रहे थे, उनसे पंजाबी में बात करो। ऐसे में पंजाबी कितने लोगों को आती है यह बड़ी समस्या थी।

खबर संक्षेप

छोटे चाय उत्पादकों को मिलेगी किसान आईडी

गुवाहाटी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि असम में छोटे चाय उत्पादक अब किसान पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार के अलग-अलग लाभों का फायदा उठा सकेंगे। किसानों को किसान आईडी जारी की जाएगी। वे उर्वरक, सरकारी योजनाओं के लाभ,कर्ज और अन्य कृषि सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

300 फीट नीचे नाले में गिरी कार, 4 की मौत

चंबा। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला के जनजातीय उपमंडल भरमौर में शनिवार को भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सामरा-उरेई लिंक रोड पर सारणी का नाला के समीप एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में लुढ़कते हुए नाले में जा गिरी।कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य घायल हो गए।

जोधपुर एयरपोर्ट का 4 को मोदी करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर में 35 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षित नया एयरपोर्ट टर्मिनल अब जनता की सेवा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।नई दिल्ली से जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने यह बात कही।

केरल में शिगेला प्रकोप 10 नए मामले दिखे

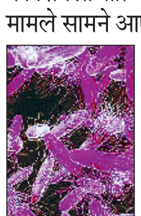

तिरुवनंतपुरम। केरल में शनिवार को शिगेला संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इस वर्ष राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 266 हो गई। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, नए मामलों में मलप्पुरम से पांच, कोझिकोड से चार और वायनाड से एक मामला सामने आया है।

बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत, मां-बेटा घायल

हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के एनएच-334 स्थित टियाला अंडरपास के पास शनिवार की सुबह ट्रैक्टरट्रॉली ने एक बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक कार के नीचे आ गई और कार हाईवे पर पलट गई। बाइक सवार जिला गाजियाबाद के गांव बम्हेटा निवासी विनोद उर्फ बबली (35) व उनके पुत्र प्रियांश (11) की मौके पर ही मौत हो गई।

भोपाल के रवींद्र भवन में सशक्त उद्यमी-समृद्ध मप्र समिट का आयोजन, सीएम ने की बड़ी घोषणाएं

अगला साल युवा वर्ष के रूप में मनेगा जनवरी में भोपाल में होगी जीआईसी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सीएम ने कहा कि वर्ष 2025-26 में मप्र के 20 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं। राज्य सरकार सभी की कठिनाई को समझते हुए विकास की धारा में सरलता, सुचिता और अपने पारदर्शी निर्णयों के बूते आगे बढ़ रही है

मुख्यमंत्री ने 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि दी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सशक्त उद्यमी-समृद्ध मप्र समिट में बोलते हुए

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि साल 2027 को राज्य सरकार युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। दूसरी ओर ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) भी जनवरी में भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से 760 से अधिक इकाइयों को प्रोत्सान राशि दी। उन्होंने प्रदेश के 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ की सहायता राशि भी दी। मप्र निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत वृहद उद्योगों को 1274 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए भूमि आवंटन पत्र और लोन स्वीकृति पत्र भी दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह घोषणाएं अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस-2026 पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित 'सशक्त उद्यमी-समृद्ध मप्र समिट' में की। कार्यक्रम में मप्र के सफल उद्यमियों की विकास गाथा पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 4 लाख 41 हजार से अधिक एमएसएमई यूनिट्स की कमान माताओं-बहनों के हाथों में है। पिछले वर्षों के मुकाबले वर्ष 2024 से 2026 के बीच एमएसएमई में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व 59 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए 16 कलस्टर का निर्माण किया है। 14 नए कलस्टर पर काम चल रहा है। राज्य को ओडीओपी में उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2025-26 में मप्र के 20 उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं।

सरकार ने उद्योगों को 1,274 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की एमओयू भी हुए साइन

प्रदेश के 137 स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ की सहायता राशि भी दी

देवास, पांढुर्णा, टीकमगढ़, उज्जैन को एमएसएमई भवन की सौगात

मुख्यमंत्री ने देवास, पांढुर्णा, टीकमगढ़, उज्जैन को एमएसएमई भवन की सौगात भी दी। मंदसौर में मुल्तानपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 288 भू-खंड, मंडला में 165 भू-खंड, जबलपुर में 61 भू-खंड, बैतूल में 50 भू-खंड, कटनी के नवीन औद्योगिक क्षेत्र में 68 भू-खंड, नीमच के सरगना औद्योगिक क्षेत्र में 127 भू-खंड, खरगोन के डाबरिया औद्योगिक क्षेत्र में 103 भू-खंड दिए गए। प्ले एंड प्लग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एमएसएमई विभाग के बीच स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एमओयू भी साइन किए गए। समिट में मुख्यमंत्री ने कटनी और मंडला के उद्यमियों से संवाद भी किया।

एग्रीकल्चर सेक्टर को ऊंचाई पर लेकर जाएंगे

डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित मप्र का निर्माण करना भी जरूरी है। राज्य सरकार ने आगामी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को भोपाल में आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस पूरे वर्ष में एग्रीकल्चर सेक्टर को आधुनिक तरीके से नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे।

उद्योग विकास में मप्र ने हासिल की नई ऊंचाइयां

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि मप्र ने उद्योग विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल कीं हैं। जब नेतृत्व में दृष्टि हो तो एमएमएमई विभाग का बजट 1100 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ हो जाता है। राज्य सरकार ने विभाग का बजट बढ़ाकर सीधे तौर पर उद्यमियों को लाभ दिया है। उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है।

अस्पतालों-कोचिंग में अग्निकांड

सुप्रीम कोर्ट में कानून बनाने की मांग, सुरक्षा इंतजाम किए जाएं

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

देश में बार-बार होने वाले भीषण अग्निकांडों पर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस में केंद्र सरकार को देश भर के उच्च जोखिम वाले सार्वजनिक परिसरों के लिए एक राष्ट्रीय अग्नि और जीवन सुरक्षा ढांचा तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, साथ ही केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक मजबूत फायर सेफ्टी कानून बनाए। यह याचिका वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, होटल, रेस्तरां, मॉल और अस्पतालों के लिए एक सख्त नियम होना चाहिए। भारी भीड़ वाली इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हैं।

3 महीने में हो हर बिल्डिंग की जांच

याचिका में सभी राज्यों को एक बड़ा निर्देश देने की मांग की गई है। वकील ने कहा कि 3-4महीने के भीतर सभी राज्यों में फायर ऑडिट होना चाहिए। खासकर कोचिंग हब, स्कूल, अस्पताल और मॉल की जांच पहले हो। दिल्ली और लखनऊ में दो बड़े हादसे हुए। याचिका में इन हादसों का जिक्र है। वकील ने कहा कि देश में एक जैसा कड़ा कानून नहीं है। इसी वजह से बार-बार ऐसी लापरवाही और मौतें हो रही हैं। याचिका में लिखा है, हादसे के बाद सिर्फ कमेटी बनाना काफी नहीं है। हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। सरकार का काम केवल शोक मनाना नहीं, बल्कि हादसों को रोकना है।कोर्ट से कहा गया है कि सभी राज्य एक लिस्ट सौंपें। अदालत को बताया जाए कि कितनी बिल्डिंग बिना फायर एनओसी के चल रही हैं।

याचिका की 5 सबसे बड़ी बातें

- **राष्ट्रीय स्तर पर बने कड़ा नियम:** पूरे देश के सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले परिसरों के लिए एक समान और राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाए।
- **3-4 महीने में हो विशेष ऑडिट:** सभी राज्यों में स्कूल, कोचिंग, अस्पताल, होटल और मॉल का समय सीमा के भीतर सघन फायर ऑडिट हो।
- **अवैध निर्माणों पर लगे तुरंत रोक:** बिना मंजूरी के चल रहे बेसमेंट, छतों, अस्थायी ढांचों और अवैध मंजिलों पर क्लासरूम, लाइब्रेरी या रेस्तरां चलाने पर पूरी तरह पाबंदी हो।
- **दोषी अफसरों की तय हो जवाबदेही:** बिना फायर एनओसी के खतरनाक इमारतों को चलने देने वाले सरकारी अधिकारियों पर सीधे क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए।
- **हादसों के सबूत रखे जाएं सुरक्षित:** मालवीय नगर और अलीगंज जैसे हालिया हादसों के सीसीटीवी फुटेज, एनओसी और निरीक्षण रिकॉर्ड को तुरंत सील कर सुरक्षित करें।

विदेश मंत्रालय ने जारी की ई-नीलामी, 30 जून तक चलेगी

रोलेक्स घड़ी, चांदी के खंजर और 300 तोहफे होंगे नीलाम

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

विदेश मंत्रालय ने तोशाखाना में सुरक्षित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भारत सरकार के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को भेंट किए गए करीब 300 उपहारों की ई-नीलामी जारी की है। बता दें कि इस नीलामी में लग्जरी घड़ियों, आभूषणों, स्मृति चिन्हों, सजावटी वस्तुओं और अन्य दुर्लभ उपहारों को शामिल किया गया है। ई-नीलामी आठ जून से शुरू हुई थी और 30 जून तक चलेगी। तोशाखाना वह आधिकारिक भंडार है, जहां विदेश यात्राओं या भारत में विदेशी प्रतिनिधियों से सरकारी अधिकारियों को प्राप्त उपहार सुरक्षित रखे जाते हैं। पहली बार इन उपहारों की सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित होगी. इसमें केवल भारत के निवासी नागरिक पंजीकरण कर बोली लगा सकते हैं और खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी भी देश के भीतर ही की जाएगी।

बेंगलुरु में युवती का अपहरण

जिंदा जला अगवा करने वाला महिला, चालक कूदकर भागे

एजेंसी ▶▶ तुमकुरु

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक चलती कार अचानक जोरदार धमाके के साथ आग का गोला बन गई। हादसे में कार के भीतर युवक जलकर कंकाल बन गया। पुलिस को आशंका है कि यह आत्मघाती कदम था और युवक ने कार के भीतर ही किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। धमाके से ऐन पहले एक महिला और कार चालक कूदकर जान बचाई।

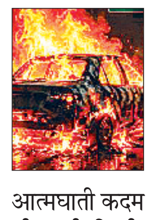

जानलेवा हमला और फिर जोरदार धमाका

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 30 वर्षीय नागेंद्र के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नागेंद्र ने बेंगलूरू के जयानगर स्थित सिद्धापुरा इलाके से एक कार बुक की थी। आरोप है कि उसने राम्या नाम की एक महिला को जबरन कार में बैठाया और उसका अपहरण कर लिया।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब की बेटी शर्मिष्ठा ने लेख साझा कर किया दावा

मेरे पिता का मानना था मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री को सीधे जनादेश नहीं मिला

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस की पूर्व नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक लेख में दावा किया है कि उनके दिवंगत पिता का मानना था कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जनता से सीधे जनादेश मिला। उन्होंने लिखा कि पहले नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई भी प्रधानमंत्री सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था।

किसी पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं मिला यह श्रेय

दोनों में अच्छे संबंध रहे

मुखर्जी ने लिखा- लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री को लेकर बहस के बीच मुझे प्रणब जी की 2014 में मोदी की जबरदस्त जीत पर कही गई दिलचस्प बात याद आती है। उस समय बाबा भारत के राष्ट्रपति थे।

3 दशकों के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत

उन्होंने कहा कि 3दशकों के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। तब बाबा ने प्रोफेसर वाले अंदाज में पूछा, और क्या? जब मोदी जी चुप रहे, तो बाबा ने बताया कि 2014 का चुनाव इतिहास में अनोखा था।

दो अलग-अलग मामलों में हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

माता-पिता के विवाद में बच्चों को नुकसान, जबरन 'पिस' रहे

चाइल्ड कस्टडी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चाइल्ड कस्टडी मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का सबसे अधिक नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टडी से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी या बच्चे को दूसरे अभिभावक को सौंपने में टालमटोल करने से नाबालिग को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ता है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

अदालत के चक्कर लगाना बच्चे के लिए नुकसानदायक

न्यायमूर्ति तेजस करिया और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि कस्टडी विवादों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बच्चे का कल्याण है। अदालत ने माना कि जब माता-पिता अपने विवाद के कारण बच्चे को समय पर दूसरे अभिभावक के पास नहीं भेजते, तो अंततः इसकी कीमत बच्चे को चुकानी पड़ती है। ऐसे मामलों में लगातार अदालत का रुख करना भी बच्चे के मानसिक विकास और भावनात्मक संतुलन के लिए उचित नहीं है।

माता-पिता के साथ सार्थक समय बिताने का है हक

पीठ ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को माता-पिता दोनों के साथ स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाए रखने का अधिकार है। यदि छुट्टियों के दौरान कस्टडी देने में देरी करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया, तो इससे बच्चे के हितों के साथ अभिभावकों के साथ उसके संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

झारखंड हाईकोर्ट ने की प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी

चाय-बिस्कुट ले गया नौकर उसे निकालना असंवेदनशील

रांची। झारखंड के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने संवेदनशील निर्णय सुनाते हुए एक संविदा चपरासी की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है। चपरासी को बहाल करने,50% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया है। उसने चाय- बिस्कुट निकाल लिया था।

रेस्क्यू टीम सदस्य सुनील ने किया चौंकाने वाला दावा

रेस्क्यू टीम को केतन का सिर कुचला मिला, शांत थी सिया

एजेंसी ▶▶ पुणे

सिया

केतन मर्डर केस में हर रोज नए-नए दावे सामने आ रहे हैं। केतन की रेस्क्यू करने वाली टीम के सदस्य सुनील गायकवाड़ ने दावा किया है कि केतन की खोपड़ी कुचली हुई थी, उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं और हाथ-पैर भी कई जगह चोट थीं। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद बाकी लोग मदद के लिए चिल्ला रहा थे, लोग रो रहे थे लेकिन सिया गोयल शांत खड़ी थी। गायकवाड़ ने बताया कि शव को जंगल के रास्ते बाहर लाया गया। 18 जून की सुबह 10:30 बजे घटना की जानकारी पुलिस को मिली थी। रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर 12:30 तक चला और करीब 1:30 बजे शव एंबुलेंस में पहुंचाया गया था।

पुलिस ने सिया के भाई साहिल गोयल से करीब 10 घंटे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, साहिल चेतन को जानता था। उनसे बताया कि चेतन और सिया की दोस्ती क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। साहिल गोयल ने पुलिस को बताया कि लिया उसके साथ क्रिकेट मैच देखने जाती थी।

मुंबई-दिल्ली नहीं, बल्कि छोटे शहर भी बन रहे हैं निवेश के हब

40% से अधिक नए एसआईपी टियर-2, 3 और 4 शहरों से, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में दावा : हर महीने 3 अरब डॉलर का निवेश
अगले दशक में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का हस्तांतरण, भारतीय बाजारों को मिलेगा बड़ा फायदा, निवेशक भी होंगे मालामाल

निवेश मंत्रा

बिजनेस डेस्क

भारत में निवेश का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अब केवल महानगर ही नहीं, बल्कि टियर-2, टियर-3 और टियर-4 शहर भी निवेश वृद्धि के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में शुरू होने वाले 40 फीसदी से अधिक नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) छोटे शहरों से आ रहे हैं। मासिक एसआईपी निवेश 3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो भारतीय शेयर बाजार को स्थिर और दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध करा रहा है। भारतीय निवेश बाजार में छोटे शहरों की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बाजारों को खुदरा निवेशकों और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (एचएनआई) दोनों वर्गों की बढ़ती भागीदारी का लाभ मिलेगा। भारत में वर्तमान में हर महीने करीब 3 अरब डॉलर का एसआईपी निवेश आ रहा है। पीडब्ल्यूसी ने इसे प्राइस इंसेंसिटिव इक्विटी फ्लो बताया है, क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशक नियमित निवेश जारी रखे हुए हैं। इससे शेयर बाजार को स्थिर और दीर्घकालिक पूंजी मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू निवेशकों की बढ़ती ताकत भारतीय बाजार को वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाने में भी मदद कर रही है। देश में डिजिटल क्रांति ने निवेश के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जहां निवेश की सुविधा मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित थी, वहीं अब मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल केवाईसी जैसी सुविधाओं ने छोटे शहरों के लोगों को भी बाजार से जोड़ दिया है। यही वजह है कि अब निवेश का नया केंद्र छोटे शहर और कस्बे बनते जा रहे हैं।

क्या कहता है अनुमान

रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 वर्षों में भारत में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होगी। इस वेल्थ ट्रांसफर का बड़ा हिस्सा वित्तीय उत्पादों, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं की ओर जा सकता है। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में एचएनआई आबादी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज गति से बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संपत्ति हस्तांतरण भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। नई पीढ़ी पारंपरिक निवेश साधनों की तुलना में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य आधुनिक वित्तीय उत्पादों में अधिक रुचि दिखा रही है। इससे निवेश उद्योग को नई गति मिलने की संभावना है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी रिपोर्ट में निवेश वृद्धि का प्रमुख आधार बताया गया है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल-फर्स्ट निवेशक वर्ग और एआई आधारित वित्तीय सेवाओं ने निवेश को आसान और सुलभ बनाया है। यही कारण है कि छोटे शहरों से निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें

- 40% से अधिक नए एसआईपी टियर-2, 3 और 4 शहरों से।
- हर महीने करीब 3 अरब डॉलर का एसआईपी निवेश।
- अगले 10 वर्षों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की पीढ़ीगत संपत्ति हस्तांतरण की संभावना।
- 2030 तक भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आबादी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज गति से बढ़ने का अनुमान।
- भारत वैश्विक निवेशकों और भारतीय पूंजी के लिए दोतरफा निवेश गलियारा बन रहा है।

छोटे शहरों से क्यों बढ़ रहा निवेश

- इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में तेजी
- डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार
- म्यूचुअल फंड कंपनियों की बढ़ती पहुंच
- युवाओं में निवेश के प्रति जागरूकता
- वित्तीय शिक्षा और निवेश अभियानों का असर
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना ताकत

क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार भारत का मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी एआई इंजीनियरिंग प्रतिभा, मोबाइल-फर्स्ट निवेशक वर्ग और नवाचार आधारित वित्तीय प्रणाली उसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों से आगे खड़ा करती है। देश में मौजूद विशाल डिजिटल नेटवर्क निवेशकों को कम लागत और कम समय में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। जीआईएफटी सिटी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय निवेश अवसरों को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह भारत के लिए एक समयबद्ध अवसर है, जो देश को वैश्विक वित्तीय सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है।

एशिया-प्रशांत में भारत की बढ़त

पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि 2026 से 2030 के बीच एशिया-प्रशांत क्षेत्र का एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट बाजार 6.8 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़ेगा। यह उत्तर अमेरिका के 6.2 फीसदी और यूरोप के 5.6 फीसदी की तुलना में अधिक है। भारत इस वृद्धि का प्रमुख लाभार्थी बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत आर्थिक विकास, युवा आबादी और बढ़ती आय भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक बाजारों में शामिल कर रही है।

निवेश के उभरते अवसर

म्यूचुअल फंड, पैसिव फंड, शेयर बाजार, वैकल्पिक निवेश, प्राइवेट क्रेडिट, वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं, वैकल्पिक निवेश में बड़ा अवसर

निवेशकों के लिए संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे शहरों से बढ़ती निवेश भागीदारी बाजारों को अधिक गहराई और स्थिरता प्रदान करेगी। बढ़ती वित्तीय जागरूकता, डिजिटल पहुंच और लंबी अवधि की निवेश संस्कृति आने वाले वर्षों में भारतीय पूंजी बाजारों की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है तो भारत वैश्विक निवेश मानचित्र पर और अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई देगा और घरेलू निवेशक इसकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे।

निवेश विशेषज्ञ अब दे रहे सोने से दूर रहने की सलाह

सुझाव

बिजनेस डेस्क

पिछले कुछ वर्षों में सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और डॉलर पर घटते भरोसे जैसे कारणों से सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन अब एक ऐसे निवेश विशेषज्ञ, जिनकी पिछली कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, निवेशकों को सोने से दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं। मौजूदा स्तर पर सोना आकर्षक निवेश नहीं रह गया है। उनके अनुसार इक्विटी और डेट मार्केट फिलहाल निवेशकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं। नवंबर 2023 में जब निवेशकों का भरोसा सोने पर कमजोर था और बाजार में नकारात्मक माहौल था, तब बुलियन में निवेश की जोरदार पैरवी की थी। बाद में चांदी की कीमतों को लेकर भी उनकी चेतावनी काफी हद तक सही साबित हुई। अब उनका कहना है कि जो परिस्थितियां पहले सोने के पक्ष में थीं, वे काफी हद तक बदल चुकी हैं। इसलिए नए निवेश के लिए सोना उनकी प्राथमिकता नहीं है।

ईटीएफ निवेश ने बढ़ाई कीमतें

हाल की तेजी में केवल केंद्रीय बैंकों की खरीदारी ही नहीं, बल्कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आए बड़े निवेश का भी योगदान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी एसेट में अत्यधिक उत्साह पैदा हो जाता है, तो उसके रिटर्न की संभावनाएं धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।

इक्विटी में दिख रहा बेहतर मूल्यांकन

भारतीय शेयर बाजार में 2024 के दौरान वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए थे। लेकिन बाद की गिरावट और करेक्शन के बाद अब कई सेक्टर और कंपनियां अधिक उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। उनके अनुसार अगले 3 से 5 वर्षों में इक्विटी बाजार सोने की तुलना में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। खासकर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत विकास दर, बढ़ता घरेलू निवेश और कॉरपोरेट आय में सुधार की संभावनाएं इक्विटी बाजार के पक्ष में नजर आती हैं। यही वजह है कि कई फंड मैनेजर अब सोने की बजाय शेयर बाजार को प्राथमिकता दे रहे हैं।

बेहतर यील्ड का फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में डेट मार्केट भी निवेशकों को आकर्षक अवसर प्रदान कर रहा है। ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड के मौजूदा स्तर कई निवेशकों के लिए अच्छा जोखिम-रिटर्न संतुलन पेश कर रहे हैं। डेट निवेश उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो नियमित आय, अपेक्षाकृत कम जोखिम और पोर्टफोलियो में स्थिरता चाहते हैं।

10 लाख हों तो क्या करें?

यदि किसी निवेशक के पास 10 लाख रुपये निवेश के लिए उपलब्ध हैं, तो फिलहाल सोने में अतिरिक्त निवेश से बचना बेहतर हो सकता है। इसके बजाय राशि को इक्विटी और डेट निवेश के बीच संतुलित रूप से बांटना अधिक उपयुक्त रणनीति हो सकती है। हालांकि निवेश का अनुपात प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, जोखिम क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और निवेश अवधि के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

क्या सोने को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए?

यह समझना जरूरी है कि किसी विशेषज्ञ द्वारा सोने को कम आकर्षक बताने का अर्थ यह नहीं है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो से सोना पूरी तरह हटा दें। वित्तीय योजनाकार आमतौर पर कुल पोर्टफोलियो का 5% से 10% हिस्सा सोने में रखने की सलाह देते हैं ताकि विविधीकरण बना रहे। सोना अब भी भू-राजनीतिक संकट, मुद्रास्फीति और बाजार की अनिश्चितता के समय सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। लेकिन वर्तमान मूल्य स्तरों पर असाधारण रिटर्न की उम्मीद करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

क्यों बदल गया सोने का निवेश समीकरण?

पहले वैल्यूएशन आकर्षक था : विशेषज्ञों के अनुसार कुछ साल पहले सोना अपेक्षाकृत कम कीमतों पर उपलब्ध था। उस समय डी-डॉलराइजेशन, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक आर्थिक चिंताओं जैसे कारक सोने के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे थे। हालांकि आज स्थिति अलग है। पिछले वर्षों की तेज बढ़त के बाद सोने की कीमतों में काफी वृद्धि हो चुकी है और निवेशकों का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया है। ऐसे माहौल में आगे की तेजी की संभावना सीमित हो सकती है।

नॉर्मल, फिक्स्ड टॉप-अप और वैरिएबल टॉप-अप एसआईपी

● छोटी बढ़ोतरी से करोड़ों का बन सकता है अतिरिक्त फंड ● 25 साल में रिटर्न का बड़ा अंतर, आय बढ़ने के साथ एसआईपी बढ़ाना जरूरी ● 10 हजार रुपये की मासिक एसआईपी पर वैरिएबल टॉप-अप से बन सकता है 4.46 करोड़ तक का फंड

म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे लोकप्रिय और आसान तरीका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) माना जाता है। छोटी-छोटी रकम को नियमित रूप से निवेश कर लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि बीते कुछ वर्षों में एसआईपीनि वेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एसआईपी शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय के साथ निवेश राशि को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बढ़ती आय के साथ यदि एसआईपी राशि भी बढ़ाई जाए तो लंबी अवधि में रिटर्न कई गुना बढ़ सकता है। निवेशकों के लिए सामान्य तौर पर तीन प्रकार की एसआईपी रणनीतियां उपलब्ध हैं। इनमें नॉर्मल एसआईपी , फिक्स्ड टॉप-अप एसआईपी और वैरिएबल टॉप-अप एसआईपी शामिल हैं। तीनों का उद्देश्य नियमित निवेश करना है, लेकिन निवेश राशि बढ़ाने के तरीके और अंतिम फंड में काफी अंतर देखने को मिलता है।

क्या है नॉर्मल एसआईपी

नॉर्मल एसआईपी सबसे सामान्य और पारंपरिक निवेश विकल्प है। इसमें निवेशक हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और पूरी अवधि के दौरान यह राशि समान रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये मासिक एसआईपी शुरू की है तो अगले वर्ष और उसके बाद भी वह हर महीने 10,000 रुपये ही निवेश करेगा। नॉर्मल एसआईपी उन लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो निवेश में सरलता चाहते हैं और अपनी मासिक बचत को एक निश्चित सीमा में रखना पसंद करते हैं। हालांकि इसमें एक कमी यह है कि आय बढ़ने के बावजूद निवेश राशि नहीं बढ़ती, जिससे लंबी अवधि में संभावित फंड का आकार सीमित रह सकता है।

जानकारी

बिजनेस डेस्क

नॉर्मल एसआईपी की विशेषताएं

■ हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश ■ निवेश प्रक्रिया सरल और आसान ■ बजट प्रबंधन में सुविधा ■ नए निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प ■ आय बढ़ने का पूरा लाभ निवेश में नहीं जुड़ता

क्या है फिक्स्ड टॉप-अप एसआईपी

फिक्स्ड टॉप-अप एसआईपी उन निवेशकों के लिए बनाई गई है जो अपनी एसआईपी राशि को समय-समय पर बढ़ाना चाहते हैं। इसमें निवेशक हर वर्ष अपनी मासिक एसआईपी में एक निश्चित रकम जोड़ता है। यह बढ़ोतरी पहले से तय होती है और हर साल समान रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई निवेशक 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू करता है और हर साल 1,000 रुपये का टॉप-अप चुनता है, तो अगले साल उसकी एसआईपी 11,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये और उसके बाद 13,000 रुपये हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह विकल्प उन वेतनभोगी लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें हर साल नियमित वेतन वृद्धि मिलती है। इससे आय बढ़ने के साथ निवेश भी बढ़ता रहता है और लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है।

फिक्स्ड टॉप-अप एसआईपी के फायदे

■ हर साल निवेश राशि में बढ़ोतरी ■ वेतन वृद्धि का लाभ निवेश में शामिल ■ लंबी अवधि में अधिक संपत्ति निर्माण ■ निवेश योजना पहले से तय रहती है ■ वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद

क्या है वैरिएबल टॉप-अप एसआईपी

वैरिएबल टॉप-अप एसआईपी सबसे उन्नत और आक्रामक एसआईपी रणनीति मानी जाती है। इसमें निवेशक हर साल अपनी एसआईपी राशि को एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर बढ़ाता है। यह प्रतिशत 5, 10 या 15 फीसदी हो सकता है। मान लीजिए किसी निवेशक ने 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू की और 10 फीसदी वार्षिक टॉप-अप चुना। ऐसे में अगले साल उसकी एसआईपी 11,000 रुपये होगी। दूसरे साल यह 12,100 रुपये और तीसरे साल 13,310 रुपये तक पहुंच जाएगी। यानी हर साल बढ़ी हुई राशि पर भी वृद्धि का लाभ मिलता है।

वैरिएबल टॉप-अप एसआईपी बेहतर क्यों

■ प्रतिशत आधारित वृद्धि ■ बढ़ी हुई राशि पर भी कंपाउंडिंग का लाभ ■ लंबी अवधि में सबसे अधिक फंड बनने की संभावना ■ बढ़ती आय वाले युवाओं के लिए उपयुक्त ■ महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में मदद

25 साल में कितना बन सकता है फंड

यदि कोई निवेशक 25 वर्षों तक हर महीने 10,000 रुपये से निवेश शुरू करता है तो तीनों एसआईपी विकल्पों में अंतिम फंड का आकार काफी अलग हो सकता है।

एसआईपी	कुल निवेश	
नॉर्मल	30 लाख रु.	2.27 करोड़ रु.
फिक्स्ड टॉप-अप	66 लाख रु.	3.44 करोड़ रु.
वैरिएबल	1.18 करोड़ रु	4.46 करोड़ रु

निवेशकों के लिए सही विकल्प क्या

सही एसआईपी रणनीति का चुनाव निवेशक की आय, वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति की आय सीमित है और वह निवेश को सरल रखना चाहता है तो नॉर्मल एसआईपी बेहतर विकल्प हो सकती है। वहीं जिन लोगों की आय हर साल बढ़ती है, उनके लिए फिक्स्ड टॉप-अप एसआईपी अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरी ओर युवा निवेशक, पेशेवर और तेजी से बढ़ती आय वाले लोग वैरिएबल टॉप-अप एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में बड़ा कोष तैयार कर सकते हैं।

अलर्ट सही अवधि का चुनाव बढ़ा सकता है रिटर्न, सुरक्षित होगा भविष्य, ब्याज दर के साथ निवेश अवधि और वित्तीय लक्ष्य भी हैं अहम

सही एफडी का चुनाव बढ़ा सकता है आपकी कमाई और बचत

1, 3 या 5 साल... किस फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलेगा ज्यादा मुनाफा? ब्याज दर, टैक्स और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख करें निवेश

समझदारी

बिजनेस डेस्क

शेयर बाजार की उठापटक के बीच यदि कोई निवेश विकल्प आज भी सबसे भरोसेमंद माना जाता है तो वह है फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी)। पूंजी की सुरक्षा और पहले से तय रिटर्न के कारण एफडी आज भी लाखों निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है। खासकर नौकरीपेशा, वरिष्ठ नागरिक और जोखिम से बचने वाले निवेशक एफडी को सुरक्षित निवेश मानते हैं। हालांकि एफडी में निवेश करते समय सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि 1 साल, 3 साल या 5 साल में से किस अवधि की एफडी सबसे अधिक लाभ देगी।

इसका जवाब केवल ब्याज दरों में नहीं छिपा है। सही एफडी का चुनाव आपकी वित्तीय जरूरत, निवेश की अवधि, ब्याज दरों के रुझान और टैक्स प्लानिंग पर निर्भर करता है। वर्तमान में विभिन्न सरकारी, निजी और स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग-अलग अवधि पर अलग ब्याज दरें दे रहे हैं। ऐसे में निवेश करने से पहले इनकी तुलना करना जरूरी हो जाता है।

1 साल की एफडी : कम समय के लिए बेहतर विकल्प

अगर आप अपना पैसा लंबे समय तक लॉक नहीं करना चाहते या निकट भविष्य में पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो 1 साल की एफडी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। इस अवधि की एफडी में निवेशक को यह सुविधा मिलती है कि मैच्योरिटी के बाद वह उस समय की नई ब्याज दरों के अनुसार दोबारा निवेश कर सकता है। यदि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इसका फायदा भी आसानी से उठाया जा सकता है। वर्तमान में स्मॉल फाइनेंस बैंक इस अवधि में सबसे अधिक ब्याज दे रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल की एफडी पर 7.25 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं, जबकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.10 प्रतिशत की दर ऑफर कर रहा है। निजी बैंकों में यस बैंक 6.65 प्रतिशत, जबकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक 6.25 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं। सरकारी बैंकों में एसबीआई 6.25 प्रतिशत और बैंक ऑफ इंडिया 6.50 प्रतिशत तक ब्याज दे रहा है।

3 साल की एफडी : रिटर्न व अवधि का बेहतरीन संतुलन

जो निवेशक मध्यम अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और बिना बहुत लंबा इंतजार किए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, उनके लिए 3 साल की एफडी आकर्षक विकल्प मानी जाती है। इस अवधि में कई बैंक 1 साल की तुलना में अधिक ब्याज दे रहे हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल की एफडी पर 7.50 प्रतिशत तक ब्याज की पेशकश कर रहे हैं। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.35 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की 3 वर्षीय टाइम डिपॉजिट योजना पर 7.10 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 6.45 प्रतिशत, जबकि एसबीआई 6.30 प्रतिशत ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।

5 साल की एफडी : टैक्स बचत

यदि आपका उद्देश्य लंबी अवधि का निवेश करना है और साथ ही आयकर में बचत भी करनी है तो 5 साल की टैक्स-सेवर एफडी सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इस एफडी में निवेश करने पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ लिया जा सकता है। 5 साल की अवधि में भी स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे अधिक ब्याज दे रहे हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.90 प्रतिशत, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.77 प्रतिशत और डीसीबी बैंक 7.50 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं। बड़े निजी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक 6.50% और एचडीएफसी बैंक 6.40% ब्याज की पेशकश कर रहे हैं। वहीं सरकारी बैंकों में एसबीआई 6.05 प्रतिशत, बैंक ऑफ इंडिया 6 प्रतिशत और पंजाब नेशनल बैंक 5.95 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।

सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त फायदा

लगभग सभी बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में 0.25 से 0.75 प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज देते हैं। कई बैंक सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी विशेष ब्याज दरें लागू करते हैं। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को निवेश से पहले बैंक की विशेष एफडी योजनाओं की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए।

सिर्फ ब्याज दर देखकर फैसला न करें

निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि एफडी चुनते समय केवल सबसे अधिक ब्याज दर पर ध्यान देना सही रणनीति नहीं है। बैंक की विश्वसनीयता, जमा राशि की सुरक्षा, समय से पहले निकासी के नियम, ब्याज भुगतान का विकल्प और आपकी वित्तीय जरूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि निवेश की अवधि कम है तो 1 साल की एफडी बेहतर हो सकती है, जबकि मध्यम अवधि के लक्ष्य के लिए 3 साल और टैक्स बचत व लंबी अवधि के लिए 5 साल की एफडी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है।

किसके लिए कौन-सी एफडी?

1 साल की एफडी

- कम अवधि का निवेश
- पैसों की जल्द जरूरत होने की संभावना
- ब्याज दर बढ़ने पर दोबारा निवेश का अवसर

3 साल की एफडी

- बेहतर रिटर्न और संतुलित अवधि
- मध्यम अवधि के वित्तीय लक्ष्य
- जोखिम कम, रिटर्न अपेक्षाकृत बेहतर

5 साल की एफडी

- लंबी अवधि का सुरक्षित निवेश
- धारा 80सी के तहत टैक्स बचत
- भविष्य के बड़े वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयुक्त

निवेश टिप्स

- निवेश का उद्देश्य और अवधि पहले तय करें।
- विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें।
- केवल अधिक ब्याज के बजाय बैंक की विश्वसनीयता भी देखें।
- टैक्स बचत चाहिए तो 5 साल की टैक्स-सेवर एफडी चुनें।
- वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ अवश्य लें।
- मैच्योरिटी के बाद राशि का पुनर्निवेश करने की योजना पहले से बनाएं।

उरुग्वे टूर्नामेंट से बाहर, नॉकआउट में स्पेन

ग्वाडालाजारा। स्पेन ने गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा की एक और गलती का फायदा उठाते हुए उरुग्वे को 1-0 से हराकर विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और दक्षिण अमेरिका की दिग्गज टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। दो बार की चैंपियन उरुग्वे की टीम ग्रुप एच में एक भी मैच नहीं जीत सकी। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने सात अंकों के साथ ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया और अगले दौर में उसका सामना गुरुवार को कैलिफोर्निया के इंगलवुड में ग्रुप जे से दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम (ऑस्ट्रेलिया या अल्जीरिया) से होगा। स्पेन के लिए एलेक्स बाएना ने 42वें मिनट में गोल दागा, जब मुस्लेरा पेनल्टी एरिया के अंदर से लगाए गए उनके शॉट को रोकने में नाकाम रहे जबकि यह मुश्किल नहीं लग रहा था। 40 वर्षीय मुस्लेरा की यह टूर्नामेंट में तीसरी गलती थी, जिसके बाद कोच मार्सेलो बिएल्सा ने उन्हें हाफ टाइम में ही बाहर कर दिया।

सेनेगल ने की इराकी टीम पर गोलों की बारिश

टोरंटो। स्थानापन्न खिलाड़ी पेप गुये के दो गोल की मदद से सेनेगल ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे इराक पर 5-0 की शानदार जीत हासिल करके विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। इराक के रेबिन सलाका को 13वें मिनट में ही लाल कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया था और इसके बाद उसे 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, जिसका सेनेगल ने पूरा फायदा उठाया। सेनेगल की तरफ से हबीब दियारा ने चौथे मिनट में ही गोल कर दिया था। इससे वह मध्यांतर तक 1-0 से आगे था। उसने दूसरे हाफ में गोल की झड़ी लगा दी। इस्माइला सर्र ने 56वें मिनट में गोल करके स्कोर 2-0 कर दिया। इसके बाद पेप गुये ने 59वें और 71वें मिनट में गोल किए। उसकी तरफ से आखरी गोल 82वें मिनट में इलिमन नदिये ने किया। सेनेगल ग्रुप आई में फ्रांस और नॉर्वे से हार गया था लेकिन इराक पर जीत से उसने तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए।

केप वर्दे नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश

ह्यूस्टन। केप वर्दे ने अपना स्वप्निल अभियान जारी रखते हुए सऊदी अरब के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला और इस तरह से विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बन गया। उसकी यह उपलब्धि 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा के शानदार खेल के दम पर संभव हुई है, जिन्होंने अपने देश की दृढ़ता का प्रतीक बनकर सबको प्रभावित किया है। वोजिन्हा ने कहा, हम भले ही (क्षेत्रफल में) छोटे हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हम हार नहीं मानते। हम जुझारू हैं। केप वर्दे ने ग्रुप एच में अपने तीनों मैच ड्रॉ कराए, जिससे वह स्पेन के बाद दूसरे स्थान पर रहकर आगे बढ़ने में सफल रहा। इस ग्रुप में उरुग्वे और सऊदी अरब के दो-दो अंक ही हासिल कर पाए और वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित छोटा द्वीपीय राष्ट्र केप वर्दे फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर पहली बार खेल रहा है।

मिस्र ने पहली बार बनाई राउंड ऑफ 32 में जगह

सिएटल। मिस्र ने महमूद साबेर के शुरू में किए गए गोल के बावजूद कुछ विषम पलों से गुजरते हुए ईरान के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण मैच को 1-1 से ड्रॉ खेला और पहली बार विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में जगह बनाई। ईरान ने गोल करने के अधिक मौके बनाए। इनमें संभावित विजयी गोल भी शामिल था, जिसे ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया। उसे अब अपने भाग्य का पता लगाने के लिए एक दिन इंतजार करना होगा जब टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आठ टीम का निर्धारण होगा। मिस्र ने पांचवें मिनट में साबेर के गोल से शुरुआती बढ़त हासिल कर ली। मोहम्मद सालाह ने बॉक्स के अंदर शानदार खेल दिखाया, जिसके बाद साबेर ने ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंद के पैरों के बीच से शॉट मारकर गोल कर दिया। ईरान ने नौ मिनट बाद रामिन रेज़ेयान के गोल से मैच को बराबरी पर ला दिया। उसने दूसरे हाफ के इंजरी टाइम के तीसरे मिनट में विजयी गोल कर दिया था जब शोजा खलीलज़ादेह ने गोल में शॉट लगाया, लेकिन वीडियो समीक्षा के बाद उसे ऑफसाइड करार दिया गया। अगर यह गोल मान्य होता तो ईरान नॉकआउट राउंड में अपनी जगह पक्की कर लेता।

डेम्बेले ने रचा इतिहास, फ्रांस की नार्वे पर 4-1 से धमाकेदार जीत

32 साल बाद पहले हाफ में हैट्रिक

एजेंसी ▶▶| फॉक्सबोरो

स्ट्राइकर उस्मान डेम्बेले ने पहले हाफ में ही हैट्रिक बनाई, जिससे फ्रांस ने विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप आई में नॉर्वे को 4-1 से हराकर अपना विजय अभियान जारी रखा। डेम्बेले ने सातवें, 20वें और 32वें मिनट में गोल किए। उनके एक गोल में काइलियन एमबाप्पे ने मदद की।

विश्व कप में पिछले 32 वर्षों में यह पहला अवसर था जबकि किसी खिलाड़ी ने पहले हाफ में ही हैट्रिक बनाई। इससे पहले 1994 में अमेरिका में खेले गए विश्व कप में रूस के फॉरवर्ड ओलेग सालेन्को ने कैमरून के खिलाफ अपने पांच में से तीन गोल शुरुआती 45 मिनट में किए थे। डेम्बेले इस तरह से लियोनेल मेस्सी और अपने साथी एमबाप्पे के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल हो गए हैं।

फ्रांस की टीम ने बनाए रखा दबदबा

डेम्बेले ने कहा, 'यह एक अनूठा क्षण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने ग्रुप चरण में पहल स्थान पर रहकर अगले दौर में प्रवेश किया। अब हमारा ध्यान अगले मैच पर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है।' फ्रांस और नॉर्वे पहले ही नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर चुके थे और इस मैच से ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम का फैसला होना था। फ्रांस की टीम ने दबदबा बनाए रखा। उसकी तरफ से चौथा गोल दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम में डेसिरे डोउ ने किया। नॉर्वे के लिए एकमात्र गोल थैलो आसगार्ड ने 21वें मिनट में किया। फ्रांस ने तीन मैचों में 10 गोल किए हैं। डेम्बेले ने कहा, 'हम अपने सभी मैच जीतना चाहते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे।'

बेल्जियम की न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत, ग्रुप जी में शीर्ष पर

वैंकूवर। लिएंड्रो ट्रोसार्ड (28वें और 50वें मिनट) के दो गोल की बदौलत बेल्जियम ने विश्व कप फुटबॉल में धीमी शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड पर 5-1 से जीत हासिल कर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इस जीत से बेल्जियम ने पांच अंकों के साथ ग्रुप जी में शीर्ष स्थान हासिल किया और वह अगले दौर में बुधवार को सिएटल में तीसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आठ टीमों में से किसी एक टीम का सामना करेगा। ग्रुप जी में मिस्र ने भी पांच अंक हासिल किए लेकिन वह बेल्जियम से गोल अंतर में पीछे रहने के कारण दूसरे स्थान पर रहा।

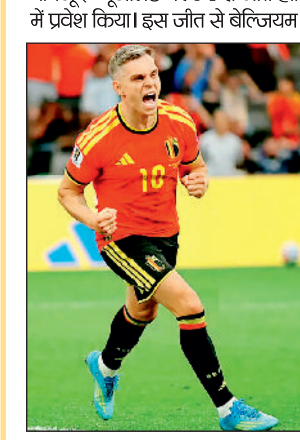

केविन डी ब्रुइन (66वें), रोमेलु लुकाकू (86वें) और एलेक्सिस सैलेमेकर्स (इंजरी टाइम के चौथे मिनट) ने भी बेल्जियम के लिए गोल किए। इससे उसने बड़ी जीत सुनिश्चित करके ग्रुप में पहला स्थान भी हासिल कर लिया। बेल्जियम चार साल पहले कतर में खेले गए विश्व कप में ग्रुप चरण से ही बाहर हो गए था, जबकि उसने रूस में विश्व कप 2018 में तीसरा स्थान हासिल किया था। न्यूजीलैंड के लिए एलिजा जस्ट ने 84वें मिनट में गोल किया। उसे नॉक आउट चरण में जगह बनाने के लिए इस मैच में जीत की दरकार थी लेकिन अब उसे वापस घर लौटना होगा।

खबर संक्षेप

देविका ने किया उलटफेर रिको गुंजी को हराया

फुलर्टन। देविका सिहाग ने जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी को हराकर बड़ा उलटफेर करके अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया जबकि रौनक चौहान ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए अंतिम चार में जगह बनाई। देविका ने महिला एकल क्वार्टरफाइनल में दोनों गेम के अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखते हुए गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया। रौनक चौहान ने इजरायल के मिशा जिल्बरमैन को सिर्फ 38 मिनट में 23-21, 21-11 से पराजित किया। वह पहली बार किसी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इसके बाद अनुभवी खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झूओ-फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराकर रविवार को भारत के दो खिलाड़ियों के बीच फाइनल की उम्मीदें बढ़ा दीं।

963 दिन बाद वापसी फीकी, जीत के साथ दौरा खत्म करना चाहेंगे अय्यर

एजेंसी ▶▶| बेलफास्ट

आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती मुकाबले में चौकाने वाली हार का सामना करने के बाद भारत की स्टार खिलाड़ियों से सजे शीर्ष बल्लेबाज़ी क्रम पर रविवार को होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा। श्रेयस अय्यर की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 963 दिनों बाद वापसी और राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। वह बुधवार से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला शुरू होने से पहले आयरलैंड दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेंगे।

बिखरी टीम इंडिया की बल्लेबाजी

भारतीय टीम की सबसे बड़ी समस्या बल्लेबाजी का बिखर जाना रही। तीन महीने पहले विश्व कप में नायक रहे संजू सैमसन सिर्फ चार गेंद खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन और अय्यर भी बल्ले से कोई खास योगदान नहीं दे सके। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक खेल जारी रखा और अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिला। पावरप्ले के बाद उनका आउट होना भारत की पारी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ।

आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला आज शाम 6 बजे से

राणा ने किया अच्छा प्रदर्शन

गेंदबाजी में कुछ सकारात्मक बातें भी रहीं। हर्षित राणा ने चोट से वापसी करते हुए 24 रन देकर 3 विकेट के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने भी अंतिम ओवरों में बेहतर गेंदबाजी की। टीम को सबसे अधिक नुकसान वॉशिंगटन सुंदर के एक ओवर में 19 रन और प्रसिद्ध कृष्णा के चार ओवरों में 57 रन लुटाने से हुआ। कृष्णा ने पारी के 17वें ओवर में 27 रन दिए।

आयरलैंड का मनोबल ऊंचा

आयरलैंड की ओर से कप्तान लोर्कान टकर ने 50 रन और गैरेथ डेलानी ने 49 रन की अहम पारियां खेलीं, जिससे टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। श्रृंखला के शुरुआती मैच में इतिहास रचने के बाद आयरलैंड का मनोबल ऊंचा है, जबकि भारतीय टीम श्रृंखला गंवाने की शर्मनाक स्थिति से बचने के साथ-साथ इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहेगी।

महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच शाम 7 बजे से

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का हाई-वोल्टेज मुकाबला आज

एजेंसी ▶▶| लंदन

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 28 जून (रविवार) को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा।

टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में अभी तक चार मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 3 में जीत मिली है। वहीं एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर दोनों देशों के फैंस के बीच भारी उत्साह है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 38 मैच खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया को सिर्फ 9 में जीत मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 27 मुकाबले जीतने में कामयाब रही है। दोनों टीमों के बीच एक मैच टाई रहा है और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया। ये आंकड़े बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हमेशा से भारतीय महिला टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए अपने खेल के हर डिपार्टमेंट बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

एशियाई खेलों में मैदान पर उतरेंगे नीरज

एजेंसी ▶▶| भुवनेश्वर

भारतीय भाला फेंक के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में अपने खिताब का बचाव करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) की चयन समिति के अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला ने इसकी पुष्टि की। चोपड़ा सितंबर 2025 में तोक्यो विश्व चैंपियनशिप से पहले पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट से उबर गए हैं। उन्होंने हाल में दोहा डायमंड लीग से अपने सत्र की शुरुआत की, जहां उन्होंने 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता 28 वर्षीय चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे या नहीं। सुमारीवाला ने कहा, 'वह (चोपड़ा) राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों दोनों में भाग लेंगे। उन्होंने क्वालीफाई कर लिया है और वह अभी चोट से पूरी तरह उबरने की प्रक्रिया में है।

एफआईएच प्रो लीग

भारत ने की पाकिस्तान पर गोल की वर्षा

पाकिस्तान को दी 7-1 से करारी शिकस्त

एजेंसी ▶▶| लंदन

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के दूसरे मैच में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। भारत ने शुरू में गोल खाने के बाद शानदार वापसी की और इसके बाद गोल वर्षा कर दी। उसकी तरफ से सुखजीत सिंह (20वें), हरमनप्रीत सिंह (26वें), हार्दिक सिंह (34वें), जुगराज सिंह (35वें), अभिषेक (41वें), राज कुमार पाल (44वें) और दिलप्रीत सिंह (54वें) ने गोल किए। मिडफील्डर हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

भारतीय खिलाड़ियों ने खेला आक्रामक खेल

भारत ने दूसरे हाफ में अपना दबदबा बरकरार रखा। उसे 34वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर के चलते पेनल्टी मिली, जिसे हार्दिक ने गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया। पाकिस्तान ने लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने उसके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारत ने इसके बाद जवाबी हमला किया। दिलप्रीत ने सुखजीत के साथ शानदार तालमेल बिठाते हुए जुगराज को पास दिया, जिन्होंने 35वें मिनट में शानदार गोल दागकर स्कोर 4-1 कर दिया। भारत ने आक्रामक रवैया जारी रखा, जिसका उसे तब फायदा मिला जब सुखजीत ने अभिषेक को पास दिया, जिन्होंने 41वें मिनट में दौड़ते हुए गोल दाग दिया। भारत को तीसरे क्वार्टर के आखिर में लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर मिले। इनमें से एक पर राज कुमार पाल ने रिबाउंड पर गोल किया और टीम की बढ़त को 6-1 कर दिया। अंतिम क्वार्टर में भारत ने रक्षापंक्ति में अनुशासन बनाए रखा और साथ ही आक्रमण जारी रखा।

अंडर-15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में देश के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते

रोहतक। अंडर-15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो पदक जीते। शनिवार को ग्रीको रोमन शैली के मुकाबले खेले गए। यह प्रतियोगिता 27 जून से 5 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। इसमें भारत ने एक स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य सहित कुल 5 पदक हासिल किए। 62 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, दर्पण चौधरी ने फाइनल में ताजिकिस्तान के अमरिदीन कुरबोनोव पर 5-0 से आसान जीत दर्ज कर भारत के लिए दिन का एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किया। यश (48 किलोग्राम) और जतिन (85 किलोग्राम) को कजाकिस्तान के रोलन किम और येराली मुरातोव से अपने-अपने फाइनल में 0-8 के समान अंतर से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस बीच, परयास धौंचक ने 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया, उन्होंने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर तुर्कमेनिस्तान के मुहम्मद उलुगबेकोव को 8-0 से हराया। 75 किलोग्राम में गौरव ने रजत पदक जीता। अन्य तीन भारतीय पहलवान, सौरभ (38 कि.ग्रा.), राजवीर सिंह (44 कि.ग्रा.) और तुषार खोखर (52 कि.ग्रा.) अपने-अपने कांस्य पदक के प्लेऑफ में हार गए और पांचवें स्थान पर रहे।

नेशनल बॉक्सिंग : प्रणव, माही, कनिष्का, वंश, कुनाल और शिया सेमीफाइनल में

रोहतक। पंजाब की एलपीयू यूनिवर्सिटी में खेली जा रही नेशनल अंडर-15 बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने रिंग में अपनी तकनीक और ताकत का लोहा मनवाते हुए धमाकेदार अंदाज में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 29 जून तक आयोजित की जाएगी।

ये रहे परिणाम

पुरुष वर्ग

▶▶| 35 किलोग्राम में हरियाणा के प्रणव ने एसएससीबी के रोहित को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

▶▶| 37 किलोग्राम में वंश ने हरियाणा के वंश ने पुदुचेरी के संतोष कुमार को 5-0 से हराया। -43 किलोग्राम में हरियाणा के कुनाल ने महाराष्ट्र के समर्थ को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

महिला वर्ग

▶▶| 35 किलोग्राम में हरियाणा की जिया ने असम की उपासना को 5-0, 40 किलोग्राम में हरियाणा की सोनिया ने तमिलनाडु की एबीआई पी को 5-0 हराकार सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

▶▶| 43 किलोग्राम में हरियाणा की तंवी ने असम की मायाश्री को हराया।

▶▶| 49 किलोग्राम में हरियाणा की शिया ने पंजाब की अनुरीत को हराया।

▶▶| 52 किलोग्राम में हरियाणा की कनिष्का ने तेलंगाना की वेधाक्षरी को 5-0 से दी मात।

▶▶| 64 किलोग्राम में हरियाणा की माही ने मध्यप्रदेश की प्रियांशी को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

हरियाणा मुक्केबाजी का पावरहाउस

हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल सिंधु ने खिलाड़ियों और उनके कोचों को बधाई दी। उन्होंने कहा हमारे अंडर-15 के इन नन्हे मुक्केबाजों ने राष्ट्रीय मंच पर जो खेल दिखाया है, वह बेहद गर्व की बात है। अधिकांश मुकाबलों में 5-0 का एकतरफा स्कोर यह दर्शाता है कि हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और तकनीक का स्तर कितना ऊंचा है। हरियाणा हमेशा से भारतीय मुक्केबाजी का पावरहाउस रहा है, और जूनियर स्तर पर मिल रही यह सफलता यह सुनिश्चित करती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। संघ का हमेशा प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर (ग्रासरूट) पर खिलाड़ियों को सही इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतियोगिताएं मिलें। मुझे पूरा विश्वास है कि सेमीफाइनल और फाइनल में भी हमारे खिलाड़ी इसी जोश के साथ उतरेंगे और स्वर्ण पदकों के साथ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में एक अहम समुद्री पार्टनर और करीबी दोस्त है। मैं इस दौरे को लेकर उत्साहित हूं, जिसका मकसद हमारे पुराने रिश्तों को और मजबूत करना और दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए सहयोग बढ़ाना है

तीन दिवसीय दौरे पर सेशेल्स पहुंचे पीएम मोदी

दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को देंगे बढ़ावा

एजेंसी ▶▶ विक्टोरिया

पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिन के सरकारी दौरे पर सेशेल्स पहुंचे। राजधानी विक्टोरिया में सेशेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पीएम मोदी को औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। पीएम मोदी 29 जून को सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। पीएम सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।

◆ पीएम सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे

सेशेल्स पहुंचने पर पीएम मोदी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया

राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे

पीएम मोदी ने सेशेल्स दौरे पर कहा- सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और 'विजन महासागर' का प्रमुख साझेदार है। जिसका मतलब है 'क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति' और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की साझा प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस साल भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और लोगों के गहरे जुड़ाव पर आधारित हैं। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, समृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे।

हिंद महासागर में करीबी दोस्त

पीएम मोदी ने सेशेल्स पहुंचने पर एक पोस्ट में कहा कि सेशेल्स पहुंच गया हूं। एयरपोर्ट पर डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की मैं बहुत सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में एक अहम समुद्री पार्टनर और करीबी दोस्त है। मैं इस दौरे को लेकर उत्साहित हूं, जिसका मकसद हमारे पुराने रिश्तों को और मजबूत करना और दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए सहयोग बढ़ाना है।

भारतीय समुदाय ने किया स्वागत

सेशेल्स एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एक्स पर कहा कि ये सेशेल्स एयरपोर्ट पर हुए शानदार स्वागत की कुछ झलकियां हैं।

तीव्र गश्ती पोत, नौकाएं और एम्बुलेंस सौंपी

पीएम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सेशेल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी को उपहारस्वरूप तीव्र गश्ती पोत 'लेस्पवार', 10 उपयोगी वाहन, 5 लेजर रेडियल नौकाएँ तथा 6 एम्बुलेंस सौंपी।

कच्छ के नृत्य की प्रस्तुति

पीएम मोदी के स्वागत के लिए कच्छ का नृत्य प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी ने लिखा कि शानदार सांस्कृतिक जुड़ाव! सेशेल्स में एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान कच्छ का नृत्य भी शामिल था।

खबर संक्षेप

तीन माह के बेटे संग बैठक में पहुंची स्वीडन की मंत्री

लक्जमबर्ग। स्वीडन की मंत्री रोमिना पोरमोख्तारी अपने तीन महीने के बेटे एडम को गोद में लेकर यूरोपीय संघ के जलवायु मंत्रियों की बैठक में पहुंचीं। यूरोपीय यूनियन की बैठक में

पहली बार ऐसा देखने को मिला, जब इतना नन्हा मेहमान इसका हिस्सा बना। रोमिना ने कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि मां बनने का मतलब यह नहीं कि किसी महिला का कॅरिअर रुक जाए। 30 साल की पोरमोख्तारी वर्ष 2022 में पद संभालने के समय स्वीडन की सबसे कम उम्र की मंत्री थीं।

गुलमर्ग में ब्लास्ट, एक पोर्टर की मौत, 4 घायल

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में धमाका हुआ है। इसमें एक पोर्टर की मौत हो गई, जबकि चार अन्य के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि

गुलमर्ग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुमली वाली ढोक में आशा पोस्ट के नजदीक एक धमाका हुआ। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान जाबिर अहमद बजाद के रूप में हुई है, जो मोहम्मद रफीक बजाद का बेटा था और बारामूला के चंदूसा में गलीबल का रहने वाला था।

लंदन में एशिया हाउस और दुनिया की प्रमुख कंपनियों से मिले केंद्रीय मंत्री गोयल

भारत-यूके सीईटीए को बताया आर्थिक साझेदारी का आधार, निवेश के कई सुनहरे अवसर खुलेंगे

पीयूष गोयल ने भारत के मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगा

एजेंसी ▶▶ लंदन

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने एशिया हाउस और दुनिया की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उपयोगी गोलमेज बैठक की, जिसमें भारत-यूके आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और भविष्य के अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि भारत के मजबूत विनिर्माण ईकोसिस्टम और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अपार अवसर वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने 'एक्स' पर कहा कि बैठक के दौरान भारत के मजबूत विनिर्माण ईकोसिस्टम और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती देगा।

भारत-ब्रिटेन सीईटीए भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता

पीयूष गोयल यूकेआईबीसी सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए

यूकेआईबीसी के साथ निवेश पर चर्चा

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) के सदस्यों के साथ एक इंटरैक्टिव लंच बैठक भी की। दुनिया की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ भारत-यूके आर्थिक सहयोग, निवेश बढ़ाने और नए कारोबारी अवसरों पर चर्चा की। सहयोग को और गहरा कर भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

देशभर में 1,000 सलाहकार होंगे तैनात

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 1,000 सलाहकार कर्मियों की तैनाती और व्यापार पोर्टल को उन्नत बनाने की घोषणा की, ताकि उद्योग जगत भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) का अधिकतम लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई, 2026 से लागू होने वाला यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार एवं निवेश के नए अवसर खोलेगा। लंदन में आयोजित 10वें वार्षिक ब्रिटेन-भारत सप्ताह के दौरान विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत-ब्रिटेन सीईटीए भारत का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। उन्होंने बताया कि इससे दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 अरब जीबीपी (ग्रेट ब्रिटिश पाउंड) की वृद्धि होने का अनुमान है।

शिक्षा और नवाचार पर जोर

पीयूष गोयल ने लंदन बिजनेस स्कूल में फैकल्टी, छात्रों, पूर्व छात्रों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने एक विशेष फायरसाइड चैट में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्र, पेशेवर और उद्यमी दोनों देशों के बीच सहयोग, नवाचार और लोगों के बीच संबंधों को और सशक्त बना सकते हैं।

ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान

पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्वास, प्रतिभा, समावेशी विकास और स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने उद्योग जगत से ब्रांड इंडिया को वैश्विक स्तर पर मजबूती से प्रस्तुत करने, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को अपनाने और ब्रिटेन के साथ दीर्घकालिक व्यापार एवं निवेश साझेदारियां विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्यम देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

यूएस विदेश मंत्री रुबियो ने की पुष्टि

जल्द आएंगे राष्ट्रपति ट्रंप समझौता अंतिम चरण में

यूएस विदेश मंत्री मार्को रुबियो

एजेंसी ▶▶ वॉशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसकी पुष्टि की है। रुबियो ने बताया कि वे खुद ट्रंप के भारत के ऐतिहासिक दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और इसके लिए वे जल्द भारत आएंगे। रुबियो ने बताया कि ट्रंप प्रशासन अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की तैयारियां कर रहा है। यह भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती नजदीकी को रेखांकित करता है, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। रुबियो ने कहा, मैं साल के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे की तैयारियों के सिलसिले में भारत की यात्रा करूंगा। भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर रुबियो ने कहा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत स्थिति में हैं।

भारत अमेरिका का करीबी सहयोगी

अमेरिकी विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि क्वाड बैठक पर भी जल्द बातचीत हो सकती है। रुबियो ने भारत को अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका का करीबी सहयोगी है और पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, जो मुझे लगता है कि कूटनीति में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। रुबियो ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है, क्योंकि दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं। उन्होंने भारत की ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति का समर्थन करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा क्षेत्र में गहरा सहयोग दोनों देशों की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है।

पीएम मोदी बेहद ऊर्जावान: गोर

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच करीबी कार्य संबंधों की भी तारीफ करते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव बताया। पीएम मोदी के बारे में गोर ने कहा कि वे बेहद ऊर्जावान हैं, हर काम में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं और परिणाम देने पर जोर देते हैं। मुझे उनमें और राष्ट्रपति ट्रंप में कई समानताएं दिखाई देती हैं, क्योंकि दोनों ही खुद नेतृत्व करते हुए काम पूरा कराने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की सोच काफी हद तक एक जैसी है और दोनों परिणाम देना चाहते हैं।

जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप, यूएन से हस्तक्षेप की मांग

एजेंसी ▶▶ जिनेवा

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मुख्यालय के बाहर स्थित 'ब्रोकन चेयर' स्मारक पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 62वें सत्र के दौरान आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बल पीओजेके में लोगों पर दमन कर रहे हैं। यूकेपीएनपी के नेताओं जमील मकसूद और अमजद यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए ताकि वह अपनी सुरक्षा बलों को क्षेत्र से हटाए और रावलाकोट में जारी घेराबंदी खत्म करे। आयोजकों ने नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग और शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के आरोपों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच कराने की मांग भी की।

पीओके पीएम की पाक रक्षा मंत्री को दो टूक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के रावलकोट और मीरपुर के निवासी असली कश्मीरी नहीं हैं। उनके इस बयान की पीओके के पीएम फैसल मुमताज राठौर ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ या किसी और से पुष्टि की जरूरत नहीं है। आप जैसे बूमर्स (पुरानी सोच वाले लोग) और उनकी हरकतें लोगों को करीब लाने के बजाय उनमें फूट डाल रही हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी फिर चेतावनी

डिजिटल सेवा कर लगाने पर यूएस 100% टैरिफ लगाएगा

एजेंसी ▶▶ वॉशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई देश अमेरिका की डिजिटल सेवा से जुड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाता है, तो उनकी सरकार ऐसे देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाएगी। ट्रंप ने साफ किया कि यह टैरिफ उन देशों पर ऊपर से लगेगा, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार समझौता लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की शर्तें लगभग तय कर ली हैं और दोनों देशों के बीच इस पर मुहर लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डिजिटल सेवा कर आमतौर पर देशों की तरफ से इसलिए लागू किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मल्टीनेशनल तकनीकी कंपनियां उस देश के कर ढांचे में अपना योगदान दें।

मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ी साजिश नाकाम

जहरीले पदार्थ को कैप्सूल में भरकर बेचने वाला एक युवक हिरासत में

30000 कैप्सूल तैयार किए, करीब 15000 बरामद

एजेंसी ▶▶ मुंबई

मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने फैयाज प्रेमजी नाम के युवक को हिरासत में लिया है, जिस पर जिंक फॉस्फाइड जैसे जहरीले पदार्थ को कैप्सूल में भरकर लोगों के बीच पेन किलर बताकर बेचने का आरोप है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ी संख्या में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मामले की जांच जारी है और आरोपी के इरादों का पता लगाया जा रहा है।

आरोपी फैयाज

कैप्सूल में भरा था जिंक फॉस्फाइड

मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर 50 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड मंगवाया था। उसने लगभग 30 हजार कैप्सूल में एक-एक ग्राम जिंक फॉस्फाइड भरा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 14,900 कैप्सूल बरामद किए हैं। फैयाज पुणे के विमान नगर का निवासी बताया जा रहा है।

लाल किला ब्लास्ट केस में 3 के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट

एनआईए ने नवंबर, 2025 में दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार बम धमाका मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस ब्लास्ट में 11 लोगों की जान चली गई थी। एनआईए ने अपने केस में तुफैल अहमद भट, मुजफ्फर अहमद उर्फ फराज उर्फ जफर और जमीर अहमद आहंगर को आरोपी बनाया है। ये तीनों जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। साथ ही, इस केस में चार्जशीट किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है।

खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर कई मंदिर

खुफिया विभाग ने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आतंकी उत्तराखंड और दिल्ली के मंदिरों, सरकारी संस्थान, रेलवे स्टेशन और पुलिस को भी टारगेट कर सकते हैं। एक ईमेल के मिलने के बाद से उत्तराखंड पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियां और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर हैं। ईमेल में कई मंदिरों के नाम, कई ऑफिस और पॉलिटिकल नेताओं को टारगेट के बारे में भी लिखा है। दिल्ली पुलिस भी अब इस ईमेल की जांच में जुटी है। अलर्ट मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस, खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सैंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ.हिमांशु द्विवेदी। आरएनआई नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109